लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig 18.10.73

Preservation Unit. 14.5.92 Fumigated On 3.12.83 Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ बैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० बैशाख, १८८४ (शक) — पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० . . . ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ . . . ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ . . . ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . . ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है . . . ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना . . . ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . . . ७५१—५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . . . ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . . ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित . . . ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ७५३

दैनिक संक्षेपिका . . . ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . . ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . ८२२—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३—७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३–७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४—७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४—७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५–७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०–८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१—९१६

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ९१७—२३

अंक १३—बुधवार, २ मई, १९६२/वैशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६—९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६–९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७–९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८—१०००

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१—११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . १०११—५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८—६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण— . .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८६, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१—५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५—५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६—५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११६३—६४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११६४—६६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६—१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ बैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२८२

राष्ट्रपति का संदेश १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित . . . १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प १३३८

दैनिक संक्षेपिका १३४४-५०

अंक १९—सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १३५१

प्रश्नों के **मौखिक** उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९९ . १३७६--८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ १३८९--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . १४८६—२५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३-५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६-७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९-२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०
हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२
सूचना प्राप्त करने के बारे में
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—
चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८
दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
१. फिजो के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ८ मई, १९६२
१८ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले की बजाय मीथेन गैस[1] का प्रयोग

†*१९७. **श्री रामेश्वर टांटियां** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने ५ अश्व शक्ति (हार्स पावर) वाले इंजन को चलाने के लिये गोबर आदि से उपलब्ध मीथेन गैस को काम में लाने का सफल प्रयोग कर दिखाया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का औद्योगिक कार्यों के लिये कोयले के स्थान पर इस गैस के प्रयोग का प्रचार करने का इरादा है : और

(ग) इसके लिये क्या कदम उठाने का इरादा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). ५ हार्स पावर वाले इंजन को चलाने के लिये गोबर की गैस इस्तेमाल करना प्रविधिक रूप से संभव पाया गया है। यह केवल प्रदर्शन के तौर पर किया गया है ; अभी यह प्रयोग इस स्थिति पर नहीं पहुंचा है कि कोयले के स्थान पर इसको औद्योगिक इस्तेमाल अथवा वाणिज्यिक स्तर पर प्रयोगात्मक रूप में रखने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : जब कि कोयले की बहुत कमी है, क्या सरकार मीथेन गैस के अधिक इस्लेमाल के लिये अधिक ध्यान देगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : निःसन्देह सरकार इस पर ध्यान देगी परन्तु निश्चयात्मक रूप से इसकी संभावयता या व्यावहारिता का पता नहीं लगता गया है कि क्या यह कोयले अथवा अन्य किसी ईंधन के स्थान पर ठीक प्रकार इस्तेमाल की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Methane gas.

664 (Ai) LSD—1

†श्री श्यामलाल सर्राफ़ : क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व एक विदेश (योरोपीय देश) से एक विशेषज्ञ गोबर का उत्तम इस्तेमाल विशेषत : इससे गैस बनाने के लिये बुलाया गया था ?

†श्री स० का० पाटिल : यदि वाणिज्यिक रूप से ऐसा कना सम्भव हुआ, तो किया जायेगा। ८० से ९० पौंड गोबर से १००घन फुट गस बनाई जा सकती है जो कि एक परिवार की प्रकाश और ईंधन की औसत आवश्यकता है । फिर इसकी वाणिज्यिक व्यावहारिकता पर विचार किया जाना है ताकि जो भी मशीन हम बनायें वह सभी परिवार खरीद सकें और चलाना सकें । इसलियें इसमें काफी समय लगेगा ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि पिछले छ: या सात वर्षों से विभिन्न खंडों में गोबर संयंत्र चल रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह केवल प्रदर्शन कार्य के लिये इस्तेमाल किया गया है । यदि वाणिज्यिक रूप से इसका विस्तार करना संभव होगा, तो ऐसा किया जायेगा ।

†श्रीमती सावित्री निगम : इसको वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराने में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाईयां है ?

†श्री स० का० पाटिल : पहले तो वाणिज्यक रूप से इस्तेमाल के लिये इसकी क्षमता सिद्ध होनी चाहिये । सरकार के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है ।

†श्री का० रा० गुप्त : इस को वाणिज्यक इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराने में कया मुख्य कठिनाई या रुकावट है ?

†श्री स० का० पाटिल : हमको मूल्यों पर भी ध्यान देना है क्योंकि यदि हम ऐसी मशीन बनायें जो बहुत कीमती हो, जो सामान्य कृषक परिवार न खरीद सके, तो उस का कोई लाभ नहीं । इससे गैस बन सकती है और डाइनमो लगाने से बिजली भी बन सकती है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या किसान इसे खरीद सकता है ।

श्री ज० ब० सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मशीन जो अभी एक्सपेरिमेन्टल स्टेज में है उस के बनाने की क्या कास्ट पड़ रही है ?

श्री स० का० पाटिल : जो पहले गैस प्लान्ट्स बने थे उन की कास्ट शायद ३०० या ३५० रु० थी लेकिन धीरे धीरे उन की बनने की कास्ट बढ़ जा सकती है। अगर इस तरह से वे बनते रहे तो सब्सिडी वगैरह देना पड़ेगा । सब्सिडी चन्द लोगों को, यानी १०० या २०० आदमियों को देना हो तो ठीक है, लेकिन मिलियन्स को सब्सिडी देना सम्भव नहीं है। इस लिये अभी एक्सपेरिमेन्ट हो रहे हैं कि कैसे उसकी कास्ट कम हो जाय और मास प्रोडक्शन हो जिस में कि वह चल सके ।

†कुछ माननीय सदस्य उठे---

†अध्यक्ष महोदय : इस गोबर में से और कुछ नहीं निकाला जा सकता अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग में हिन्दी

†*४९८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये प्रेरणा के तौर पर उन्हें आर्थिक लाभ देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(ग) यह योजना किस हद तक लागू की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) से (ग). डाक तथा तार बोर्ड ने, सिद्धान्त रूप से, यह मंजूर किया है कि प्रशिक्षण कक्षाओं में इस्तेमाल के लिये पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दी जायें और गृह-कार्म मंत्रालय द्वारा आयोजित परिक्षाओं के परिणाम पर नगद पुरस्कार दिये जायें। इस बारे में गृह-कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परारर्श से ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस विभाग में यह कब लागू किया गया है और कर्मचारी किस हद तक हिन्दी सीख सके हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** इस को अब कई प्रशासी कार्यालय कार्यान्वित कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जैसा कि प्रतिरक्षा और अन्य विभागों में है, क्या डाक तथा तार विभाग भी अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये कुछ अध्यापक नियुक्त करेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय की योजना के अधीन इस कार्य के लिये कुछ कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत डाक तार विभाग के भी कुछ कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या संख्या कितनी हैं और क्या उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : प्रशिक्षण तो दिया गया है, कितने लोगों अभी तक मिल चुका है यह आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जिनको हिन्दी सिखायी जाती है उनको हिन्दी सीख लेने से लाभ तो होता ही है ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या प्रशासी अधिकारियों के लिये, पदोन्नति किये जाने से पूर्व, कोई हिन्दी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** हमारे नियम अन्य मंत्रालयों में अखिल भारत सेवाओं के तरीके का अनुसरण करते हैं। जब उन्हें ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाता है, तो उन्हें कुछ परीक्षा पास करनी पड़ती है तकि उन्हें भाषा का कार्यकारी ज्ञान हो जाये।

श्री भक्त दर्शन : यह जो नई योजना चालू की जा रही है इसमें कितना समय और लगेगा और क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जाएगी ?

श्री जगजीवन राम : हम लोगों ने कुछ निश्चिय किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज में ३१ मार्च सन् १९६४ तक स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट, ३१ दिसम्बर सन् १९६४ तक टाइपिस्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

और आपरेटिव स्टाफ जो पोस्ट और टेलीग्राफ आफिसेज में है वह ३१ मार्च सन् १९६६ तक हिन्दी की योग्यता प्राप्त कर लें।

सवारी डिब्बों का निर्यात

+

†*४९९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवारी डिब्बों और माल-डिब्बों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू डिब्बों का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) हमारे देश में इस समय बन रहे डिब्बों में से कितने डिब्बे हमारी आवश्यकता को पूरा करने के बाद बच रहते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सवारी डिब्बों या माल-डिब्बों के लिये इस समय कोई निर्यात व्यादेश नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) मिले जुले डिब्बों की देशीय उत्पादन-क्षमता का हमारी अपनी आवश्यकताओं के लिये पूरा इस्तेमाल हो रहा है। यदि कोई निर्यात व्यादेश मिला तो निर्यात बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसकी उत्पादक-क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सवारी डिब्बों के निर्माण में सरकार ने आत्म निर्भरता प्राप्त कर कर ली है, यदि नहीं तो वे इनका निर्यात कैसे कर पायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु तृतीय योजना में सवारी-डिब्बों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता ८९२२ है। प्रत्येक सवारी डिब्बे पर लगभग १ लाख रुपया लागत आती है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : अभी अभी उपमंत्री महोदय ने बताया कि यदि निर्यात के लिये कोई व्यादेश मिला तो उसे पूरा किया जायेगा। क्या उनका इरादा सवारी डिब्बे निर्यात करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब फालतू नहीं हैं, तो निर्यात कैसे किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पुराने सवारी डिब्बों के स्थान पर देशीय डिब्बे कब लगाये जायेंगे और इस समय वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पुराने डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे लगाना तो चलता रहता है और हम यातायात की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए प्रतिशतता कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य को पता है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन, जो ३५० डिब्बे प्रति वर्ष रखा गया था, को बढ़ा कर लगभग ७०० किया जा रहा है और इसी प्रकार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और अन्य कारखानों में भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गाड़ियां हिन्दुस्तान में बनती हैं उनकी कीमत में और जो इस प्रकार की गाड़ियां स्विटजरलैंड में बनती हैं, उनकी कीमत में क्या फर्क है ताकि फारिन मारकेट में हम कम्पीट कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने तो काफी अरसे से कोई इस किस्म की कोचेज बाहर स्विटजरलैंड वगैरह से नहीं खरीदी हैं, लेकिन जब हमने कुछ खरीदी थीं उस वक्त की उनकी कीमत में और अब जो हमारी लागत कीमत है उसमें बहुत फर्क है, हमारी बहुत सस्ती हैं ।

†**श्री निम्बियार :** क्या यह सच नहीं है कि सरकार सवारी-डिब्बों की कमी के कारण अधिक गाड़ियां लगाने से इन्कार करती है और यदि हां, तो फालतू डिब्बे निर्यात करने का प्रश्न कैसे उठता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंनें बताया है कि डिब्बे फालतू नहीं हैं ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** इन सवारी डिब्बों के पुर्जे किस हद तक भारत में बनाये जाते हैं और क्या कुछ प्रतिशतता का आयात भी किया जाता है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** कुछ विशेष इस्पात को छोड़ कर केवल ४ या ५ प्रतिशत का आयात किया जाता है । जब इस्पात संयंत्रों में क्षमता बढ़ जायेगी तो हम उसका भी आयात नहीं करेंगे ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इन्टीग्रल कोच फक्टरी में उत्पादन को बढ़ा कर १२०० से अधिक नहीं किया जा सकता है ? क्योंकि पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में १२०० बताया था, न कि ६०० ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैंने बताया कि इसको ३५० से बढ़ाकर ७०० किया जा रहा है ।

केरल में तपेदिक के मरीज

+

†*५००. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वारियर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य विधान-सभा में २ मार्च, १९६२ को दिये गये इस वक्तव्य की ओर गया है कि राज्य में तपेदिक के लगभग २ लाख मरीज हैं जिनमें से केवल आध मरीजों की चिकित्सा हो पाती है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस दुखद स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां तो भारत सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) सरकार को राज्य विधान-सभा में दिये गये ऐसे किसी वक्तव्य का पता नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या सरकार को पता है कि इनमें से केवल कुछ सौ व्यक्तियों की ही सेनेटोरियम में चिकित्सा हो पाती है और यदि हां, तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में और सेनटोरियम खोलने की कोई योजना है ?

†**डा० सुशीला नायर :** केरल में तपैदिक के रोगियों के लिये ६९५ बिस्तर हैं । इसके अतिरिक्त वहां पर ९ क्षेय रोग रुग्णालय हैं जो तपेदिक के बाकी मरीजों का बिना दाखले के इलाज करते हैं। केरल राज्य में पांच बी०सी०जी० दल भी हैं जिसन कुछ लाख व्यक्तियों को टीके लगाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन् नायर : इस बात को देखते हुए कि इस क्षेत्र में तपेदिक के रोगी इतने अधिक हैं, मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना में और अस्पताल या सेनटोरियम चलाने की कोई योजना है। मुझे इसका उत्तर नहीं मिला।

†डा० सुशीला नायर : भारत में तपेदिक जैसी बड़ी समस्या के लिये घर पर इलाज का विस्तार करने की योजनायें हैं।

†श्री प० कुन्हन : क्या केरल राज्य में इस बारे में अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†डा० सुशीला नायर : सामान्य रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया परन्तु कुछ समय पूर्व मान सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण के आधार पर यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में कार्यशील और संभवतः कार्यशील तपेदिक की दर १·५८ प्रति हजार व्यक्ति है।

दिल्ली मास्टर प्लान

+

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
*५०१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसमें अभी भी कुछ कठिनाइयां हैं अथवा उन्हें पूरा कर लिया गया है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने मास्टर प्लान को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि भूमि के क्रय-विक्रय में कोई भ्रष्टाचार न हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं। यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) किसी गंभीर कठिनाई की संभावना नहीं है और यदि कोई आ भी जाय तो उसका समाधान कर दिया जायेगा।

(ग) दिल्ली के मास्टर प्लान पर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारों की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्लान का वैधिक कार्य का भाग केवल संघ-क्षेत्र दिल्ली से ही संबंधित है और दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत इसे तैयार किया गया है जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिल्ली में भूमि की अवाप्ति और विकास की एक योजना के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन भूमि अवाप्ति अधिनियम के अधीन दिल्ली में भूमि प्राप्त कर रहा है और उसे उपयोग के लिये उपलब्ध करता है। इन कार्यों पर आवश्यक पर्यवेक्षण और सतर्कता बरती जायेगी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि दिल्ली के मास्टर प्लान के संबंध में उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों की कोई सम्मिलित बैठक हुई थी ? अगर हां, तो वह बैठक किस निश्चय पर पहुंची थी ?

डा० सुशीला नायर : प्लान बनते समय अधिकारी लोग दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश और पंजाब के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार-विनिमय करते रहे हैं और जो कुछ भी तय किया गया है, पारस्परिक सम्मति से किया गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि पीछे मास्टर प्लान के संबंध में यह घोषित किया गया था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का कुछ भाग मास्टर प्लान के अन्तर्गत आता है, इसलिए जब मास्टर प्लान का विकास किया जायगा, तो वह इन दोनों प्रदेशों की सरकारों की देख-रेख में किया जायेगा, अथवा वह दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत किया जायगा।

डा० सुशीला नायर : मास्टर प्लान बनाने वालों ने कुछ सुझाव दिये हैं कि दिल्ली के इर्द-गिर्द जो इलाके पड़ते हैं, जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, लोनी, फ़रीदाबाद, बल्लबगढ़, इत्यादि, इनका भी विकास अगर ठीक ढंग से किया जाय तो दिल्ली का विकास आगे चल कर ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा और दिल्ली के किनारों पर हैपहैजर्ड ग्रोथ रुक जायगी। इस काम के लिए उन्होंने अपने सुझाव अपने इस बड़े प्लान में दिये हैं। उसके डीटेल्ड प्लान्ज राज्य सरकारें स्वयं आगे वर्क आउट करेंगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इस मामले पर ७ वर्ष से, १९५४-५५ से, जब कि मंत्राणी महोदया दिल्ली राज्य सरकार में किसी पद पर थीं, विचार हो रहा है, इस मामले को अन्तिम रूप देने में इस असामान्य बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**डा० सुशीला नायर :** केन्द्रीय सरकार ने, नवम्बर, १९५५ में, दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार की स्थापना की थी। इस संगठन की सहायता के लिये दिसम्बर, १९५५ में नगर आयोजन संगठन स्थापित किया गया था। उसके बाद, उन्होंने सितम्बर, १९५६ में एक अन्तरिम सामान्य योजना बनाई जिसमें विकास की सामान्य रूप रेखा थी। ३० दिसम्बर, १९५७ को संसद् के एक अधिनियम के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकार बनाया गया। इन लोगों ने एक वृहत् योजना बनाई और ८ जुलाई, १९६० को जनता की राय जानने के लिये रखी। लगभग ६०० आपत्तियां प्राप्त हुई और उन पर एक विशेष बोर्ड द्वारा विचार किया गया और १७ मार्च, १९६१ को योजना सरकार को भेज दी गई। उसके बाद, इसको विचारों के लिये विभिन्न मंत्रालयों में भेजा गया। २० सितम्बर, १९६१ की बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकार ने पुनरीक्षित भू-प्रयोग नक्शा पास कर लिया था। पुनरीक्षित योजना को अन्तिम रूप दे कर ३० नवम्बर, १९६१ को भेजा गया। फिर . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** योजना बनाने में विलम्ब हुआ या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर देने में इतना बिलम्ब हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य पूरा उत्तर चाहते थे और मैंने वह देने का प्रयत्न किया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। कारण क्या हैं ? वह बिलम्ब का कारण जानना चाहते थे ।

†**डा० सुशीला नायर** : अन्त में, विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त विचारों पर कल सचिवों की संयुक्त बैठक में विचार किया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : एक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर काफी समय लग गया है। श्री दी० चं० शर्मा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्राणी महोदया के वक्तव्य के अनुसार, जो प्राधिकार बनाया गया था, उसने कितने एकड़ भमि अर्जित की है और उसमें से कितनी भमि अन्य व्यक्तियों को दे दी गई है और क्या यह न लाभ-न हानि के आधार पर दी गई है या सरकार उस पर कोई लाभ ले रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस मामले में ब्योरे में पड़ रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ब्योरे के बिना योजना कैसे क्रियाकारी हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी विषय पर नियमित चर्चा और प्रश्न के उत्तर में कुछ अन्तर तो होना ही चाहिये। प्रश्न का उत्तर कुछ ही बातों तक जो इससे सीधे सम्बन्धित हों, सीमित होना चाहिये। क्या हम इन ब्योरों की बात कर सकते हैं कि कितनी भूमि ली गई है, किस मूल्य पर ली गई है, जिन्होंने यह भूमि ली है, उनसे क्या मूल्य लिया गया है, आदि।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कुछ भूमि ली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी भूमि ली गई है और कितनी बेची गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कितनी भूमि ली गई है ? मैं केवल इस एक प्रश्न के उत्तर दिये जाने की अनुमति देता हूं।

†**डा० सुशीला नायर** : कई अध्यादेश जारी हुए हैं। एक में ३,००० एकड़, दूसरे में ३४,०७० एकड़, फिर दूसरे में १,८०८ एकड़ और फिर १६,००० एकड़।

आस्ट्रेलिया के साथ किया गया गेहूं का सौदा

†*५०२. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आस्ट्रेलिया के साथ गे का कोई सौदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). ६ अप्रैल, १९६२ को नई दिल्ली में आस्ट्रेलियन व्हीट कमेटी, लन्दन के मैनेजर के साथ ३१ जुलाई, १९६२ तक भारत को २.७ लाख टन आस्ट्रेलियाई गेहूं के संभरण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** आस्ट्रेलियाई गेहूं का क्या मूल्य है और भारतीय मंडी में क्या मूल्य चल रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे पास मूल्य हैं परन्तु आस्ट्रेलियन व्हीट कमेटी को दिये गये आश्वासन के अनुसार हमने कुछ समय तक वह जानकारी देना स्थगित कर दिया है । मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन दिलाता हूं कि हम यह उससे अधिक लाभप्रद शर्तों पर खरीद रहे हैं, जिस पर हम पहले आयात कर रहे थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उस गेहूं के मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** जब हम पी० एल०-४८० कार्यक्रम के अधीन गेहूं का आयात कर रहे हैं, तो इस करार के अधीन भी गेहूं का आयात करना किस कारण से आवश्यक समझा गया ?

†**श्री अ० म० थामस :** पी० एल०-४८० कार्यक्रम के अधीन हमें प्रति वर्ष वाणिज्यिक विपणन के रूप में ४००,००० टन आयात करना पड़ता है । यह खरीद उसी रूप में की गई है ।

श्री अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक विदेशों से गेहूं हिन्दुस्तान में आता रहेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं बतला चुका हूं कि ३१ जुलाई, १९६२ से पूर्व इस मात्रा का आयात कर लिया जायेगा ।

†**श्री त्यागी :** इस करार के पश्चात्, प्रति वर्ष गेहूं के आयात पर कुल कितना व्यय करना पड़ेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** गेहूं के यहां पहुंचने की लागत लगभग २४ पौंड प्रति टन है । यह हिसाब का मामला है ।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी ।

†**श्री अ० म० थामस :** हम वाणिज्यिक आयात के रूप में आस्ट्रेलिया से लगभग ३ लाख टन और अमरीका से १ लाख टन की खरीद कर चुके हैं । एक टन गेहूं की लागत—मैं यहां पर उतारे हुए गेहूं के मूल्य का जिक्र कर रहा हूं —लगभग २४ पौंड आती है ।

†**श्री त्यागी :** मैं सभी देशों से प्रति वर्ष आयातित गेहूं की कुल लागत जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य से उसका हिसाब लगाने को कहा है —मात्रा की दर से गुणा करके आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** वह केवल एक ही देश से आयात नहीं करते। मैं सभी देशों से आयातित गेहूं की कुल लागत जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय यह मंत्री जी के पास नहीं है। यदि उनके पास होती तो वह उत्तर दे देते।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** चार वर्षों में, जिनमें से दो वर्ष बीत चुके हैं कुल १६० लाख टन का आयात करना है। १० लाख टन की लागत लगभग ४० करोड़ रुपये बठती है। हमें ४० लाख टन में से लगभग ४ लाख टन प्रतिवर्ष वाणिज्यिक आयात के रूप में आयात करना पड़ता है। अतः १० प्रतिशत वाणिज्यिक विपणन के रूप में है। इस बारे में भी ऐसी व्यवस्था है कि यदि हम चाहें तो कम भी ले सकते हैं क्योंकि उस मामले में विदेशी मुद्रा की बचत होती है। हर वर्ष इसका पुनर्विलोकन किया जाता है और बाज दफा हम कम भी लेते हैं।

†**श्री उमानाथ :** जहां तक आस्ट्रेलिया से आयात का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था क्यों है और क्या यह अमरीका से अपर्याप्त आयात के कारण है या अन्य किसी कारण ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी, नहीं। यह व्यवस्था है और उसके कई स्पष्ट कारण भी हैं। हम कनाडा और आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदते थे और फिर वे देश कहेंगे कि क्योंकि हमें अमरीका से सस्ता गेहूं मिलता है इसलिये हमने उनसे खरीदना बन्द कर दिया है। अतः यह पी० एल०-४८० कार्यक्रम का एक भाग है कि वाणिज्यिक आयात किया जा सकेगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या हम आन्तरिक बाजार में यह गेहूं उसी दर पर बेच रहे हैं जिस पर, हम आस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** हम यह १४ रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचते हैं और हमारी लागत भी लगभग इतनी ही है।

दक्षिण के राज्यों में सूखा

†*१०३. **श्री मं० रं० कृष्ण:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण के उन राज्यों को, जो सूखे से पीड़ित रहते हैं, सहायता देने के उपायों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश को सहायता के तौर पर जो राशि मंजूर की गई थी क्या वह इस राज्य को दे दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) चालू वर्ष में अब तक दक्षिण के राज्यों से किसी सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं मिली है। वर्ष १९६०–६१ में जब कि मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा था, राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि छोटे सिंचाई कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये क्योंकि उससे स्थायी आस्तियां बनेंगी और देश में श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

(ख) सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं पर व्यय करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष १९६०–६१ में १·४० करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन

---

†मूल अंग्रेजी में।

किया गया। वर्ष १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश सरकार से अतिरिक्त आवंटन के लिये ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है और न ही चालू वर्ष में अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना मिली है।

दक्षिण रेलवे पर विभागीय उपहार-गृह

†*५०४. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर चलाये जा रहे उपाहार-गृह बन्द किये जा रहे हैं और उनका प्रबन्ध ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]।**

†**श्री नम्बियार :** क्या रेलवे के उपाहार-गृहों में यात्रियों को दिये जाने वाले चावल की मात्रा अपर्याप्त है और क्या उनको अतिरिक्त भुगतान पर और चावल लेना पड़ता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री नम्बियार :** क्योंकि इस कारण उपाहार-गृह बन्द कर दिये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह यह है कि क्या दक्षिण रेलवे पर विभागीय रूप से चलाये जा रहे उपाहार-गृहों को बन्द करके ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है। उसमें चावल, दाल और कई अन्य वस्तुएं होंगी। अब वह चावल की अपर्याप्तता का प्रश्न उठा रहे हैं। उनका प्रश्न केवल यह है कि इनको बन्द करके ठेकेदारों को क्यों सौंपा जा रहा है।

†**श्री नम्बियार :** कारण पूछा गया है और उत्तर यह है कि हानि के कारण इनको बन्द किया गया है। हानि अपर्याप्त मात्रा में चावल के सम्भरण के कारण है क्योंकि इस कारण यात्री लोग रेलवे के उपाहार-गृह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अतः मैंने यह प्रश्न पूछा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** चावल का अपर्याप्त संभरण वहां चावल की कमी के कारण हो सकता है।

†**श्री नम्बियार :** वहां राशन व्यवस्था लागू की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने विवरण में बताया है कि वे बड़े स्टेशनों पर ध्यान दे रहे हैं। अतः उन्होंने कुछ ऐसे उपाहार-गृहों को बन्द कर दिया है जो हानि पर चल रहे थे।

†**श्री नम्बियार :** हानि इस कारण है कि चावल का संभरण सीमित था। अतः यात्री लोग बाहर जा कर खाना खाते हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** विभागीय योजन व्यवस्था के साथ साथ ठेकेदार द्वारा भोजन-व्यवस्था भी है। परन्तु सहायक होने के बजाय वह स्पर्धा करते हैं। उसको दूर करने के लिये हमने बड़े स्टेशनों पर विभागीय व्यवस्था करने का फैसला किया है। विभागीय भोजन-

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था लागू करने का मतलब उच्च स्तर से है ताकि गैर-सरकारी ठेकेदार भी वह स्तर अपना सकें। इसीलिये प्रमुख स्टेशनों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि विभागीय रूप से चलाये जा रहे इन उपाहार-गृहों में चावल पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता और इसलिये ग्राहक बाहर जाते हैं। इसलिये विभागीय रूप से चलाये जा रहे उपहार-ग्रहों को हानि होती है। क्या ऐसा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी नहीं। यह सच नहीं है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह दक्षिण रेलवे में केटरिंग सुपरिन्टेंडेंट की अकार्य-कुशलता के कारण भी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ऐसा नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया है कि 'उन संस्थानों को जो प्रमुख और अत्यावश्यक नहीं थे और जिनका प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा कुशलता से किया जा सकता था, बन्द करने' का निर्णय किया गया है। क्या इसमें सरकार को कोई सुझाव निहित है कि विभागीय भोजन-व्यवस्था असफल रही है अथवा इतनी सफल नहीं रही है, जितनी आशा थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह असफल नहीं र ी है। दूसरी ओर, हम दक्षिण रेलवे पर थोड़ा सा लाभ कर रहे हैं। यह इस कारण नहीं है। यह इसलिये है कि हम ठेकेदार द्वारा भोजन-व्यवस्था और विभागीय भोजन-व्यवस्था में अनावश्यक स्पर्धा रोकना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप हानि होती है।

†**अध्यक्ष महोदय:** उसमें यह निहित था कि विभाग ने उनको बन्द कर दिया है जिन्हें ठेकेदार अच्छी तरह चला सकते हैं। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः उन मामलों में ठेकेदार अच्छे ढंग से चला रहे थे।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ठेकेदार अधिक सस्ता चला सकते हैं क्योंकि उन पर कुछ मजूरी विनियम लागू नहीं होते, जब कि हमें अधिक मजूरी देनी पड़ती है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस विभागीय भोजन-व्यवस्था को एक तरफ फैलाने और दूसरी तरफ घटाने का अनुभव इतना उत्साहजनक है कि इसको अन्य रेलवें पर भी लागू किया जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह आवश्यक नहीं है। जहां कहीं हानि होती है, हम हानि को कम करना और प्रयुख स्टेशनों पर ध्यान देना चाहते हैं।

†**श्री कोया :** क्या सरकार का इरादा सभी विभागीय कैन्टीनों के ठेकेदारों को दे देने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जी, नहीं। यह इरादा नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मंत्री महोदय ने बताया है कि वे सदैव ऐसा नहीं करेंगे परन्तु जहां कहीं हानि होती है, वहां ऐसा ही किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे रेलवे

---

†मल अंग्रेजी में

मंत्रालय यह पता नहीं लगा सकी है कि हानि क्यों होती है और कारणों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमें कारणों का पता है। हम केवल अधिक मजूरी ही नहीं दे रहे हैं परन्तु हम किस्म पर भी अधिक ध्यान दे रहे हैं जो कि वगैर-सरकारी ठेकेदार नहीं कर सकते ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या रेलवे द्वारा चलाई जा रही भोजन-कारें हानि पर नहीं चल रही हैं; यदि हां, तो क्या उनको भी बन्द कर दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उनमें से कुछ हानि पर चल रही हैं परन्तु यात्रियों की सुविधा के लिये उन्हें जारी रखा जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** ये जो उपाहार-गृह ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं क्या इनमें से किन्हीं को सहकारी समिति को भी दिया जायेगा ? क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यदि सहकारी समितियां आगे आती हैं, तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या यह सही नहीं है कि डाइनिंग कार में जो थाली परोसते हैं तो अगर दस थाली परोसते हैं तो दो की ही रसीद देते हैं और दो का ही हिसाब रखते हैं इसलिये लास होता है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सही नहीं है। जितनी थाली देते हैं उतने का ही हिसाब रखते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : हमने देखा है कि हिसाब गलत रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल हो जाए तो दूसरे के लिये इजाजत की जरूरत है ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : वह हिसाब गलत रखते हैं, रसीद कम थालियों की देते हैं इसलिये लास होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब यह तीसरा सवाल कर दिया ।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या रेलवे द्वारा चलाये जा रहे किसी उपाहार-गृह में लाभ भी हो रहा है, यदि हाँ, तो कितने उपाहर-गृहों में लाभ हो रहा है ?

†**श्री सं० वें० रामस्वामी** : लाभ कमाने का इरादा नहीं है परन्तु न-लाभ न-हानि के आधार पर चलाने का है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री डी० ना० मुकर्जी। श्री नवल प्रभाकर।

†**श्री नवल प्रभाकर :** जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह "जी, हां" न कह कर संख्या पुकारें।

†**श्री नवल प्रभाकर :** ५०६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पंचायतों के चुनाव

***५०६. श्री नवल प्रभाकर : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंचायतों के चुनाव होंगे ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सब प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) दिल्ली में मौजूदा पंचायतों की अवधि अक्तूबर, १९६२ को समाप्त होनी है। नये चुनाव समय पर करने का विचार है ।

(ख) चुनाव करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नवल प्रभाकर : पिछले जनरल एलेक्शंस में बहुत से लोगों के वोट नहीं बने थे और इस कारण वह वोट देने से रह गये थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब उनको वोटर्स बनाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं ताकि सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकें ।

†**श्री नवल प्रभाकर :** पंचायतों के जो चुनाव हुए थे उनमें पंचायतों के मैम्बरों को अंग्रेजी में नामिनेशन फार्म्स दिये गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले चुनावों में क्या कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि उनको हिन्दी या उर्दू में यह फार्म्स दिये जायें ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी हां इस पर विचार किया गया है और उनको हिन्दी में भी दिये जायेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कितनी पंचायतें ऐसी हैं जोकि अपने चुनाव कराने के लिए फौज की मदद चाहती हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : फौज की मदद की जरुरत नहीं है ।

श्री भगवत झा आजाद : पुलिस की मदद कहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

रिहन्द बिजली परियोजना की फालतू बिजली

+

†*५०७. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहन्द बिजली परियोजना की बिजली बड़ी मात्रा में फालतू है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस फालतू बिजली का उत्तर प्रदेश के बाहर उपयोग करने की कोई योजना है ; और

(ग) क्या इस बारे में किसी अन्य राज्य की मांग पर विचार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) रिहन्द बिजली घर में कुल २५० मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। फिर भी १०० प्रतिशत लोड-फैक्टर पर केवल १०५ मेगावाट बिजली ही लगातार पैदा की जा सकती है । वहां पूरी पूरी बिजली पहले से ही पैदा की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जब सभी ग्राहक अपनी अपनी बिजली लेना शुरु करेंगे तब उसके बाद शीघ्र ही रिहन्द की पूरी पूरी बिजली काम में लायी जायेंगी । ५० मेगावाट की एक मशीन १ फरवरी, १९६२ से वाणिज्यिक बिजली (कमर्शियल लोड) ले रही है । दो मशीनें चालू होने ही वाली हैं और दूसरी और दो मशीनें जल्द ही तैयार हो जायेंगी । कुछ थोक ग्राहक जैसे हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन और रेलवे, अभी बिजली लेने की स्थिति में नहीं है और चूंकि अभी कुछ ट्रांसमिशन लाइनें और उप-स्टेशन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए अभी परियोजना से कभी सिर्फ १२ मेगावाट बिजली ही ली जा रही है ;

संभवतः जून, १९६२ तक मुख्य ग्राहक अपने कोट की पूरी पूरी बिजली ले लेंगे । तब तक की अल्पावधि में रिहन्द में कुछ बिजली फालतू रहेगी ।

(ख) जी हां, रिहन्द की कुल बिजली की १० प्रतिशत बिजली मध्य प्रदेश के लिए रखी गयी है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बिजली के बंटवारे के सम्बन्ध में अभी ब्यौरे निश्चित करने हैं ।

(ग) रिहन्द परियोजना से कुछ बिजली बिहार और दामोदर घाटी निगम को अस्थायी तौर पर बिजली देने के प्रस्ताव की छानबीन की जा रही है ।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि ५ यूनिटों में से सिर्फ एक ही यूनिट अभी तक चालू किया गया है और दूसरे यूनिट इसलिए चालू नहीं किये गये हैं कि ग्राहक बिजली लेने के लिए तैयार नहीं है । क्या इन चार यूनिटों को बेकार रखने की बजाय इसकी कुछ बिजली दामोदर घाटी निगम को दी जायेगी जिससे बंगाल और बिहार में उद्योगों के लिए बिजली की कमी पूरी की जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद विवरण के आखिर में एक वाक्य है कि उस पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव किस दिशा में है ?

†**श्री अलगेशन** : उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया था कि रिहन्द परियोजना से जिन ग्राहकों को बिजली दी जाने वाली है जब तक वे उसे लेने के लिए तैयार न हों तब तक अस्थायी तौर पर दामोदर घाटी निगम क्षेत्र को बिजली सप्लाई करने के प्रश्न पर वह विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह मालूम होता है कि जून, १९६२ तक मुख्य ग्राहक अपने कोटे की पूरी पूरी बिजली ले लेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस थोड़ी सी अवधि में रिहन्द से कितनी बिजली फालतू होगी और क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी खपत होने की संभावना है या यह मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य को दी जायेगी ?

†श्री अलगेशन : यह फालतू बिजली उपलब्ध होने का सवाल नहीं है, वह तो अतिरिक्त क्षमता है । इस परियोजना से कितनी बिजली पैदा की जायेगी यह पहले ही ग्राहकों को नियत की जा चुकी है । फिर भी अभी केवल अस्थायी तौर पर दूसरे ग्राहकों की मदद की जा रही है ।

†श्री दाजी: दूसरे राज्यों को रिहन्द की बिजली दी जाने से पहले क्या मध्य प्रदेश से किये गये वायदे पूरे किये जायेंगे ?

†श्री अलगेशन : जी हां । .

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या रिहन्द बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटने के प्रश्न पर केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् अभी आजकल विचार कर रही है ? क्या सरकार उस परिषद् की सिफारिश की प्रतिक्षा करेगी या इस सम्बन्ध में उसके निश्चय से पहले ही वह अपना निश्चय करने जा रही है ?

†श्री अलगेशन : यह परियोजना शुरु होने से पहले भी, क्योंकि तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र डब जाने वाले थे, इसलिए यह समझौता हुआ था कि १० प्रतिशत बिजली तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र को दी जाये । वही बात अब भी है । दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री आपस में बातचीत करके तब कोई फैसला करेंगे ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दामोदर घाटी निगम ग्रिड के लिए कुल कितनी बिजली उपलब्ध होगी ?

†श्री अलगेशन : मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता । यदि वह दी भी जायेगी, तो पूर्णतः अस्थायी आधार पर । सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा गया है और वह उसकी छानबीन कर रही है ।

†श्री कृ० चं० पन्त : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया है कि उसके पास कुछ फालतू बिजली है जिसका उपयोग वह राज्य में नहीं कर सकती ?

†श्री अलगेशन : जी नहीं ।

इम्फाल-कचार सड़क

†*५०८. श्री रिशांग किशिंग : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल-कचार सड़क के लिये कितनी राशि नियत की गयी है ;

(ख) सड़क के पूरा होने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ; और

(ग) नियर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १३५ लाख रुपये ।

(ख) तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक ।

(ग) यह सड़क बनाने के लिए अभी तक ३० अनुमान मंजूर किये गये हैं और साथ ही साथ इम्फाल से नंगबा और नंगबा से जीरीघाट तक के दो अनुभागों में यह सड़क बनाने का काम शुरु किया जा चुका है । प्रत्येक अनुभाग में दोनों सिरों पर काम जारी है और निर्माण के कई दौरों में काम आगे बढ़ रहा है।

†श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि उस क्षेत्र में समाजविरोधी लोगों की कार्रवाइयों के कारण, इस सड़क के काम में काफी नुक्सान पहुंचा है और यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री राज बहादुर : उस क्षेत्र में जमीन की तथा परिस्थितियों की कठिनाइयां हैं। सड़क बनाने के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाइयां हैं। आशा है कि अब स्थिति सुधर जायेगी।

†श्री रिशांग किशिंग : सवाल यह है कि समाज विरोधी तत्वों की कठिनाइयों से सड़क के काम पर गहरा असर पड़ा है, वह जमीन का सवाल है ?

†श्री राजबहादुर : मैं ने जवाब दिया है कि कुछ कठिनाइयां हैं, तो लेकिन वह अब नहीं रहेंगी ।

†श्री हेम बरुआ : क्या समाज वरिोधी तत्वों ने भारी मोटरगाड़ियों और सशस्त्र मोटर-गाड़ियों के कारण इस सड़क पर बहुत बोझ लाद रखा है और क्या इसी कारण सड़क का काम आगे नहीं बढ़ रहा है ?

†श्री राज बहादुर : इस मंत्रालय में हमारा सम्बन्ध केवल सड़कों के निर्माण से है और जहां तक संभव है हम निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अनुमानों पर मंजूरी दे दी है । दूसरे कामकाज के बाबत, सम्बन्धित मंत्रालय से प्रश्न पूछे जायें।

†श्री दाजी : इस सड़क के सामरिक महत्व को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि आपके सामने कौनसी कठिनाइयां हैं और उन्हें रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ताकि सड़क जल्दी बन कर तैयार हो जाय ?

†श्री राज बहादुर : इस सड़क के सम्बन्ध में, जीरघाट तक काफी अच्छी हालत है और उस पर मोटरें आ जा सकती हैं। जीरघाट से इम्फाल पर जीपगाड़ियां आ जा सकती हैं लेकिन ऊंचानीचा बहुत है, मोड़ भी काफी हैं और काफी ढलुबे उतारचढ़ाव हैं, इसलिए नयी रेखा चुनी गयी है और अब उसके बारे में निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है ।

†श्रीमती रेणुका राय : इस नयी रेखांकन का कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक मेरा ख्याल है, ११० $^{1}/_{4}$ मील तक की सड़क के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और वह कई दौरों में बनायी जायगी । सड़क एकाएक पूरी नहीं की जा सकती है । हमने एक एक अनुभाग को किया है और कुल १५० मील में अनुभागों में निर्माण कार्य जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपर सिलेरू परियोजना का स्थान

+

†*५०९. { श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपर सिलेरू परियोजना (विद्युत्) का स्थान निश्चित करने के बारे में श्री सी० एम० त्रिवेदी का पंचाट मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब मिला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अभी इस मामले की छानबीन हो रही है।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या श्री त्रिवेदी की रिपोर्ट न मिलने पर भी यह काम शुरू किया जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : दोनों मुख्य मंत्रियों ने श्री त्रिवेदी से राय पूछी है और हम उनके सुझावों की प्रतीक्षा में हैं।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : उनकी रिपोर्ट मिलने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : दोनों सरकारों ने या संबंधित चीफ इंजीनियरों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और केन्द्रीय पानी बिजली आयोग उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं और सारी बातें श्री त्रिवेदी के सामने रख दी जायेंगी जो बाद में अपना अंतिम निर्णय देंगे।

गन्ने की खेती का क्षेत्र फल

†*५१०. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कुल कितने एकड़ भूमि में गन्ने की काश्त की गई ; और

(ख) क्या वर्ष १९६०-६१ की अपेक्षा वर्ष १९६१-६२ में गन्ने की उपज में प्रति एकड़ कुछ वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९६०-६१ में कुल ५,७३४ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की फसल बोयी गयी। १९६१–६२ के लिये तत्संबधी आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) यह अभी मालूम नहीं हुआ है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या उत्तरी भारत में पैदावार को देश के दक्षिणी भागों मे होने वाली पैदावार के स्तर तक लाने के लिये कोई कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह कार्यवाही तो स्वतः किसानों को ही करनी पड़ेगी। जहां तक हमारी मदद का सम्बन्ध है, वह उन्हें दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री काशीनाथ पांडे: किसानों को फी, एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार क्या कर रही है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह एक लंबी कहानी है और वह प्रश्नकाल में नहीं समझायी जा सकती । मैं समझता हूं कि बजट पर चर्चा के समय हम उसे पूरी तरह बतायेंगे ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि १९६०–६१ में कितनी जमीन पर गन्ना बोया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि यह भूमि बढ़ती जा रही है या उतनी ही है और अगर बढ़ती जा रही है तो क्या यह गहूं और चावल की भूमि है या नई भूमि तोड़ी जा रही है ?

श्री स० का० पाटिल : पिछले बरस में वह बढ़ गई है । इसकी चर्चा तो सदन में हो गई है एक बार । मैं मानता हूं करीब एक मिलियन यानी दस लाख जितनी बढ़ गई है । लेकिन यह बढ़नी नहीं चाहिये । अगर बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि गेहूं और दूसरे जो खाद्यान्न हैं, उनके अन्तर्गत जो भूमि है, वह कैश क्राप में चली गई है जोकि देश के लिय नुक्सान वाली बात है ।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या सरकार ने बोआई का मौसम शुरू होने से पहले किसानों को इस बारे में सलाह देने की कोई कोशिश की है कि वे गन्ना बोने की जमीन का क्षेत्रफल बढ़ायें या कम करे ?

†श्री स० का० पाटिल : केवल सलाह से कोई लाभ नहीं होता क्यों कि किसान अपना फायदा अच्छी तरह जानता है ? मैं जो निकट भविष्य में एक इस तरह का विधान रखने के बारे में सोच रहा हूं जिस में संपूर्ण कृषि उत्पादन का ख्याल रखा जाय और व्यापारिक फसलों तथा अनाज की फसलों के लिये एक प्रकार का कोई ढांचा मुकर्रर किया जाये । लेकिन यह बहुत पेचीदा और मुश्किल मामला है और मैं समझता हूं कि अक्सर यहां यह उठाया जा चुका है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या इस बात पर विचार करना ठीक नहीं होगा कि चीनी जो हम बाहर भेजते हैं और गहूं मंगाते हैं तो गन्ने की बवाई कुछ कम करके उसकी जगह पर गेहूं बोया जाये और गेहूं बोने को प्रोत्साहन दिया जाय ? क्या यह अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा ?

श्री स० का० पाटिल : यह बात तो ठीक है लेकिन किसान कैसे करेगा । किसान तो मानता है कि गन्ने में उसको ज्यादा लाभ मिलता है । किसान पर एसा कोई निर्बंध नहीं है कि वह गन्ना कम करे और गेहूं बोए ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस साल उत्तर प्रदेश में बहुत सारा गन्ना पड़ा हुआ है और मिल वाले उसको ले नहीं रहे हैं ? क्या एसी कोई शिकायतें आपके पास भी आई हैं या नहीं आई हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : इस का इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी बताया है कि किसान गन्ना बोने के लिये ज्यादा उत्सुक हैं अपेक्षाकृत गेहूं बोने के क्योंकि उन्हें इसमे अधिक लाभ है । क्योंकि हमारे देश में गेहूं का अभाव है और बाहर से गेहूं का आयात करना पड़ता है, इसलिये क्या हम एसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते कि किसान गहूं बोने की ओर अधिक अग्रसर हों ?

†अध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने कहा है कि वह कोई लैजिस्लेशन लाना चाहते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : इसका दूसरा इलाज सबसिडी वगैरह देना है गेहूं के लिये। लेकिन यह चीज़ आवश्यक नहीं है। इस का कारण यह है कि इस बरस करीब १ करोड़ १० लाख टन जितना गेहूं हो गया है। मैं समझता हूं हमारे लिये यह काफी है। लेकिन दो चार बरस [illegible] देखना चाहिये कि इसी लेवेल पर हम रहते हैं या नहीं। अगर इस लेवेल पर हम रहे तो यह चीज पैदा नहीं होगी कि बाहर से गेहूं मंगाना पड़े।

†**श्री महेश्वर नायक** : गन्ने की खेती बढ़ाने के अलावा, उसकी किस्म सुधारने के लिये सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गन्ने की किस्म बराबर अच्छी होती जा रही है क्योंकि हर जगह अनुसंधान केन्द्र हैं और पिछले कई वर्षों से प्रति दिन अनुसंधान हो रहा है। भारत में उगायी गयी कुछ किस्में दुनिया की सर्वोत्कृष्ट किस्मों के मुकाबले में काफी अच्छी समझी जाती हैं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा दो मंजिली बसों का आयात

+

†*५११. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम का विचार २० दो मंजिली बसें और आयात करने का है और इसके लिये उसने संघ सरकार से वित्त आवंटित करने की प्रार्थना की है ;

(ख) क्या प्रस्ताव पर विचार हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन उपक्रम का २० दो मंजिली बसें आयात करने का विचार है और उसने आवश्यक आयात लाइसेंस दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है। इस विशिष्ट प्रयोजन के लिये उपक्रम ने अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये बसें शीघ्र प्राप्त होने में क्या रुकावटें हैं ?

†**श्री राजबहादुर** : आवश्यक लाइसेंस देने के लिये आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक को इस मामले की छानबीन करनी होगी और यह वह कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ लोग साउथ इंडिया जा रहे हैं दो सौ बसों को खरीदने के लिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लोगों को जाने दीजिये, उन से क्या मतलब है ?

श्री रघुनाथ सिंह : इनके डिपार्टमैंट के और दूसरे लोग जा रहे हैं। यह आज के अखबार में आया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि लोग जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** जो प्रश्न किया गया है वह केवल इन बीस डबल डैकर बसिस के बारे में है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** ये २० दो मंजिली बसें मंगाने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ।

†**श्री राज बहादुर :** एक एक बस की कीमत ४१,००० रुपया है । मैं विदेशी मुद्रा की रकम ठीक ठीक नहीं बता सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के पास अभी बसों का जो बेड़ा है वह दिल्ली की आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल कम है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने स्थिति का ठीक ठीक पता लगाया है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह तो दिल्ली परिवहन उपक्रम को मालूम करना होगा । यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह बिलकुल अपर्याप्त है उससे जरूरत पूरी हो रही है लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह पर्याप्त है । इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि जरूरत पूरी करने के लिये बेड़े मे काफी संख्या में बसें हों । इसी लिये दो मंजिली वाली बसों की यह व्यवस्था है । तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में नियमित कार्यक्रम है और आशा है कि योजना की अवधि के अन्त तक विभिन्न मार्गों पर १००० बसें चलेंगी ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश से भी बसें लेने का दिल्ली प्रशासन का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि हम भारत में दो मंजिली बसें तैयार कर रहे हैं और यदि हां, तो बाहर से इतनी बसें मंगाने का यह सवाल कैसे पैदा हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि ये बसें तैयार करने के लिये हमें अब भी कुछ हिस्सों और पुर्जों का आयात करना पड़ता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली में दिन में किसी खास समय ही भीड़ होती है क्या यह आयात करने से पहले दो मंजिली बसों के यातायात से लाभहानि की यथोचित रूप से जांच कर ली गयी है ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में स्थिति बिलकुल उलटी है । क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर लोगों की थोड़ी थोड़ी भीड़ होती है और इसीलिय सेक्रटरिएट या दूसरी जगहों पर दो मंजिली बसों की हमें जरूरत है ।

त्रिपुरा में पशु महामारी

†*५१२. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि छेन्ता, त्रिपुरा में पशु महामारी फैल गई है और जिससे अनेक पशु मर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बहुत फैली हुई महामारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक स्थायी पशु चिकित्सालय खोलने का है जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) छेन्ता में कोई पशु महामारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) छेन्ता में फिलहाल कोई नहीं।

†**श्री दशरथ देव** : क्या सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है कि चमानू क्षेत्र में पशु महामारी फैली हुई है और वहां कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : वह महामारी नहीं थी। कुछ थोड़े से पशु वहां मर गये लेकिन बाद में वह रोग फैला नहीं। इसीलिए मैं ने जवाब दिया कि वह महामारी नहीं थी और अब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रासायनिक-उर्वरक

+

†*५१३. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री याज्ञिक :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट के बदले रासायनिक-उर्वरक के रूप में दे दिया जा रहा है और भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में, बड़े पैमानें पर बिक रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). जी हां। इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि सोडियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के किसानों को अमोनियम सल्फेट खाद के बदले में दिया जा रहा है।

(ग) (१) अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध राज्य सरकारें कार्रवाई कर सकें इस उद्देश्य से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में एसा संशोधन किया गया है कि खाद के रूप में किसी भी पदार्थ की बिक्री जो वास्तव में खाद न हो, जुर्म होगा।

(२) महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों से इस मामले की जांच पड़ताल करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए, कहा गया है। जांच पड़ताल जारी है। इस बीच राज्य सरकारों ने किसानों को इस बारे में आगाह कर दिया है और अपने निरीक्षण कर्मचारियों को भी ठीक ठीक हिदायतें दे दी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० क० गोपालन : क्या नडियाद तथा दूसरी जगहों पर उर्वरक निरीक्षकों ने कभी कोई जांच की है और यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट थी ?

†श्री स० का० पाटिल : इसमें शक नहीं है कि वह बड़े पैमान पर बेचा गया था। हमें इस बाले में सूचनाएं भी मिली थीं कि ऐसा हो रहा हैं । इसीलिए हमने सम्बन्धित सरकारों को चेतावनी दे दी है और इस बात के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं कि इस जुर्म के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या सरकार को मालूम है कि सोडियम सल्फेट के प्रयोग से न केवल खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं बल्कि दो तीन साल तक जमीन भी बेकार हो जाती है ।

†श्री स० का० पाटिल : यह बहुत कुछ ठीक है । सौडियम सल्फेट से जमीन के मूल-भूत तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसका प्रयोग खतरनाक हैं । इसीलिए इसके लिए कठोर दंड होना चाहिये । लेकिन कठिनाई यह है कि केवल किसी पदार्थ के बेचे जाने से ही हम उसे दंड नहीं दे सकते। उसमें यह सिद्ध करना होगा कि वह रासायनिक पदार्थ खाद के तौर पर लिया गया था और खाद के रूप में ही उसका प्रयोग किया गया था।

†श्री उमानाथ : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि नेशनल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, बम्बई, नामक संस्था लाखों टन इसे खरीद बेच रही है । यदि हां, तो इस संस्था के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री स० का० पाटिल : यही वह संस्था है । माननीय सदस्य ने हमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी दी है ।

†श्री ज० ब० सिंह : मैं यह जानाना चाहता हूं कि वह एनक्वायरी किस के जरिए हो रही हैं उसको पुलिस कर रही है या कोई जूडीशियल एन्क्वायरी हो रही है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह एनक्वायरी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की सी० आई० डी० इसको कर रही है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस विशिष्ट फर्म का नाम क्या है ? क्या यह सच है कि उसने पहले भी इस तरह की बातें की थीं ?

†श्री स० का० पाटिल : नाम माननीय सदस्य ने बताया है । हमें यह मालूम नहीं कि वह फर्म पहले भी ऐसा करती थी या नहीं । लेकिन वह पहले ऐसा करती हो या न करती हो, वह जुर्म है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या वैज्ञानिक महानुभाव से यह परामर्श ले लिया गया है कि यह जो रासायनिक खाद है यह कुछ वर्ष के पश्चात् खेती के उत्पादन में बाधा पहुंचाती है ? अगर ऐसा है तो क्या गोबर की खाद जो यहां सुलभ भी है और उससे उत्पादन भी बढ़ता है, उसके बनाने की योजना पर विचार हो रहा है ?

श्री स० का० पाटिल : यह तो दूसरा सवाल है, इसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री याज्ञिक :** क्या यह सच है कि यह सोडियम सल्फेट बहुत बड़ी मात्रा में बेचा गया है जिसकी वजह से गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के अन्य भागों के भी किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर उन्होंने यह कह कर दे दिया है कि वह बड़े पैमाने पर बेचा गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या खाद के रूप में सोडियम सल्फेट बेचने के लिए किन्हीं कम्पनियों या व्यक्तियों को दंड दिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हमें पता लगा है कि वह कम्पनी जिसका अभी उल्लेख हुआ है, ऐसा करती रही है । उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है । कुछ कानूनी दिक्कतें हैं। मैं वह बताना नहीं चाहता क्योंकि अभी सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य तथा कृषि संगठन

†*५१४. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने अल्प विकसित देशों को बड़ी मात्रा में फालतू खाद्य तथा कुछ नकदी दे कर सहायता करने का एक कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

खाद्य तथा कृषि संगठन ने अल्प विकसित देशों को निम्नलिखित के लिए सहायता देने के लिए ३ वर्ष तक प्रयोगात्मक रूप में चलाने के लिए १० करोड़ डालर का विश्व खाद्य कार्यक्रम तैयार किया है : (१) सतत पौष्टिक आहार की कमी के कारण संकटकालीन खाद्य विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति जिसमें खाद्य रक्षित भंडारों की स्थापना भी शामिल है ।

(२) स्कूल से पहले और स्कूल के समय खाना खिलाने में मदद करना ।

(३) अग्रिम परियोजनाओं को कार्यान्वित करना जिनमें आर्थिक तथा सामाजिक विकास में भोजन एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ।

इस कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से अधिकतर अनाज के रूप में अंशदान लिया जायेगा। इस कार्यक्रम से नकदी ऊपरी खर्च पूरा करने के लिए काम में लायी जायेगी।

अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इस सहायता में भारत का क्या हिस्सा होगा क्योंकि कार्यक्रम कार्यान्वित करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक बातें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : खाद्य तथा कृषि संगठन किन शर्तों पर बहुतायत वाले देश से अनाज ले रहा है और कमी वाले देश को दे रहा है ?

†श्री स० का० पाटिल : कुछ साल पहले हमने अपने देश की ओर से खाद्य तथा कृषि संगठन के सामने यह सुझाव रखा था कि वह एक खाद्य-बैंक स्थापित करे। उसके पीछे कल्पना यह थी कि बहुतायत वाले देश अपना सारा अतिरिक्त अनाज उसे दे दें ताकि कमी वाले देशों में उसका अधिक अच्छा उपयोग हो सके। यह पहला दौर है और १० करोड़ डालर खाद्य तथा कृषि संगठन के पास रखा गया है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : किन किन देशों से यह सहायता मिलने की संभावना है ?

†श्री स० का० पाटिल : अमेरिका ने १० करोड़ डालर खाद्य तथा कृषि संगठन को दिया है। बहुतायत वाले देश वे हैं जहां अनाज अधिक है और कमी वाले देशों के बारे में सभी को जानकारी है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इससे भारत को भी लाभ होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : भारत कमी वाला देश है ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस संग्रह से उन द्विपक्षीय करारों पर भी असर पड़ेगा जो भारत ने अन्य देशों के साथ किये हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : उससे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो करार किये जा चुके हैं उनके अधीन जिम्मेदारी पूरी करनी ही होगी। यह अधिक अच्छा है। यदि यह किया जाय और सारा फालतू अनाज इकट्ठा कर एक संग्रह बनाया जाय तो वितरण अधिक अच्छा होगा और खाद्य तथा कृषि संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होने के कारण, उसका उस प्रयोजन के लिए अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकेगा।

प्रश्न काल समाप्त

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी में एक स्त्री से बलात्कार

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. {
श्रीमती विजय राजे सिंधिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कृष्ण पाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा कर्मचारी वृन्द के सदस्यों ने २७ अप्रैल, १९६२ को शुक्रवार को मोरीना और धौलपुर के बीच पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी में दो स्त्रियों से बलात्कार किया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) तीन कुलियों और दो सार्टरों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है । पुलिस ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ और ५११ के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार कर लिया है ।

(ख) मामले की जांच हो रही है । गिरफ्तार व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दिया गया है ।

†**श्रीमती विजय राजे सिंधिया :** क्या कुछ समय पहले ऐसा मामला नहीं हुआ था जब एक स्त्री और एक बच्चे को चलती गाड़ी में से फेंक दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मामले का सही ब्यौरा क्या है। कुछ तथ्यों के आधार पर अल्प-सूचना प्रश्न पूछा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पुलिस के पास जाने से पूर्व रेलवे मंत्रालय के पास मामले का ब्यौरा आया होगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** शिकायत दर्ज करवा दी गई है ।

२६ अप्रैल, १९६२ को लगभग १० बजे रात्रि को, पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी का रेलवे डाक सेवा दल झांसी से चला जिसमें एक प्रमुख सार्टर, आठ सार्टर और तीन कुली थे । काम एक डाक के डिब्बे में तथा उससे लगे हुए तीसरी श्रेणी के एक डिब्बे में किया जा रहा था। डाक के डिब्बे में और तीसरी श्रेणी के डिब्बे के बीच एक अन्दर जाने वाला दरवाजा था। बिजली बिल्कुल फेल हो चुकी थी और डाक गाड़ी में काम मोम बत्तियां जला कर लिया जा रहा था ।

मोरीना में, जहां गाड़ी १२ बज कर २९ मिनट को पहुंची, दो पुरुषों ने दो स्त्रियों और पांच बच्चो के साथ तीसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ने का प्रयत्न किया । डिब्बे में मौजूद कर्मचारियों को दो स्त्रियों को और पांच बच्चों को यह कहते हुए चढ़ा लिया कि डिब्बा जनाना डिब्बा था और इसलिये पुरुष उसके अन्दर नहीं चढ़ सके । वे किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ गये । तीन कुलियों और दो सार्टरों के बारे में शिकायत हुई है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको १२ बज कर ५९ मिनट पर धोलपुर स्टेशन पर उतार दिया । पुरुषों न इस बात को मान लिया और उन्होंने आगरा में पुलिस से शिकायत की। वे कर्मचारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया गया है । उनको विभाग द्वारा मुअत्तिल कर दिया गया है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** सर्वोत्तम प्रबन्ध के बावजूद हत्या जैसी घटनाएं हो जाती हैं। जितनी जल्दी जल्दी और निडरतापूर्वक ये घटनायें होती हैं न प्रायः हर रोज किन्तु बहुत बार बार, उनसे यह सिद्ध होता है कि रेल प्रशासन अकुशल है । ये घटनायें हुई जहां स्त्रियो को एक आर० एम० एस० डिब्बे में घूसने के लिये लुभाया गया । वे इसमें कैसे घुसीं ? साधारणतया वे साधारण गाड़ियों में यात्रा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** यदि ऐसी बात है, तो उन पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारियों के बारे में क्या बात है, जो इसमें थ ? उन के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सारी सूचना दे दी गई है ।

श्री राम सेवक यादव : वे लोग किस तारीख को गिरफ्तार किये गये ?

श्री जगजीवन राम : उसी वक्त ट्रेन में से ही गिरफ्तार कर लिये गये थे ।

श्री बड़े : यह इनवैस्टिगेशन रेलवे पुलिस कर रही है या वहां की लोकल पुलिस कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह दोनों लोकल पुलिस ही होती हैं। जी० आर० पी० पी० तो स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** उनको क्यों उन डिब्बे में बिठाया गया और स्त्रियों वाले डिब्बे की ओर क्यों नहीं भेजा गया ?

†**श्री जगजीवन राम :** जिन कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने कहा था कि वह स्त्रियों वाला डिब्बा था।

†**श्री बड़े :** क्या उन की जमानत हो गई है या वे अभी भी गिरफ्तार हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** उनकी जमानत हो गई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या उनको मुअत्तिल किये जाने के बाद, विभागीय कार्यवाई चल रही है या मामला पुलिस पर छोड़ दिया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह स्पष्ट होना चाहिये कि जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वे मामले की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या विभाग भी इसकी जांच कर रहा है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, । ध्यान दिलाने वाली अधिसूचना ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीका को चीनी का निर्यात

†*५०५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के सभी देशों से चीनी खरीदने की अमरीका की जो नयी नीति है उस का अमरीका में इस वर्ष १ जुलाई के बाद किये जाने वाले भारतीय चीनी के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत कोटे के आधार पर, जो अब तक जारी रहा है, अमरीका को चीनी बेचना जारी रख सकेगा ; और

(ग) नयी व्यवस्था के अन्तर्गत अमरीका को चीनी का निर्यात करने के लिये प्रति टन अनुमानतः कितनी सहायता देना आवश्यक होगा ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). अमरीकी सरकार न १ जुलाई १९६२ से विश्वजनीन पद्धति पर चीनी का आयात करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। इसलिये यह सवाल पैदा नहीं होता।

अजमेर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोके गये तार

†*५१५. **श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ अप्रैल, १९६१ को अजमेर से समाचार पत्रों और अफसरों को भेजे गये तार अजमेर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोक लिये गये थे ;

(ख) क्या तारों का इस प्रकार रोका जाना अवैध और अनुचित पाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) कुछ तारें जो आपत्तिजनक समझी गई थीं, भारतीय तार नियमों १७ और २४ के अधीन स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लिये गये थे।

(ख) जी नहीं, किन्तु कार्यवाई प्रशासनिक हिदायतों के अनुकूल नहीं थी।

(ग) संबद्ध अफसर को उचित रूप से मंत्रणा दी गई है कि वह भविष्य में अधिक ध्यान के साथ इस विषय मे हिदायतों का पालन करें।

कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन

†*५१६. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ताकि लोह अयस्क पत्तन तक शीघ्रता से भेजा जा सके ; और

(ख) इस काम के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और काम के कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली में टेलीफोन

*५१७. { श्री रा० स० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोनों की कमी के कारण, जिसकी मांग बढ़ती जा रही है, दिल्ली के निवासियों को बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ; और

(ग) टेलीफोन सेवा की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्रवाई करने का विचार है और कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान १६००० लाईनें बढ़ाई गई थीं, जिससे कि टेलीफोन प्रणाली की क्षमता दुगुनी हो गई है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ३०,००० लाइनें और बढ़ाने का विचार है ।

जलढाका जल-विद्युत परियोजना

†*५१८. { डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरकार मुरमू :
श्री कार्जी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने, उत्तर बंगाल में बाढ़ों को रोकने और बिजली तैयार करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना पर, जलढाका जल-विद्युत् परियोजना की मंजूरी दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना भारत सरकार द्वारा छोड़ दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जलढाका जल-विद्युत् परियोजना से केवल बिजली पैदा करने का इरादा है। इस में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई उपबंध नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†*५१९. { **श्री बसुमतारी :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** :(क) हां, गोहाटी और शिलांग में

(ख)	गौहाटी . . .	१९६४–६५ में
	शिलांग . . .	१९६५–६६ में
(ग)	गौहाटी . . .	लगभग २५ लाख रुपये
	शिलांग . . .	लगभग २१.५ लाख रुपये

कृषि आयोग

†*५२०. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में कृषि विकास के विविध पहलुओं का पुनर्विलोकन करने के लिये एक कृषि आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : कृषि सम्बन्धी आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। सब राज्यों से उत्तर प्राप्त हो जाने के उपरांत अन्तिम फैसला किया जायेगा। दो राज्य सरकारों ने अभी तक अपने उत्तर नहीं भेजे।

पशुधन

५२१. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्रों में गाय और मुर्गी पालन के सम्बन्ध में कुछ विशेष केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां कहां हैं और इन पर पृथक पृथक कितना व्यय किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि गोवंश की उन्नति और नस्ल सुधार के लिये जो केन्द्र स्थापित किये गये हैं, उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में उस सम्बन्ध में कुछ अनुकूल निर्णय लेने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) से (घ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मल अंग्रेजी में

श्रीसैलम और नागार्जुनसागर परियोजनाएं

†*५२२. **श्रीमती यशोदा रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीसैलम एवं नागार्जुनसागर जल-विद्युत् योजनाओं के समन्वित विकास के अनुमोदन का प्रश्न उन के मंत्रालय के पास आया है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि निर्णय किया जा चुका है, तो क्या वह निर्णय आन्ध्र प्रदेश सरकार को बताया जा चुका है ; और

(घ) क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों को दोनों परियोजनाओं के लिये पृथक २ परियोजना निवेदन पेश करने को कहा गया है ।

भारत में मानसिक रोग

*५२३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं क्या इस तथ्य का पता लगाने के लिये शासन द्वारा सर्वेक्षण करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(१) स्वास्थ्य मंत्रालय की गतिविधियों पर एस्टीमेट कमेटी की १९५८–५९ की रिपोर्ट में की गई एक सिफारिश के अनुसार १९६१ में समस्त राज्य सरकारों (सिवाय उड़ीसा सरकार के जहां इस समय कोई मानसिक अस्पताल नहीं है) से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत मानसिक अस्वस्थता और मानसिक व्याधि के मामलों पर एक सर्वेक्षण करें। राज्य सरकारों से अभी तक मिली सूचना को देखने से ज्ञात होता है कि केरल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र सरकारें सर्वेक्षण कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसके परिणाम भारत सरकार को भेज दिये गये हैं। शेष राज्य सरकारों ने इस को प्रारम्भ कर लिया है अथवा नहीं—इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है और उन्हें सतत इस विषय पर स्मरण कराया जा रहा है ।

जैसे ही आवश्यक सामग्री राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, सर्वेक्षण के परिणाम सांख्यिकीय रूप से सारणीबद्ध कर दिये जायेंगे ।

(२) सुपेरिन्टेंडेंट, मानसिक अस्पताल, आगरा के मार्ग-दर्शन में मानसिक रोगों पर एक प्रारम्भिक-आपरीक्षण आगरा के एक चुने हुए औद्योगिक क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है। यह

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिक-आबादी वाले भाग में किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत लगभग एक हजार परिवारों, जिनकी आबादी करीब पांच हजार है, की जांच की जा रही है।

पेंसिल निर्माण के लिये लकड़ी का आयात

†*५२४. **श्री जेधे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंसिल निर्माण के लिये काम में आने वाली लकड़ी जो देश में उपलब्ध नहीं होती, विदेश से मंगाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी समय देश में उपयुक्त किस्म के वृक्ष लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है, जिन से अपेक्षित किस्म की लकड़ी प्राप्त हो सके ; और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) क्योंकि पेंसिल निर्माता इमारती लकड़ी स्लेटों के रूप में सुखाई गई और सर्वे भी गई चाहते हैं—जिस का उत्पादन देश में बहुत कम है, अमरीकी और अफ्रीकी देवदार, स्लेटों के रूप में, पेंसिल निर्माण के लिये बाहर से मंगवाया जा रहा है

(ख) यह पाया गया है कि रंगा हुआ और मोम वाली सरू, देवदार तथा वैंद अमरीकी देवदार के मुकाबले में हैं। संवारा गया कूयान और होलीजैंट भी अफरीकी देवदार जैसे अच्छे माने जाते हैं। इस किस्म की लकड़ी इस देश में प्राप्त होती है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

जापान से प्रौद्योगिकीय सहायता

†*५२५. **श्री महेश्वर नायक** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जापान की सरकारों के बीच एक करार हुआ है जिस के अधीन कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जापान द्वारा प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी भारत को भी दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

करार के अधीन जापानी सरकार, नाडिया जिला (पश्चिम बंगाल), संबलपुर जिला (उड़ीसा) में चकूली फार्म, शाहबाद जिला (बिहार) में आराह, और सूरत जिला (गुजरात) में वयारा फार्म में स्थापित किये जाने वाले चार फारमों को चलाने के लिये अपेक्षित मशीनरी और उपकरण के चार मुकम्मल सैट देगी और प्रत्येक फारम में काम करने के लिये चार जापानी शिल्पिक देने का खर्च भी देगी। राज्य सरकारें फारमों को चलाने का व्यय देंगी तथा जापानी कर्मचारियों के

†मूल अंग्रेजी में

लिये निःशुल्क निवास की व्यवस्था करेगी। जापानी सरकार को भी वे विशेषाधिकार और अनुक्तियां प्राप्त होंगी जो कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञों को प्राप्य हैं। फारमों में जापानी तरीकों से कृषि के तरीकों का प्रदर्शन किया जायगा और वे भारतीय किसानों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिये केन्द्र का काम करेंगे।

बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस में सोने के लिये डिब्बा

†*५२६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस में सोने के डिब्बे की व्यवस्था करने के प्रश्न की इस बीच जांच कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह लगा दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी तक सेवा चालू नहीं की गई क्योंकि आवश्यक संख्या में सोने के डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं।

हैलीकोप्टर डाक सेवा

†*५२७. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मिजो जिले के लंगलेह सब-डिवीजन में हेलीकोप्टर डाक सेवा लागू करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ;

(ख) क्या उन को आसाम में कचार, मिजो जिले और उत्तरी कचार की पहाड़ियों के लोगों को हो रही संचार की कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) सिल्चर-गोहाटी, सिल्चर-कलकत्ता और सिल्चर-एजाल के बीच सिल्चर में एक अतिरिक्त वायरलैस सर्किट लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) आसाम में, विशेष कर उल्लिखित क्षेत्रों में, संचार लाइनें पर्वतीय क्षेत्र और घने जंगल में से गुजरती हैं। इन क्षेत्रों में लाइन संबंधी अन्तर्बाधाओं को ठीक करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वहां रेल सेवा बहुत कम होती है और पठार की कठिनाइयां होती हैं।

(ग) सिल्चर-गौहाटी, सिल्चर-कलकत्ता और सिल्चर-ऐजल के बीच वायरलैस स्टैंडबाई सर्किटों को लगाने का प्रश्न विचाराधीन है।

पानशेत और खड़कवासला बांध

†*५२८. **श्री नाथ पाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पानशेत और खड़कवासला बांध के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिये भारत सरकार से कहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मांगी गयी सहायता का क्या ब्योरा है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हफाजि मुहम्मद इब्राहीम)** :(क) से (ग). जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक दल सितम्बर १९६१ में पूना की बाढ़ों से पैदा होने वाली हालत का अध्ययन करने के लिये, महाराष्ट्र राज्य में गया था, राज्य सरकार ने उन के साथ पनशेत और खड़कवासला बांधों की मरम्मतों के लिये लगभग २५० लाख रुपये की अनुमानित केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर बातचीत की। उन बातचीतों में यह स्वीकार किया गया कि जब तक प्रविधिक अनुसंधान पूरा न हो जाय, इस मामले पर विचार तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय। तब से कोई अग्रेतर प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई ।

राप्ती पुल

†*५२९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ पर राप्ती पुल के बारे में २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'स्पैन' (दो आधारों के बीच का पुल का भाग) के टूट जाने के कारणों की जांच के लिये समिति को अपना प्रतिवेदन कब देना है ;

(ख) प्रतिवेदन पेश करने में समिति की क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ; और

(ग) कथित पुल का निर्माण पुनः आरम्भ करने में क्या रुकावटें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) अक्तूबर १९६१ के अन्त तक ।

(ख) मुख्य बाधायें ये हैं :

(१) मुख्य गर्डर के टूटे हुए किनारों तक पहुंचने में कठिनाई (जो बहुत गहरे पानी के नीचे पड़े हैं) जिस के कारण टूटे हुए गर्डर का सीधा परीक्षण करने में विलम्ब हुआ ।

(२) समिति के प्रधान (श्री जी० पांडे, उपकुलपति रुड़की विश्वविद्यालय) की अचानक बीमारी ।

(ग) पुल के पिछले ठेकेदारों द्वारा अधूरे छोड़ दिये गये काम को, जिन का ठेका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है, पुनः आरम्भ करने के लिये, निर्माण अभिकरण निश्चित करने के लिये नई व्यवस्था करनी होगी ।

मालाबार तट पर मत्स्य-पालन

†*५३०. { **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मालाबार तट पर मछलियां और विशेषतः 'सारडाइन' और 'मैकरेल' मछलियों बड़े पैमाने पर घट रही हैं ;

(ख) क्या सरकार उन के कारणों की जांच करेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को मालाबार तट पर मछली न होने के कारण मछुओं की खराब दशा के बारे में जानकारी है ; और

(घ) क्या सरकार कोई सहायता कार्य करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). मैकरल और सारडीन मछलियों की विद्यमानता अनिश्चित और मौसमी है । पिछले वर्ष मत्स्य पालन अप्रत्याशित तौर पर सफल रहा । इस वर्ष शोल मछली गायब हैं । अनुसंधान जहाज "एम० वी० वरुण" और केन्द्रीय समुद्रीय अनुसंधान संस्था मलाबार तट के साथ इन शोल मछलियों के न मिलने के कारणों का अनुसंधान कर रहे हैं ।

(ग) और (घ). केरल सरकार ने मछुवों के सुपात्र परिवारों को निशुल्क साप्ताहिक राशि मंजूर कर दिया है । इस ने मछली पकड़ने वाली जातियों के वित्तीय सहायता भी दी है ।

जबलपुर इटारसी सेक्शन पर माल-डिब्बों की कमी

†*५३१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-इटारसी सेक्शन (मध्य रेलवे) पर अनाज ले जाने के लिये माल-डिब्बों की अत्यधिक कमी के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) माल डिब्बों की कुल उपलब्धि के अन्दर अधिकतम संभव सीमा तक यातायात को उठाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

चीनी का उत्पादन

†*५३२. **श्री बा० वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के चीनी कारखानों के मिल मालिक चीनी की कम प्रतिशतता के आधार पर गन्ने के मूल्य में कमी करने का विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किसानों के हितों के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) गन्ना उत्पादकों का प्रमुख हित यह है कि उस की खड़ी फसल को पेरा जाय और इस उद्देश्य के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है ।

थाईलैंड को सैलूनों का संभरण

†*५३३. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार थाईलैण्ड सरकार से थाई शाही परिवार के लिये इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बने तीन रायल सैलूनों का सम्भरण करने के लिये बातचीत कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) विश्वजनीन टेंडर के प्रयुत्तर में थाईलैंड की राज्य रेलवे को इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में बनाये जाने वाले तीन शाही सैलून के संभरण की पेशकश की गई है ।

(ख) थाईलैंड राज्य रेलवे के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पोस्ट कार्ड बेचने की मशीन

†*५३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट कार्ड बेचने की मशीन के क्षेत्र परीक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सफल हुए हैं ; और

(ग) सभी डाकखानों में ऐसी मशीनें कब तक लगा दी जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि मशीन का काम संतोषजनक है, इसमें यह त्रुटि है कि एक पोस्ट कार्ड लेने के लिय दो काम करन पड़ते हैं । पहला, कि सिक्का डालना पड़ता है और पोस्ट कार्ड आने से पूर्व लीवर उलटना पड़ता है । इसलिये एक मशीन बनाने के लिये प्रयत्न किय जा रहे हैं जिस के द्वारा लीवर उलटे बिना सिक्का डालने से पोस्ट कार्ट आ जाए ।

(ग) ज्यों ही भारत में उपयुक्त मशीन बनाने के हमारे प्रयत्न सफल हो जाएं ।

डीजल इंजनों का जल जाना

†*५३५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्घटनावश आग लगने के कारण दो डीजल इंजन—एक गया रेलवे जंक्शन के होम सिगनल के निकट और दूसरा पूर्व रेलवे के ग्रांड कॉर्ड सेक्शन पर इस्लामपुर रेलवे स्टशन पर—जलकर राख हो गये ; और

(ख) यदि हां, ता उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। केवल थोड़ी आग लगी थी ; एक २२-३-६२ को गया के समीप, दूसरी ५-४-६२ को इस्माइलपुर के समीप। इंजनों की मरम्मत की जा चुकी है और उन्हें चालू कर दिया गया है।

(ख) रबड़ की जिस नाली में से तेल चलता है, उस के फ़ट जाने से आग लगी, जो गर्म टर्बो सुपर चार्जों पर टकराई। प्रत्येक घटना में हानि १००० रुपये के लगभग हुई।

दिल्ली दूध योजना

*५३६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूध योजना द्वारा कितनी क्रीम और कितना घी प्रति मास तैयार किया जाता है ;

(ख) वर्ष १९६१–६२ के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इसके वितरण की क्या व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग). सभा की पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६**]

मलाया को चीनी के संभरण सम्बन्धी करार

†*५३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही सरकार ने मलाया को २५,००० टन चीनी का संभरण करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा मलाया को चीनी के संभरण के लिय कोई करार नहीं किया गया। हाल ही में एक भारतीय फर्म ने अप्रैल-जून १९६२ में भेजने के लिये, सी-२९ ग्रेड के लिये मलाया पत्तनों पर्यन्त किराया भाड़ा समेत ३१ पौण्ड ७ शिलिंग प्रति मीट्रिक टन पर २५,४०० मीट्रिक टन चीनी का निर्यात करने के लिये संविदा किया है।

संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनायें

†*५३८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में कितनी संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनायें संगठित करने का विचार है ;

(ख) इस समय वहां ऐसी कितनी अग्रिम योजनायें चालू हैं ; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**
(क) ९ अग्रिम परियोजनाएं।

(ख) २ अग्रिम परियोजनाएं।

(ग) तीसरी योजना अवधि के लिये १०.९८ लाख रुपये तथा १९६१-६२ के लिये १.२२ लाख रुपये।

रेलवे अस्पतालों में रोगियों से भोजन का पैसा लिया जाना

†*१३९. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में १५० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से उन्हें अथवा उनके आश्रितों को दिये जाने वाले भोजन का पैसा लिया जाता है;

(ख) यह व्यवस्था कब से की गई है;

(ग) क्या इस व्यवस्था को हटाने के लिए कर्मचारी कार्मिक संघों से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) रेलवे कर्मचारी से, जो रेलवे अस्पताल में रोगी होता है, यदि उसको प्रति मास १८० रुपये तक वेतन मिलता है, खुराक का शुल्क नहीं लिया जाता, किन्तु उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह शुल्क लिया जाता है जिस का रेलवे अस्पताल में रोगी के तौर पर इलाज किया जाता है। क्षय रोगियों के मामले में कर्मचारी या उसके परिवार वालों से ऐसा शुल्क नहीं लिया जाता यदि कर्मचारी का मासिक वेतन ३८० रुपये से अधिक नहीं होता।

(ख) यह प्रणाली बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। १-१-६१ से पहले, उपरोक्त (क) में उल्लिखित वेतन सीमा क्रमशः १३० और ३०० रुपये थीं।

(ग) और (घ). रेलवे मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन नहीं आया।

नौवहन 'टनभार'[1]

†५४०. **श्री हीं० ना० मुकर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन 'टनभार' के योजना लक्ष्यों को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) भारत के नौवहन निगमों द्वारा इस समय कितने 'टनभार' का संचालन किया जा रहा है; और

(ग) क्या आयात किए गए खाद्यान्नों को केवल भारतीय जहाजों द्वारा लाने की कोई योजना है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित ३,७४५,०० जी० आर० टी० लक्ष्य के मुकाबले में लगभग ४५,६०० जी० आर०

†मूल अंग्रेजी में
[1]Shipping Tonnage.

टी० की शुद्ध वृद्धि की गई है। तथापि पहले किये गये वायदों को ध्यान में रखते हुए, समय पर योजना का लक्ष्य पूरा होने की पूरी आशा है।

(ख) लगभग १,५४,०००० जी० आर० टी०।

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा की ब्रह्मणी नदी पर तटबन्ध[1]

†*५४१. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि जेवापुर के निकट ब्रह्मणी नदी पर नया तटबन्ध बनाने के लिए उड़ीसा सरकार ने २२ लाख रुपये की कोई योजना बनाई है जिससे नदी पर रेल के पुल का बचाव हो सके ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों और उड़ीसा सरकार के बीच इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने यह मांग की है कि आधी लागत रेलवे लगाये ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। उड़ीसा सरकार ने जेवापुर के पास ब्रह्मणी नदी के साथ वर्तमान तटबंध को ऊंचा करने की योजना बनाई है जिस में, भूतकाल में रक्षा बांध के कहीं कहीं टूट जाने के कारण बाढ़ों से प्रभावित ग्राम्य क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये २२ लाख रुपये की लागत पर एक पक्की सड़क बनाने का उपबंध है।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) अभी नहीं।

चीनी का निर्यात

†*५४२. श्री जेधे : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी चीनी मिल सन्था से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है कि वह उसकी तरफ से सीधे ही चीनी का निर्यात करे ;

(ख) क्या सरकार अमरीका को निर्यात की जाने वाली चीनी का कुछ अंश भविष्य में सीधे निर्यात के लिए सहकारी चीनी कारखानों को दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका अनुपात क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Embankment.

खुम्भी की खेती[1]

†*५४३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वाणिज्यिक पैमाने पर खुम्भी की खेती आरम्भ कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार योजना की क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई क्षेत्र चुना गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में खुम्भी की खेती के विकास की एक छोटी अग्रिम योजना १९६० में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मंजूर की गई थी । इस योजना का वास्तव में कार्यारम्भ जुलाई १९६१ से हुआ । हिमाचल प्रदेश के विविध क्षेत्रों का सर्वेक्षण, प्रकृति में उत्पन्न होने वाली खाने वाली खुम्भी की किस्मों को इकट्ठा करने की दृष्टि से किया जा रहा है और उनकी पौधा संबंधी बातों के अध्ययन तथा भूमि संबंधी आवश्यकताओं के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है, उस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप खाई जाने वाली खुम्भी की आठ किस्में एकत्रित की गई है और पहचान ली गई है । प्रयोगशाला में इन किस्मों को पालन के लिये अब तरीकों का विकास किया जा रहा है ।

खुम्भी बनाने की सामग्री हिमाचल प्रदेश द्वारा विविध साधनों से प्राप्त कर ली गई है और विभिन्न किस्मों की खुम्भी को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

काम प्रारंभिक अवस्था में है और कृषि अनुसंधान केन्द्र, सोलन में किया जा रहा है ।

उपरोक्त योजना के अधीन प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर, सरकार हिमाचल प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में, जहां की भूमि जलवायु संबंधी स्थिति उपयुक्त हो, वाणिज्य स्तर पर खुम्भी खेती करने की वांछनीयता का विचार करेंगी । वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिये निश्चित स्थानों का फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता ।

अदन को चीनी का सम्भरण

†*५४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही अदन को चीनी का संभरण करने के लिये कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो उस देश को कितनी चीनी निर्यात की जायेगी तथा किन शर्तों पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mushroom Cultivation.

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). सरकार द्वारा अदन को चीनी के संभरण के सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया गया बहुत सी भारतीय फर्मों ने मई १९६२ तक भेजने के लिये अदन और मुकुल्ला (अदन रक्षित देश) पर्यन्त किराया भाड़ा समेत २४ पौंड १० शिलिंग से २६ पौंड १० शिलिंग तक मूल्यों के बीच प्रति मीट्रिक टन पर ६५.०० मीट्रिक टन भारतीय चीनी का निर्यात करने का संविदा किया है ।

प्रतिरक्षा विभाग को गेहूं की भुसी का सम्भरण

†*५४५. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विभाग में गेहूं की भूसी के संभरण के लिये कोई टेंडर मांगे जाते हैं तथा क्या ऐसे टेंडरों की सूचनायें ठीक प्रकार से अधिसूचित की जाती हैं ;

(ख) पिछली बार ये नीटिस कब जारी किये गये थे तथा टेंडर प्रस्तुत करने के लिये कितना समय दिया गया था ; और

(ग) क्या ये टेंडर सभी देशों के लिये होते हैं अथवा केवल हमारे देश के लिये ही सीमित रहते हैं ?

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) (१) ७–४–६२ को प्रकाशित होने के लिये, भारतीय व्यापार पत्रिका, कलकत्ता में प्रकाशित होने के लिये सूचना ३०–३–१९६२ को दी गई थी ।

(२) ३१–३–६२ को ज्ञात संभरण कर्ताओं को सूचना दी गई ।

(३) टेंडर देने की अंतिम तिथि २१–४–६२ (४ बजे मध्याह्न पश्चात) थी ।

(ग) हमारे देश तक ही सीमित था ।

स्वदेश लौटने वाले भारतीय मजदूर

†*५४६. श्री अ० क० गोपालन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान मलाया तथा सिंगापुर में वर्षों तक कड़ा परिश्रम करने के बाद स्वदेश लौटने वाले भारतीय मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों के कष्टों के बारे में मद्रास से निकलने वाले 'मेल' के ७ अप्रैल, १९६२ के अंक मे प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों तथा हानियों को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला मदुरै में तीर्थ यात्री कर

†७७३. **श्री मलाइछामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मदुरै में पलानी नगरपालिका द्वारा तीर्थयात्री कर लगाने का प्रस्त व स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पास पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो आजकल मामला किस स्थिति में है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सड़क परिवहन का प्रयोग करने वाले यात्रियों पर समान कर लगाने की ऐसी ही कार्यवाही आरम्भ करने के बारे में मद्रास सरकार को इस बारे में लिखा है ।

बीना रेलवे प्रशिक्षण संस्था

†७७४. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीना रेलवे-प्रशिक्षण संस्था कितने समय से काम कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि संस्था इस वर्ष से अधिक से काम कर रही है और चहुं ओर के लोगों को प्रशिक्षण दे रही है ; और

(ग) क्या सरकार इसे बन्द करके किसी अधिक घने बसे स्थान पर ले जाने के निश्चय पर पुनः विचार करेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १९४५ से ।

(ख) हां ।

(ग) भुसावल में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल बनाने का निश्चय किया गया है और बीना स्कूल उसी में मिल जायेगा यह निश्चय करने के कारण हैं कि स्कूल प्राधिकारी भुसावल मे उपलब्ध निम्न सुविधाओं से लाभ उठा सकत हैं :—

> एक बड़ा लोको शेड, एक बड़ा यातायात यार्ड, हम्प शंटिंग, बड़े और महत्वपूर्ण केबिन्स, जटिल अन्तावाशन और मार्ग विन्यास, क्षेत्रीय नियन्त्रण कार्यालय, आदि ।

रूरकेला से भुवनेश्वर और पुरी से प्रयाग तक राजपथ

†७७५. **श्री चि० भू० देव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउर केला से भुवनेश्वर और पुरी से प्रयाग तक बरास्ता पिपरी राजपथ बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसकी अर्थ-व्यवस्था पर विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). प्रश्न के उप ोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सथानों के बीच पहिले से ही निम्न राजपथ विद्यमान है :—

(१) राउरकेला—सुन्दरगढ़—सम्बलपुर—भुवनेश्वर ।

(२) पुरी—सम्बलपुर—अम्बिकापुर—बसन्तपुर पिपरी—राबर्ट्सगंज—प्रयाग (इलाहाबाद) ।

इन दोनों सड़कों का कुछ भाग राज्य राजपथ है और कुछ भाग राष्ट्रीय राजपथ है ।

हावड़ा–बर्दवान विद्युत् चालित रेलगाड़ी के यात्री

†*७७६. { डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरकार मुरमू :

क्य रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल म हावड़ा बर्दवान विद्युत्चालित रेलगाड़ी सेवा के यात्री रोज ही कठिनाई महसूस करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हाल में वर्दवान के यात्रियों को कोई भारी असुविधा नहीं हुई । कदाचित उल्लेख एच० बी० बी० १४७ अप और एच० बी० बी० १४८ डाउन स्थानीय रेल गाड़ियों के बन्द करने का है जो बन्देल और बर्दवान के बीच चलती हैं बन्देल—बर्दवान लाइन पर रेलगाड़ियों को यात्रियों से उचित प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनके फेरे कम कर दिये गये थे । अन्य सुविधाजनक सेवायें हैं । कुछ यात्री, जो पहिले इन रेलगाड़ियों से यात्रा करत थ उनका प्रयोग कर सकते हैं ।

ललितपुर-बांदा बिजावर करतल रेलवे

७७७. श्री कुरे माते : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी राज्य मे ललितपुर–बांदा–बिजावर–करतल रेलवे, निकालने की कोई योजना बनी थी ।

(ख) क्या राज्य पुनर्गठन समिति ने मध्य प्रदेश में कोई नई रेलवे लाइन निकालने की सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हां, तो उस विषय मे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले का कितना क्षेत्र आता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। १९२८ में १४२ मील लम्बी बड़ी लाइन का केवल प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था। इससे पता चला कि यह प्रायोजना लाभप्रद न होगी, इस लिय इसे छोड़ दिया गया।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). राज्य पुनर्गठन समिति के सुझाओं को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की थी कि संलग्न विवरण मे बतायी गयी चार लाइनों का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में अग्रता के आधार पर किया जाय। इन चार लाइनों में से पहली और दूसरी लाइनें दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में बन चुकी हैं। तीसरी लाइन का लगभग ६ मील लम्बा हिस्सा इस समय बनाया जा रहा है। चौथी लाइन का १८४ मील लम्बा जगदलपुर–कोट्टवलासा खण्ड इस समय बनाया जा रहा है। यह खंड २७० मील लम्बी बलाडिल्ला–कोट्टवलासा लाइन का एक हिस्सा है। इनमें से कोई लाइन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होकर नहीं गुज़रती।

विवरण

	राज्य सरकार द्वारा बताई गयी लम्बाई
१. दुर्ग (भिलाई) और चम्पा (बिलासपुर) के बीच मुख्य लाइन पर दोहरी पटरी बिछाना	११५ मील
२. दुर्ग-बलोड-धल्ली राजहरा-रोघाट-कोंडागांव जगदलपुर-कोट्टवलासा लाइन के दुर्ग (भिलाई) धल्ली-राजहरा खण्ड का निर्माण जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है	५० मील
३. कोरबा से आगे चम्पा-कोरबा लाइन का विस्तार . .	२५ मील
४. धल्ली-राजहरा से आगे अर्थात् दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रोघाट-कोंडागांव-जगदलपुर से कोट्टवलासा तक दुर्ग (भिलाई) धल्ली-राजहरा खण्ड का विस्तार। इसकी सिफारिश पहले की जा चुकी है।	(लाइन की लम्बाई बतायी नहीं गयी)।

उद्यान कर्म के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान

७७८. **श्री सरजु पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्यान कर्म के विकास के लिए दूसरी पंच वर्षीय योजना-काल में (वर्षवार) उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) अनुदान किन योजनाओं के लिए दिये गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में उत्तर प्रदेश में उद्यान कर्म के विकास के लिए निम्न वित्तीय सहायता दी गई :—

वर्ष	अनुदान	ऋण	योग
	रु०	रु०	रु०
१९५६–५७ . .	१०,१००	..	१०,१००
१९५७–५८ . .	४३,६००	२६,८४,४२९	२७,२८,०२९
१९५८–५९ . .	६२,५००	८,३३,६५०	८,९६,१५०
१९५९–६० . .	६६,३००	४,५२,१७५	५,१८,४७५
१९६०–६१ . .	७२,९००	५,००,०००	५,७२,९००

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन रुजालय

†७७९. श्री सरजु पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल उत्तर प्रदेश में कितने परिवार नियोजन रुजालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन में से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने नागरिक-क्षेत्रों में हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सलाहकार बोर्डों के कितने सदस्य हैं; और

(घ) उनके क्या कार्य हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे के समुद्रगढ़ स्टेशन पर प्लेट फार्म

†७८०. श्री सुबोध हंसदा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के हावड़ा-कटुआ सेक्शन में समुद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय कब किया गया था;

(ग) क्या कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जून, १९६१ ।

(ग) हां ।

(घ) आशा है कि कार्य दिसम्बर, १९६२ तक समाप्त हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनमदुरै और विरुदनगर के बीच छोटी लाइन

†७८१. { **श्री उमा नाथ :**
श्री नम्बियार : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमदुरै और विरुदनगर के बीच छोटी लाइन के निर्माण का वास्तविक-कार्य सरकार कब आरम्भ करेगी;

(ख) इस कार्य को आरम्भ करने में, जिसका वचन बहुत पहिले दिया गया था, देर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार कार्य को कब पूरा करने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) इस लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी व अन्तिम स्थान-स्थिति सर्वेक्षण हो रहे हैं। सर्वेक्षण पूरा होने और लाइन के लिऐ अपेक्षित भूमि प्राप्त होने पर लाइन का वास्तविक निर्माण-कार्य आरम्भ होगा ।

(ख) कार्य संचालन में कोई देर नहीं हुई है ।

(ग) आशा है कि १९६३–६४ तक पूरा हो जायेगा ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४

†७८२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ के गलोल-रायगंज वाले भाग को पूरा करने के लिऐ क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ का गलोल-रायगंज वाला टुकड़े के लिऐ ५१.०५ लाख रुपये की लागत के काम स्वीकृत हो गये हैं और हो रहे हैं। लगभग २२.१० लाख रु० की लागत के बाकी कार्यों को स्वीकार करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

मोटर परिवहन के विकास के लिए राज्यों को रेलवेज से ऋण

†७८३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस किस राज्य को मोटर परिवहन के विकास के लिए रेलवेज़ से ऋण मिला है;

(ख) उन्हें कितनी धन राशि प्राप्त हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्यों द्वारा रेलों को कितना लाभांश दिया जायेगा; और

(घ) कितना लाभांश दिया जा चुका है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलों ने किसी राज्य को मोटर परिवहन के विकास के लिए ऋण नहीं दिया है। रेलवे ने मोटर परिवहन निगमों में, जो कुछ राज्यों ने मोटर परिवहन निगम, अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये थे, अंदाशन दिया था। मोटर परिवहन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इन निगमों को अपने वर्तमान रूप में कोई लाभांश नहीं देना पड़ता। रेलों और राज्य सरकारों पर अपने अपने पूंजी विनिमय पर निर्धारित प्रतिशत से ब्याज मिलता है। ब्याज की दर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निर्धारित करती है। पूंजीगत विनियोग का राज्यवार ब्यौरा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोर्टल्लम में पर्यटक सुविधायें

†७८४. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में कोर्टल्लम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त स्थान पर पर्यटकों के लिए सुविधायें देने की कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, उसका क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू के मूल्य निर्धारित करना

†७८५. **श्री कार्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या तम्बाकू उत्पादकों को उनकी फसल का उचित मूल्य पाने का आश्वासन देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़

†७८६. **श्री कार्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार और जलपाइगुड़ी जिलों को 'तोरशा' नदी की बाढ़ और भूमि कटाव से बचाने के लिए इस नदी को नियंत्रित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) हां ।

(ख) ब्यौरा निम्न है :—

	योजना का नाम	प्राक्कलित लागत
(१)	जलपाईगुड़ी जिले में हासीकारा रेलवे पुल से राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ तक 'चार तोरशा' के बायें किनारे पर पुश्ता बनाना ।	१०८.०० लाख रु० ।
(२)	कूच बिहार के पास हंसखवा रजड़घाट की सुरक्षा	१५.६८ लाख रु० ।

कूच बिहार में नया मेडिकल कालिज

†७८७. **श्री कार्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में कच-बिहार में एक नया मेडिकल कालिज खोलने का प्रस्ताव संघ सरकार के समक्ष रखा है;

(ख) इस प्रस्ताव के बारे में संघ सरकार का क्या मत है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोई आर्थिक सहायता देने पर सहमत हो गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). कूच-बिहार में नया मेडिकल कालिज खोलने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। भारत सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही उस पर विचार कर सकती है ।

भारतीय केन्द्रीय जुट समिति

†७८८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय केन्द्रीय कर जूट समिति ने जूट की उत्पादन-लागत के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई उप-समिति नियुक्त की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : हां। भारतीय केन्द्रीय जूट समिति ने जूट की उत्पादन-लागत का सर्वेक्षण करने में सामने आने वाली टैक्निकल बातों पर उन्हें सलाह देने और योजना की प्रगति की जांच करने के लिए एक टैक्निकल उपसमिति नियुक्त की है। भारतीय केन्द्रीय जूट समिति का आर्थिक अनुसन्धान विभाग सर्वेक्षण करेगा।

डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†७८९. डा० मेलकोटे : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पूना, अहमदाबाद और मदूरै में डाक व तार विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पांच वर्ष से अधिक से सरकारी क्वार्टर पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितने क्वार्टर बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) निर्माण प्रोग्राम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]

टेलीग्राफिस्ट और टेलीग्राफ मास्टर

†७९०. डा० मेलकोटे : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने टेलीग्राफिस्ट्स और टेलीग्राफ मास्टर्स हैं जिन्हें अपने पदों पर काम करते दो वर्ष से अधिक हो गये परन्तु अभी तक अस्थायी हैं;

(ख) १ अप्रैल, १९६२ को उपरोक्त श्रेणियों में सर्किलवार ऐसे कितने पद थे जो दो वर्ष से अधिक समय से अस्थायी थे; और

(ग) अस्थायी पदों तथा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

तार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता

†७९१. डा० मेलकोटे : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में (भारत में विभागीय तथा केन्द्रीय तारघरों में काम करने वाले) तार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) में काम करने का भत्ता देने पर कुल कितना व्यय हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में उपरोक्त तारघरों में अतिरिक्त समय भत्ते पर कितने घंटे काम हुआ; और

(ग) अतिरिक्त समय भत्तों पर व्यय में कमी करने और अधिक नियमित कर्मचारी रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायगी।

(ग) स्वीकृत कमी पूरी करने के लिये भर्ती हो गई है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डाक व तार विभाग में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता

†७९२. **डा० मेलकोटे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक व तार विभाग में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को, जब भी उनकी सेवाओं का सामान्य कार्य-समय से अधिक तक प्रयोग किया जाये, अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) स्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) पहिले केवल विदेशी डाक तथा रेलवे डाक सेवा में काम करने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता दिया जाता था। इसकी जांच करने के लिये एक विभागीय समिति बनाई गई है कि समूचे डाक व तार विभाग मे पर्यवेक्षी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों पर वेतन आयोग की सिफारिशें किस तरह लागू की जा सकती हैं। आशा है कि समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तारों का भेजा जाना

†७९३. **डा० मेलकोटे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ मार्च, १९६२ से ६ अप्रैल, १९६२ तक भारत वर्ष के विभिन्न तारघरों में टेलीप्रिंटर या 'मोर्स सर्किट' द्वारा तार भेजने के सामान्य साधनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से कितने तार भेजे गये ;

(ख) १ से २८ फरवरी, १९६२ तक ऐसे कुल कितने सन्देश भेजे गये ; और

(ग) प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सन्देशों को भजने के लिये कितने अधिसमय व्यक्ति-घंटे काम किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपमिश्रण निरोधक उपाय

†७६४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अपनाये गये अपमिश्रण-विरोधी उपायों का प्रभाव जानने का कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपमिश्रण के विरुद्ध राष्ट्रीय आकस्मिकता के आधार पर कार्यवाही करने के लिये कोई निश्चित नीति बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) वर्ष १९६० में विभिन्न राज्यों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ का प्रवर्तन, जांचे तथा अपमिश्रित पाये गये खाद्य के नमूनों, चलाये गये अभियोगों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर जुर्माना हुआ या जिन्हें सजा हुई, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]**

(ग) और (घ). सरकार खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिये निरन्तर प्रयत्न करती रही है । योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने इस बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने की कुछ सिफारिशें की हैं । उप-समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

भूमि का कृष्यकरण और वितरण

†७६५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में किये गये भूमि के कृष्यकरण का सह-सम्बद्ध अध्ययन करने का प्रबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी भूमियां कृषि योग्य बनाई गईं ;

(ग) क्या ये भूमियां भूमिहीन कृषकों को दे दी गई हैं ; और

(घ) इन भूमियों से उत्पादन तथा आय में वृद्धि के रूप में क्या लाभ हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (घ). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन डायरैक्टरी

†७६६. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम टेलीफोन सर्किल की टेलीफोन डायरैक्टरी अन्तिम बार कब छापी गई थी ; और

(ख) उनको बिल्कुल ठीक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) आसाम सर्किल के लिये टेलीफोन डायरैक्टरी (समस्त सर्किल के लिय एक) अन्तिम बार १९५९ में छापी गई थी।

(ख) काम हो रहा है और आशा है कि अगला संस्करण जून १९६२ में छप जायेगा।

केरल में 'कार्ड रेलवे लाइन' का निर्माण

†७६७. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनालूर और तिरुवल्ला अथवा पुनालूर और चेंगानूर को मिलाने वाली कार्ड रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण किया गया था तथा प्राक्कलन बनाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन कब बनाये गये थे और प्राक्कलित लागत क्या थी ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों के निर्माण के कार्यक्रम में इस लाइन को शामिल न करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) क्योंकि नई लाइनों के निर्माण के लिये उपलब्ध धन बहुत सीमित है।

ब्यास बांध परियोजना

†७६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास बांध परियोजना के लिये जलाशय का निर्माण करने के लिये कितने गांवों को नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) वहां पर एक उपनगर बनाने के लिये कितने गांवों को हट जाने के नोटिस दिये गये ; और

(ग) अब तक उपरोक्त कार्यों के लिये क्रमशः कितने गांवों को हटा दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: (क) से (ग). **जलाशय के लिए :** अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा न ही किसी गांव को हटाया गया है। आशा है जून १९६३ से आदमियों को हटाया जायेगा।

उपनगर के लिए : ११ गांवों की भूमि ले ली गई है। इन गांवों की आबादी ऐसे ही रहेगी।

पठानकोट रेलवे स्टेशन

†७६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पठानकोट रेलवे स्टेशन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पठानकोट रेलवे स्टेशन की वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं तथा इस समय और सुधार करने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यमुना पर पुल

८००. {**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना पर बहुत शीघ्र ही दो नये पुल बन कर तैयार हो जायेंगे और इन पुलों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पुलों के न बनने से यातायात व्यवस्था में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) ये दोनों नये पुल कब से चालू हो जायेंगे और कहां बनाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन में ऐसे भी कोई पुल हैं जो बरसात में चालू नहीं रह सकेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो उस समय के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]**

कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन पर गोदाम और यात्री शेड

८०१. {**श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर सैक्शन में कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन पर गोदाम और यात्रियों के लिये शेड बनाने की योजना के कार्यारम्भ में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये रेलवे मंत्रालय ने कितनी धनराशि निश्चित की थी ; और

(ग) अभी तक कार्य न आरम्भ होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) कुलपहाड़ स्टेशन पर माल गोदाम, माल प्लेटफार्म और पहुंच-मार्ग बनाने की मंजूरी दे दी गई है और काम हो रहा है। प्लेटफार्म पर छत डालने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(ख) १,२२,६०८ रु० ।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

देश में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

†८०२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र हैं ; और

(ख) ऐसे केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में ७२ संस्थायें हैं और १९६१-६२ तक इन संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता १,७२,९०० रुपय थी ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†८०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में समुद्र द्वारा कटाव को रोकने के लिय भारत सरकार में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के उप-निदेशक के सुझावों का अध्ययन कर लिया है तथा उन को क्रियान्वित करने के लिये इच्छुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) और (ख). उप-निदेशक ने समुद्र के किनारे के कटाव तथा उस से संरक्षण के विषय पर इंगलैंड में प्रशिक्षण लेकर १९ अप्रैल, १९६२ को कार्यभार संभाला है । उन्हों ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । उन का प्रतिवेदन मिल जाने पर उनमें दिये गये सुझावों पर विचार होगा और केरल में समुद्र के कटाव को रोकने के लिये आवश्यक समझे जाने पर उन का उपयोग किया जायेगा ।

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†८०४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की समस्या इतनी विषम हो गई है कि इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) समुद्र तटीय भूमि के कटाव की समस्या ने केरल में तीव्र रूप धारण कर लिया है और महाराष्ट्र में इस की तीव्रता कुछ कम है ।

(ख) केरल राज्य में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही अर्थात् समुद्र के किनारे दीवारें और लकड़ी के जंगलों के निर्माण का कार्य पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार (भूतपूर्व ट्रावनकोर-कोचीन रियासत) द्वारा प्रारंभ किया गया था । यह कार्य दूसरी योजना में भी जारी रहा और चालू योजना की अवधि में उसे और भी तेज़ कर दिया गया । समुद्री कटाव को रोकने की योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने के लिय ३६० लाख रुपये की व्यवस्था तीसरी योजना में की गई है । जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने राज्य की सीमा में कुछ स्थानों की समुद्री कटाव की समस्या को केन्द्रीय जल और विद्युत् गवेषणा केन्द्र पूना को निर्दिष्ट किया है और उन से परामर्श मांगा है ।

फेफड़ों का कैन्सर

८०५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के एक डाक्टर ने यह सिद्ध किया है कि डिजेल-इंजन का धुआं स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध होता है और इस से फेफड़ों का कैन्सर हो जाता है ; और

(ख) क्या सरकार इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित ब्रिटिश डाक्टर की रिपोर्ट नहीं देखी है । यह सच हैं कि धुआं और स्माग, जो वायु को दूषित करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं । तथापि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि डिजेल-इंजन के धुएं से फेफड़ों का केन्सर होता है ।

भारतीय नाविक

†८०६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६४०० भार टन मालवाहक जहाज 'विश्व निधि' में काम करने वाले दो भारतीय नाविक जहाज में १०० पौंड कच्ची अफीम मिलने पर शनिवार २१ मार्च, १९६२ को ब्रिटिश पुलिस तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा इंग्लैंड में टिलबरी नामक स्थान पर गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां । जहाज 'विश्व निधि' में काम करने वाले दो नाविक––सर्वश्री दित्ता बूडिया और पुरुषोत्तम भगवान ––पर गैर-कानूनी रूप से १०२ पौंड १२ औंस कच्ची अफीम रखने का आरोप लगाया गया था और ब्रिटिश पुलिस तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा ३१ मार्च, १९६२ को टिलबरी इंगलैंड में उन्हें गिरफ्तार किया गया । आरोप स्वीकार करने पर नाविकों को स्थानीय न्यायालय द्वारा २ अप्रैल, १९६२ को ६ महीने की कैद की सजा दी गई थी ।

(ख) चालू नियमों के अनुसार सम्बन्धित नाविकों का पंजीयन स्थायी तौर पर रद्द करने या किसी निश्चित अवधि के लिए निलम्बित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

कैन्सर के कारणों के बारे में रिपोर्ट

†८०७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रायल कालेज आफ़ फ़िज़ीशन्स की कैंसर के कारणों के बारे में प्रामाणिक रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार ने प्राप्त की है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने उस का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हैं और क्या विशेषज्ञों ने इस दिशा में कुछ सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) फेफड़ों के कैंसर तथा अन्य बीमारियों और धूम्रपान के परस्पर सम्बन्ध के बारे में उक्त कालेज की रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार ने प्राप्त की है।

(ख) से (घ). विशेषज्ञों ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है। उस में सिफारिश की गई है कि निम्न उपाय किये जा सकते हैं:—

(१) जनता और विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को धूम्रपान से उत्पन्न खतरे के बारे में शिक्षा देना;

(२) बच्चों को तम्बाकू बेचने पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण लगाना;

(३) तम्बाकू के विज्ञापन पर नियंत्रण;

(४) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर व्यापक नियंत्रण;

(५) सिगरेट पर कर मे वृद्धि और संभवतः पाइप और सिगरेट के तम्बाकू पर कर का उस से समायोजन;

(६) सिगरेट के धूएं, टार और निकोटीन तत्व के सम्बन्ध में विक्रेताओं को जानकारी देना;

(७) धूम्रपान को छोड़ने में जो व्यक्ति कठिनाई अनुभव करते हैं, उन्हें सहायता देने वाले तम्बाकू विरोधी अस्पतालों के महत्व की जांच।

सरकार ने निम्न कार्यवाही की है:—

(१) भारत के एक राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल में १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किसी भी रूप में तम्बाकू रखने और खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(२) सिनेमाघरों और ट्रामों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध है।

(३) प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा रही है। भारत सरकार ने अनेक पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं जिन में कैंसर के खतरे और शुरू में ही कैंसर का पता लगाने की ओर प्रकाश डाला गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने देश में कैंसर विरोधी आंदोलन के एक अंग के रूप में निम्न फिल्में तैयार की हैं:—

(१) 'फ्रॉम वन सेल' (एक कोष्ठ से)

(२) 'क्रूसेड' (धर्मयुद्ध)

(३) 'प्राबलेम ऑफ़ फियर्स डायग्नासिस' (रोग निदान की समस्या)

(४) 'सेव दीज़ लाइव्स' (इन प्राणों की रक्षा कीजिये)।

दिल्ली में चिड़ियाघर

८०८. { श्री भक्त दर्शन:
श्री वी० चं० शर्मा:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में चिड़ियाघर की स्थापना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और उस पर कितना धन व्यय हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका निर्माण कार्य पूर्णतया सम्पन्न करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) (१) पशुओं के कटघरे बनवाने, अन्य कार्य और सेवाओं के सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति निम्न प्रकार है :—

(क) निम्न कार्य पूरे किये गये हैं :—

पशु-कटघरे: ३० (एशियाई, अफरीकी और आस्ट्रेलियाई अनुभागों में)

अन्य कार्य: १. सुन्दर नगर के साथ और पिछली तरफ तथा बोटानिकल पार्क क्षेत्र के चारों ओर चार दीवारी

२. मुख्य द्वार, सहायक द्वार तथा टिकट घर

३. प्रशासन ब्लाक

४. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये २४ क्वार्टर

५. अधीक्षक का बंगला

६. छः इन्च की शुद्ध और कच्चे पानी की तथा दो इन्च की कच्चे पानी की लाइनें डलवाना

७. शुद्ध और कच्चे पानी के वितरण की लाइनें डलवाना

८. गन्दे पानी की भूमिगत लाइनें डलवाना

९. पानी निकालने के लिए पम्प लगाना

१०. नालियां तथा पानी की खाइयां

११. शिलाशीर्ष पुलियायें

१२. हाथियों के लिए पांच चबूतरे

सेवायें : १. कर्मचारियों के क्वार्टरों को जाने वाली सड़क पर रोशनी लगाना ।

२. गाड़ियां खड़े करने के स्थान तथा पैदल चलने वालों के रास्ते (केवल वर्तमान आवश्यकता के लिए)

३. सड़कें

४. खाद्य भंडार तथा रसोई के ब्लाक

५. चार आराम गृह

६. जलपान गृह

७. साइकिल स्टेन्ड

(ख) निम्न कार्यों में काम चालू है :—

सेवायें : (१) १. पशु चिकित्सालय और संगरोध केन्द्र

२. सड़कों का बिजलीकरण

(२) ३०-४-१९६२ को प्रदर्श की संख्या निम्न प्रकार थी :—

स्तनधारी	संख्या	४२२
पक्षी	संख्या	८०९
रेंगने वाले	संख्या	४
मछली	संख्या	६९
स्थल जलचर	संख्या	२
कुल		१३०६

(३) लगभग ८५ एकड़ भूमि क्षेत्र का विकास किया गया है।

(४) एक बोटानिकल पार्क बनाने का विचार छोड़ दिया गया है और इस से बची भूमि को चिड़ियाघर के विकास के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

(५) ३१-३-६२ तक व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :—

राजस्व	२२.३० लाख रुपये
मूलधन	४०.८४ लाख रुपये
कुल	६३.१४ लाख रुपये

(ख) दिल्ली चिड़ियाघर के निर्माण का कार्य केन्द्रीय निर्माण विभाग के हाथ में है जिसने इस कार्य के लिये विशेष कर्मचारी लगाये हुए हैं। निर्माणों के डिजाइन और उनको बनवाने का कार्य पार्क के अधीक्षक के परामर्श से किया जाता है। छोटे छोटे कार्य जिनकी लागत ५,००० रुपये से अधिक नहीं होती, विभागीय तौर से दिल्ली चिड़ियाघर के अधीक्षक द्वारा किये जाते हैं। सरकार ने इस परियोजना के विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए अफसरों और गैर-अफसरों की "दिल्ली जुलोजिकल पार्क कौन्सिल" नाम की एक सलाहकार निकाय की स्थापना की है। इस कौन्सिल की सहायता के लिये दो तकनीकी समितियां हैं अर्थात् निर्माण समिति और बोटानिकल समिति, जोकि कार्यों की प्रगति का पर्यवेक्षण समय समय पर करती हैं।

ग्राम सभाएं

†८०९. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चशक्ति प्राप्त अध्ययन दल स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि वह ऐसी कार्यवाही के सुझाव दे सके जिससे कि ग्राम सभाएं ग्रामस्तर पर स्वायत्त निकायों के रूप में काम कर सकें;

(ख) क्या इस के लिए रूपरेखा बना ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ?

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिये कदम सुझाने के लिए एक अध्ययन दल स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में भूमि विकास

†८१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पाइपों की उपलब्धता में कठिनाई के कारण दिल्ली में कृषि और शहरी भूमि के विकास में काफी बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कर्मचारियों की आम हड़ताल

†८११. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामले अभी विचाराधीन हैं, जिन्हें १९६० में हड़ताल में भाग लेने के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त कर दिया गया था ;

(ख) ऐसे कर्मचारी कितने हैं ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ; और

(घ) कितने कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) एक---महाप्रबन्धक को दयायाचिका दी गई है। दो--निम्न न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद कर्मचारी पदच्युत कर दिये गये थे। एक----महाप्रबन्धक द्वारा सेवा से हटा दिया गया था, रेलवे बोर्ड के पास की गई अपील विचाराधीन है।

सात---कर्मचारियों ने महाप्रबन्धक को पुनरीक्षण याचिकाएं दी थीं जिन्हें रेलवे दर न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जा रहा है।

(ग) ये मामले विचाराधीन हैं और एक निर्णय यथा संभव शीघ्र किया जायेगा।

(घ) २८-२ १९६२ को १३।

केरल में शोलयार परियोजना

†८१२. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने शोलयार परियोजना को पूरा करने के लिए जो विदेशी मुद्रा मांगी थी, उसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)**:(क) और (ख). शोलायार परियोजना के लिए बिजली पैदा करने वाली मशीनें, बटरफ्लाई वाल्व, रेडियल गेट, डिस्चार्ज से रेगुलेटर, केबलवे, इन्टेक गेट, हायस्ट, आपतकालीन गेट और हायस्टों की आयात के लिए ४८,५१,९८२ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है । स्विचगियर, बिजली ट्रांसफार्मर और रेत साफ करने वाले संयंत्रों के आयात के लिए २१,९६,१३९ रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

†८१३. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति की इस सिफारिश को, जो उस ने अपनी तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में की थी, मान लिया है कि सरकार वार्षिक राज्य योजनाओं की जांच और प्रतिवर्ष लक्ष्यों की जांच के लिए सुपारी सम्बन्धी केन्द्रीय पर्यवेक्षक निकाय को पुनर्गठित करे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

केरल में पीने का के पानी का संभरण

†८१४. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में ताजे पानी के वितरण के लिए कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) केरल सरकार ने क्या मांग की थी ; और

(ग) कितनी योजनाएं शामिल हैं और कितने ग्रामों को लाभ पहुंचेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) 'स्वास्थ्य' क्षेत्र के अन्तर्गत केरल की तीसरी योजना में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिए ५० लाख रुपये और ४०७ लाख रुपये शहरी योजना के लिए रखे गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया था कि शहरी योजनाओं के लिए ६०६ लाख रुपये और २२५ लाख रुपये ग्रामीण योजनाओं के लिए रखे जायें।

(ग) केरल की तीसरी योजना में १४ शहरी जल संभरण योजनाएं चालू की जायेंगी। ग्रामीण योजनाओं की सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

इन्द्रावती और गोदावरी नदियों के संगम पर बांध

†८१५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्रीमती मैमूना सुलतान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस तरीके से आन्ध्र प्रदेश सरकार इन्द्रावती और गोदावरी के संगम पर एक बहुप्रयोजनीय बांध बनाने का विचार कर रही है, उस के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने गुलाटी आयोग के सामने विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विरोध किस प्रकार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने गुलाटी आयोग को एक अभ्यावेदन भेजा है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावित इनामपल्ली बांध द्वारा कुछ क्षेत्रों के पानी में डूब जाने के बारे में है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और कोई परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई।

पेट के व्रण का इलाज

८१६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर को ज्ञात है कि रूस के शरीर विज्ञानाविद श्री ईवान पवलोव के शिष्य सर्वश्री कोन्स्तान्त्रि वैपकोव तथा ईवान कुर्प्तिन ने पेट के व्रण (अल्सर) के सम्बन्ध में नवीन सिद्धान्त के स्टिको विसेरल का प्रतिपादन किया है तथा इसके निराकरण निमित विशेष प्रकार के भोजन पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस चिकित्सा का वास्तविक रूप क्या है तथा क्या उसका प्रयोग भारत में किया जायगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). जी नहीं। तथापि सूचना प्राप्त की जा रही है।

तिपटूर रेलवे स्टेशन पर पुल

†८१७. **श्री बासप्पा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि बंगलोर-पूना सेक्शन पर तिपटूर रेलवे स्टेशन पर एक ऊपर का या नीचे का पुल बनाया जाय ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर में बनाये जाने वाले रेलवे के पुलों की एक सूची भजी है ; और

(ग) क्या पग उठाये गये हैं और १९६२–६३ में कौन से पुल बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार के सड़कों के कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान रेलवे फाटकों के स्थान पर बेल्लारी (मील २०३-१८–१९, बीजापुर (मील ११४/३–४), बेलगाम (मील ३१/१२-१३) और गिवीगरा (मील १५३/२) पर दक्षिण रेलवे १९६२–६३ में ऊपर या नीचे के पुल बना रहा है । मोटे तौर पर रेलवे पुल बनायेगा और पुल तक जान के रास्ते राज्य सरकार बनायेगी शेष योजनाएं राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्राथमिकता बताये जाने और निर्माण कार्य में अपना हिस्सा देने पर क्रियान्वित करने के लिए बनाई जायेंगी ।

डीजल इंजनों का दक्षिण और पश्चिम भारत में भेजा जाना

†८१८. **श्री बासप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अड़चनों के कारण कोयल की कमी को देखते हुए सरकार सब डीजल इंजनों को दक्षिण और पश्चिम भारत में भेजने और अधिक डीजल इंजन खरीदने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या एच० ए० एल० कोच कारखाने या मद्रास के इन्टेग्रल कोच कारखाने में अधिक कोयल के डिब्बे बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । डीजलकरण कार्यक्रम मुख्यत: संचालन की आवश्यकताओं पर निर्भर होता है दक्षिण और पश्चिम भारत में कोयला सम्भरण की कठिनाइयां अस्थाई थीं और अब स्थिति ठीक है ।

(ख) आई० सी० एफ० और एच० ए० एल० को संसाधन यथासंभव डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग किय जायेंगे ।

मैसूर में बाढ़ नियन्त्रण

†८१९. **श्री बासप्पा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिये राज्य से कोई सहायता मांगी है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने कुछ राशि की मंजूरी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के कृषकों के लिये काम

†८२०. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम काम के मौसम में कृषकों को काम देने के लिये त्रिपुरा में केन्द्रीय सरकार की सहायता से परियोजनायें चालू की जानी हैं ;

(ख) यदि हां, तो एसे मौसम में अनुमानतया कितने कृषक बेकार हो जाते हैं और उन्हें किस हद तक इन परियोजनाओं में काम दिया जा सकेगा ; और

(ग) परियोजनाओं का कुल व्यय क्या है और केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :(क) ऐसी तीन परियोजनायें है, जिन में से एक १९६१-५२ में शुरू की जा चुकी है।

(ख) सर्वेक्षण के न होते हुये, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि १०,००० कृषकों को काम देने का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) प्रत्येक परियोजना के व्यय का अनुमान २ लाख रुपये है। पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी ।

आसाम में बाढ़ नियन्त्रण

†८२१. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार को राज्य में बाढ़ नियंत्रण योजनाओंको कोई सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) योजना में मुख्य परियोजना कौन कौन सी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

पर्यटन के महानिदेशक द्वारा विदेश यात्रायें

†८२२. **श्री राम नाथन चेट्टियार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में पर्यटन के महानिदशक कितनी बार विदेश गये, और उन्होंने किन किन देशों की यात्रायें कीं ;

(ख) उनकी प्रत्येक यात्रा में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी ; और

(ग) इन यात्राओं से देश में पर्यटन की उन्नति को कितनी सहायता मिली ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में अर्थात् १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च १९६२ तक पर्यटन के महानिदेशक ने विदेशों की निम्न यात्रायें की । प्रत्येक यात्रा के सामने व्यय किया गया विदेशी विनिमय दिखाया गया है :–

अवधि	जिन देशों की यात्रा की	व्यय की गयी विदेशी मुद्रा की राशि
१	२	३
सितम्बर, १९६०	अफगानिस्तान (काबुल)	२१७.१४ रु०
नवम्बर, १९६०	अर्जेंटाइना (ब्यूनस आयर्स)	२२९०.०० रु०
	युरुगुए (मौंट वीडिओ) ब्राजील (रियो डी जेनिरो) मेक्सिको (मेक्सिको) अमेरिका (न्यूयार्क) पुर्तगाल (एस्टोकिल) ब्रिटेन (लंदन)	नोट : न्यूयार्क में १० दिन ठहरन का दैनिक भत्ता अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन संघ की ओर से दिया गया ।
फरवरी, १९६१	थाईलैंड (बेंकाक)	१४५० रु०
अप्रैल, १९६१	अमरिका (न्यूयार्क)	कुछ नहीं । नोट : न्यूयार्क में महानिदेशक के ठहरने का व्यय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन संघ की ओर से दिया गया ।
सितम्बर, १९६१	नपाल	कुछ नहीं ।
अक्टूबर, १९६१	फ्रांस (कैन्स) जर्मनी (क्यूनिक)	३८७५ रु० लगभग
फरवरी, १९६२	स्विट्जरलड (जनवा) ब्रिटेन (लंदन)	४९४ रु० नोट : जेनेवा तक जाने और वहां से लौटन का कुल व्यय तथा जेनेवा में ठहरने का उनका दैनिक भत्ता संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से दिया गया ।
	योग	८९५७.०५ रु०

(ग) पर्यटन के महानिदेशक विदेशों में यात्रा तथा पर्यटन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलनों में भाग लेने के लिये गये । क्यों कि यह अनुभव किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा तथा पर्यटन सम्मेलन

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के अवसरों में वृद्धि करन का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने हैं । जिससे सभी सदस्य देशों को लाभ होता है तथा इससे यात्रा में दिलचस्पी रखने वाले सदस्य देशों के सम्पर्क से भारत में पर्यटन की वृद्धि होती है । अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी यात्रा संगठन संघ, अमेरिकन यात्रा एजेंट समिति के वार्षिक सम्मलनों में, सदस्य देशों के सरकारी पर्यटन विभागों के अलावा कई अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और व्यवसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं । इस से महानिदेशक को महत्वपूर्ण यात्रा एजेंटों, यात्रा संवद्धकों, विमान कम्पनियों के प्रतिनिधियों, यात्रा लेखकों और फोटोग्राफरों से मिलने और उन्हें भारत में पर्यटन के महत्व के स्थानों को बताने का अवसर मिलता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मलनों की यात्राओं के अवसर पर, पर्यटन के महानिदेशक ने दक्षिण अमरिका के कुछ देशों की यात्रायें की । यहां पर्यटन की प्रगति के लिये काफी गुंजायश है तथापि अभी तक किसी पर्यटन अधिकारी ने वहां की यात्रा नहीं की थी । १९६० में पर्यटन के महानिदेशक की यात्रा के पश्चात् से दक्षिण अमेरिका से यात्रियों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गयी है । १९५९ में दक्षिण अमरिका से ७८३ यात्री आये थे जब कि १९६१ में यह संख्या १८३३ थी । जिन चार देशों की यात्रा पयर्टन के महानिदेशक ने की थी अर्थात् ब्राजील, अर्जेंटाइना, मैक्सिको और युरुगुये से यात्रियों की संख्या तीन गुनी हो गई ।

इस अवसर पर पर्यटन के महानिदेशक ने विदेश स्थित भारत के पर्यटन कार्यालयों को भी देखा तथा बिना अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय किये बिना ही उनके संवर्द्धन संबंधी कार्यों का समन्वय किया ।

संयुक्त स्टीमर कम्पनियां[1]

†८२३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ और २९ नवम्बर, १९६१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त स्टीमर कम्पनियों का समस्त संरक्षण व्यय सरकारी अनुदानों और ऋणों से दिया जाता है ;

(ख) क्या कम्पनियां को भाड़े की दरों में ५०/० वृद्धि करने की स्वीकृति देने के उपरांत भी इस प्रकार के ऋण या अनुदान जारी रहेंगे; और

(ग) क्या कम्पनियों अपनी रक्षित निधियों को पुरान स्टीमरों को बदलने के कार्य में व्यय करने को तैयार नहीं हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । सन् १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में अनुदान इस उद्दश्य से दिये गये थे कि संयुक्त स्टीमर कम्पनियां संरक्षण संबंधी कार्य पर आंशिक व्यय की पूर्ति कर सकें । इस प्रयोजन के लिये कोई ऋण नहीं दिये गये ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि आगामी दो वर्षों तक इन अनुदानों को जारी रखा जाये । संरक्षण कार्य के लिये ऋणों को जारी रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है भाड़े की दरों में ५०/० वृद्धि

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Joint Steamer Companies.

की सिफारिश करते समय भाड़ा दर जांच समिति ने यह अनुमान लगाया कि नदी संरक्षण कार्यों के लिये दिया जाने वाला अनुदान उसी आधार पर दिया जाता रहेगा।

(ग) नकदी में उपलब्ध हो जाने वाली रक्षित निधियों का पुराने जहाजों को बदलने में उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे कालोनियों में रेलवे संस्थान और वाचनालय

†८२४. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बस्तियों की रेलवे सस्थानों और वाचनालयों के बिजली और पानी का व्यय सदस्यों से, जो कि रेलवे कर्मचारी हैं, से एकत्रित शुल्क से दिया जाता है ;

(ख) क्या इमारतों के मरम्मत और बगीचों के सधारण का व्यय भी सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है ; और

(ग) कर्मचारियों में अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिये रेलवे निधि का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) बिजली और पानी व्यय संस्था की निधि से दिया जाता है। सस्था की आय का साधन सदस्यता शुल्क और कर्मचारी कल्याण निधि है।

(ख) संस्था के इमारत की मरम्मत रेलवे राजस्व से की जाती है। बगीचों, खेल के मैदानों इत्यादि के संधारण का व्यय संस्था की निधि से दिया जाता है।

(ग) अनुदान कर्मचारी कल्याण निधि से दिया जाता है। यह राशि कर्मचारी कल्याण निधि समिति के स्वविवेक पर निर्भर करती है।

बीकानेर नगर में दुग्धशाला

८२५ **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और बीकानेर नगर (राजस्थान) के उत्तर पश्चिम में दुग्धशाला की स्थापना की योजना स्वीकार कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) और (ख). योजना आयोग ने ३७·७५ लाख रुपये की लागत से राठी, थरपारकर और संचार (कंकरेज) नस्ल के पशुओं के की योजना स्वीकृत की हैं। इस कार्य को बीकानेर के पश्चिमोत्तर में प्रवर्तन किया जायगा। यह सुधार योजना व्यय वित्त समिति की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही रही है।

योजना में (१) राठी क्षेत्र के ५०० खानाबदोश पशुपालकों के परिवारों के पुनर्वास (२) पशु उत्पादन के तीन क्षेत्रों में जल सम्भरण के सुधार के लिये कूओं और कुंडों का निर्माण तथा सुधार (३) प्रत्यक क्षेत्र में १०० सांडों का वितरण (४) नर तथा मादा बछड़ों का राजकीय सहायता द्वारा पालन (५) दूध घी तथा अन्य दुग्धोत्पादों की बिक्री की सुविधाओं का विकास और (६) पशुओं की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये पशु पदर्शनियों और मेलों का संगठन।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में बीकानेर में किसी दुग्धशाला की स्थापना की योजना नहीं है। दिल्ली दुग्ध-योजना बीकानेर के निकटवर्ती गांवों से गाय का दूध ले रही है।

बेलघरिया और सोदपुर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल

†८२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूर्व रेलवे में बेलघरिया और सोदपुर में रेलवे लाइनों के ऊपर एक ऊपरी पुल बनाने की प्रस्थापना रखी है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे लाइनें भारी यातायात और ऐसी बस सेवाओं के मार्ग से होकर जाती हैं, जो प्रतिदिन उपनगरों से बड़ी संख्या में यात्रियों को कलकत्ता या अन्य उपनगरों में ले जाती हैं;

(ग) क्या वहां कई बार यातायात बन्द कर देना पड़ता है; और

(घ) क्या उपनगरीय रेलवे मे भारी भीड़भाड़ को देखते हुए बस सेवाओं को सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ऊपरी पुलों को बनाने के कार्य को पूर्ववर्तिता दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) रेलवे के फाटक पर यातायात बहुत अधिक रहता है।

(ग) क्योंकि ये फाटक स्टेशनों के बहुत निकट हैं तथा उन स्थानों पर रेलवे तथा सड़क यातायात बहुत अधिक है अतः यातायात अधिकांश रोकना पड़ता है।

(घ) वर्तमान फाटकों के स्थान पर ऊपरी या नीचे के पुलों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, यद्यपि पश्चिम बंगाल में अस्थायी रूप से तीसरी योजना में इन दोनों योजनाओं को शामिल कर दिया है तथापि उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना अन्तिम निर्णय नहीं बताया है कि वे इस वर्ष इसे अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे यद्यपि इस विषय पर कई स्मरण-पत्र भेजे जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में पीने के पानी का संभरण

†८२७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने पश्चिम बंगाल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अभी तक नगरपालिकाओं को पीने के पानी का सम्भरण करने के लिये कितनी राशि प्रदात्त की है ; और

(ख) चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल की नगरपालिकाओं को जहां मजदूर बस्तियों, शरणार्थी बस्तियों और जनसंख्या का अत्यधिक जमाव होता जा रहा है, सुरक्षित जल सम्भरण करने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है, उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीकानेर डिवीजन में नये स्टेशनों के लिये इमारतें

†८२८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में अगले वर्ष कितने पुराने स्टेशनों के भवनों को तोड़ कर उनकी जगह नये स्टेशन भवन बनाने की योजना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये वर्तमान स्टेशन जो प्रसिद्ध गांवों से बहुत दूर पड़ते हैं उन स्टेशनों के नाम और स्थानों को बदलने की भी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्टशनों की ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दो।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर

†८२९. **श्री वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में, जिन्हें तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर से लाभ होने की सम्भावना है दुर्भिक्ष की अवस्था फैली हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के कार्य को तत्काल करने के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना का व्यय आंध्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न विकास ऋणों से पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिये विशेष अनुरोध किया जाने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म

†८३०. { **श्री वाजी** :
श्री चांडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में सूरतगढ़ की तरह एक बड़ा यन्त्रीकृत फार्म स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत योजना बना ली गयी है ; और

(ग) योजना की विशेष बातें क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ग). मध्य प्रदेश की सरकार ने यन्त्रीकृत फार्म की स्थापना के लिये बेतूल जिले में एक स्थान का सुझाव दिया था। बड़ पैमाने के यांत्रिक फार्मों की समिति इस पर विचार कर रही है । समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय करेगी ।

रेलवे के लिये कोयला खरीदने की नीति

†८३१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये कोयला खरीदने की नीति क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड का मुख्य खान सलाहकार, इंजिनों के बुनियादी आर्डरों की देखभाल करता है, तथापि रेलवे की आपतकालीन आवश्यकता के लिये कोयला नियन्त्रक पहिले की तरह से ही कार्य करता है ।

(ग) यदि हां तो इस प्रकार के विभाजन से क्या सहायता मिली है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) सरकार द्वारा किये गये एक नीति सम्बन्धी निर्णय के आधार पर रेलवे कोयला नियन्त्रक के परामर्श से कुछ कोयला खानों का नाम निर्देश कर देती है तथा सम्भरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में ठेके कर सीधे उनसे कोयला मंगाती है। यह व्यवस्था अभी गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों तक ही सीमित है लेकिन हमें शीघ्र ही सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में भी विस्तृत किया जायेगा।

(ख) जी हां, रेलवे बोर्ड के मुख्य खनन सलाहकार, कोयला नियन्त्रक के द्वारा मंजूर किये गये कुल कोटे से कोयले की किस्म और प्रकार के अनुसार दिशावार और क्षेत्रवार मासिक आधार पर इंजिनों के लिये कोयला कार्यक्रम बनाता है । रेलवे की आवश्यकता के लिये कोयले की अतिरिक्त राशि, जिसकी आपातकाल में उन्हें आवश्यकता हो, अथवा उन क्षेत्रों के लिये जहां कोयला पहुंचाने में कमी हो गयी, भेजने के लिये कोयला नियन्त्रक से मंजूरी लेनी होती है ।

(ग) रेलवे बोर्ड के कोयला नियन्त्रक और मुख्य खनन सलाहकार के बीच जिम्मेदारी का कोई विभाजन नहीं हुआ है । सभी उपभोक्ता, जिनमें रेलवे भी शामिल हैं, कोयला नियन्त्रक द्वारा स्वीकृत कोटे के भीतर से सामान्य व्यावसायिक साधनों से कोयला प्राप्त करते हैं । आपातकाल में कोयला नियन्त्रक रेलवे को अन्य उपभोक्ताओं की भांति विशेष राशि देकर सहायता करता है।

मनीपुर को दुग्ध चूर्ण का आवंटन

†८३२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९ में राज्य व्यापार निगम द्वारा मनीपुर प्रशासन को ५० टन दूध का पाउडर दिया गया था ;

(ख) क्या प्रशासन ने दुग्ध चूर्ण की इस राशि को कलकत्ता से उठवा कर मनीपुर में वितरित कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो यह दुग्ध चूर्ण किस प्रकार वितरित किया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो दुग्ध चूर्ण कब और कहां बांटा गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ). जनकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे यथासमय सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर राज्य परिवहन

८३३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन के पास कितनी गाड़ियां हैं ;

(ख) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में मनीपुर राज्य परिवहन की आय और व्यय क्या था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मनीपुर राज्य परिवहन के विस्तार की क्या योजनायें हैं ;

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १३९ (जिनमें वे ७ गाड़ियां भी शामिल हैं जिनका ढांचा बनाया जा रहा है) ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

वर्ष	आय	राजस्व	पूंजी व्यय
१९६०–६१. .	११६३३४७ रु०	१८२७०८५ रु०	७६००८५ रु०
*१९६१–६२ .	१३४८२९९ रु०	१७२३५०९ रु०	४००५७२ रु०

(*वर्ष १९६१–६२ के आंकड़े अप्रामाणिक हैं)

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित करने के लिये मनीपुर राज्य परिवहन ने निम्नलिखित योजना बनाई है :

(१) इम्फाल नगर और ६ नये मार्गों पर चलाने के लिये ४१ लाख की अनुमानित लागत से १०० गाड़ियों की खरीद ।

(२) ५ लाख की अनुमानित लागत से कर्मचारियों के क्वार्टर और विश्राम भवनों का निर्माण ।

(३) १.६३ लाख की कीमत की मशीनों और सन्यन्त्र की खरीद ।

विजयवाड़ा और मछेरला के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

†८३४. श्री यलमंदा रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुना सागर परियोजना के महत्व को देखते हुए विजयवाड़ा और मछेरला के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय गृह

†८३५. श्री यलमंदा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना की उच्चस्तरीय नहर के दूसरे प्रक्रम को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो कब, और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यह प्रस्ताव किया गया है कि दूसरे प्रक्रम को पहिला प्रक्रम समाप्त होने पर लिया जाये । पहिला प्रक्रम तीसरी परियोजना के अन्त तक समाप्त होगा ।

तीसरी योजना में मध्यप्रदेश के लिये नई रेलवे लाइन

†८३६. **श्री दाजी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के दौरान में मध्यप्रदेश राज्य में नई रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में उस राज्य से क्या प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) तीसरी योजना के लिये कौन सी नई रेलवे लाइनों के लिये स्वीकृति दी गई है तथा उन को सम्मिलित किया गया है; और

(ग) किन लाइनों के बारे में विचार हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]**

(ख) निम्नलिखित नई रेलवे लाइन जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मध्यप्रदेश में हैं तीसरी योजना में रेलवे कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं :—

	मील
१. गुना (रोथियाई)—शाजापुर . मक्सी (बी० जी०)	१२०.१४
२. सिंगरौली–ओबरा (बी० जी) .	३६.००
३. बेलादिल्ला-मोहावाल्सा (बी० जी०) . .	२७०.००

(ग) अमला-परसिया (बी० जी०) को सिरगोरा तक बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है . ६.००

त्रिपुरा में मोटर दुर्घटनाएं

†८३७. **श्री दशरथ देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के दौरान में त्रिपुरा में कुल कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) कितनी दुर्घटनाओं में जनहानि हुई ;

(ग) ग्रस्त व्यक्तियों एवं उन के परिवारों को किस प्रकार का प्रतिकर दिया गया ; और

(घ) कितने मामलों में ड्राइवरों को अदालत द्वारा सजा दी गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादर)** : (क) से (घ). वांछित जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से मांगी गई है और जैसे ही वहां से उत्तर मिलेगा सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिपुरा में धान के लिये भूमि

†८३८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन का विचार त्रिपुरा के सोनामुरा खंड के धालियाजाला नामक स्थान पर धान के लिये भूमि लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस का प्रभाव कितने कृषकों पर पड़ेगा ;

(ग) क्या भूमि को लेने के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग १७७ परिवार ।

(ग) जी हां त्रिपुरा प्रशासन को अभ्यावेदन मिले हैं ।

(घ) अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

त्रिपुरा-अगरतला मालवाही विमान सेवा

†८३९. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के व्यापारियों की ओर से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कोई अभ्यावेदन मिला है जिस में उन्हों ने कहा है कि त्रिपुरा से तथा त्रिपुरा को सामान ले जाने तथा लाने के लिये अधिक मालवाही विमान दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) निगम ने बताया है कि उस के पास जनवरी फरवरी १९६२ में अस्थायी तौर पर मालवाही जहाजों की कुछ कमी थी । फिर भी निगम ने अपनी यथाशक्ति कलकत्ता/अगरतला की मांगों को पूरा करने के लिये प्रयत्न किया । आसाम क्षेत्र में कुछ गैरसरकारी हवाई समवायों द्वारा कुछ भागों में वायु सेवा चालू करने के लिये 'कोई आपत्ति नहीं', सर्टीफिकेट जारी कर दिये गये हैं । निगम ने यह भी बताया है कि अप्रैल १९६२ के दूसरे सप्ताह से त्रिपुरा के लिये वायुसेवा कुछ कम रही है किन्तु ९ अप्रैल १९६२ के बाद से हर मांग की पूर्ति की जाती रही है ।

बालासोर से नीलगिरि तक रेलवे लाइन

†८४०. **श्री जेना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले युद्ध में बालासोर से नीलगिरि तक रेलवे लाइन बनाने के लिये उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिये जमीन ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राप्त की गई भूमि के मालिकों को प्रतिकर दे दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो प्रतिकर कब दिया गया था ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी) :(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय ने साइडिंग के लिये भूमि पिछले युद्ध में अधिग्रहण की थी और शत्रुता की समाप्ति पर रेलवे को दे दी गई। रेलवे ने दिसम्बर, १९५९ में भूमि प्राप्त की थी ।

(ख) से (घ). प्रतिकर का भुगतान करने के लिए ६६,२०२.०४ रु० जिला बालासोर के विवेक पर छोड़े गये थे। २९,८८५.६९ रु० का प्रतिकर का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। यह भुगतान जमीन मालिकों को बालासोर के भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने किया है। शेष भुगतान करने के लिये असैनिक प्राधिकारियों को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि देय राशियों को अन्तिम रूप दें ।

दिल्ली में तकावी

८४१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में दिल्ली में कितने लोगों को तकावी दी गई ;

(ख) उस के आंकड़े विकास खण्डवार क्या हैं ; और

(ग) वह किन-किन मदों के अन्तर्गत दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :(क) २७,०७६।

(ख)

अलीपुर . .	७०१२	व्यक्तियों
कंझावला . . .	५९४१	व्यक्तियों
शाहदरा . . .	३४२७	व्यक्तियों
नजफगढ़ . . .	१०६९६	व्यक्तियों
	२७०७६	

(ग) १. कुंए खोदना
२. कुओं का बोरिंग करना
३. रहटें
४. ट्रैक्टरें
५. पम्पिंग सैट लगाना
६. नलकूपें
७. सिंचाई नालियां
८. चारा और बीज ।

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

८४२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध वितरण योजना द्वारा दिये जाने वाले दूध में भैंस का दूध कितनी डिग्री का है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गाय का कितने डिग्री का और टोन्ड कितनी डिग्री का होता है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के दूध का गाढ़ापन (२० डिग्री सेंटीग्रेड पर) निम्न प्रकार है :—

भैंस का दूध	१.०२८ से १.०३०
गाय का दूध . .	१.०२८ से १.०३०
टोन्ड दूध . .	१.०३१ से १.०३३

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

८४३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध वितरण योजना द्वारा कितना सूखा दूध तैयार किया जाता है; और

(ख) सूखे दूध का क्या उपयोग किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) १९६१–६२ वर्ष के अन्त तक, दिल्ली दुग्ध योजना के द्वारा लगभग १४० टोन्स (tonnes) स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाया गया ।

(ख) रोलर से सुखाई गई किस्म होने के कारण, यह दुग्ध चूर्ण बिस्कुट, आइसक्रीम बच्चों के खाद्य इत्यादि बनाने में उपयोग करने के लिए बेचा जाता है ।

बिनौले बोना

८४४. **श्री बड़े :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासन की यह नीति है कि विशिष्ट प्रकार के बिनौले विशिष्ट भूमि में ही या विशिष्ट राज्यों में ही बोना चाहिये;

(ख) क्या इस प्रकार के आदेश राज्य शासन ने (संघ राज्य-क्षेत्रों में) किसानों को दिये हैं;

(ग) क्या इस से किसान बिनौले बोना तथा रुई उत्पादन करना बन्द करेंगे या कम करेंगे; और

(घ) क्या यह आदेश मिल मालिकों के कहने पर संघ राज्य क्षेत्रों में सम्बन्धित प्रशासनों ने दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) इस विषय का सम्बन्ध प्रारम्भिक रूप मे राज्य सरकारों से है । कपास उगाने वाली राज्य सरकारें आमतौर पर विशेष स्थानों में खेती करने के लिए कपास की सुधरी विशेष किस्मों को कानून द्वारा निर्धारित करती हैं जिनके लिए वे किस्में सब से अधिक उपयुक्त पायी गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

पाल वाले जहाजों का विनाश

†८४५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर वर्ष १९५७ से प्राकृतिक आपदाओं या अन्य दुर्घटनाओं के कारण पाल वाले जहाजों के आंशिक या पूर्ण विनाश से प्रति वर्ष कितनी हानि हुई;

(ख) इस में से कितनी हानि सामान की थी और कितनी हानि जहाज़ की; और

(ग) बीमा से कितनी हानि पूरी हुई ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†८४६. श्री म० ना० स्वामी: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र नागार्जुन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में क्यों अपने हाथ मे नहीं लेती;

(ख) परियोजना किस तारीख तक पूरी हो जायेगी;

(ग) अब तक केन्द्र ने कितना ऋण दिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार निरन्तर केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगती रही है; और

(ङ) इस परियोजना में कौन से ताल्लुके और कितना क्षेत्र आता है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) "सिंचाई" राज्य की सूची में है (संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ में प्रविष्टि १७) । इस कारण सिंचाई की सारी परियोजनायें राज्य परियोजनायें हैं और पंचवर्षीय योजनाओं मे सम्मिलित किये जाने के, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है ।

(ख) संभव है कि परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य तक पूरी होगी ।

(ग) ४५.३२ करोड़ रुपये ।

(घ) नहीं ।

(ङ) स्वीकृत वर्तमान नागार्जुनसागर परियोजना से जिला गुन्टूर, कुरनूल और नेल्लोर में राइट बैंक कैनाल से और लेफ्ट बैंक कैनाल से नलगोण्डा, खमाम और कृष्णा जिलों में २०.६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जिसका व्यौरा निम्न है :—

(१) राइट बैंक कैनाल	९.७ लाख एकड़
(२) लैफ्ट बैंक कैनाल . .	७.९ लाख एकड़
(३) कृष्णा डेल्टा	३.० लाख एकड़

†मूल अंग्रेजी में

चेचक और छोटी चेचक[1]

†८४७. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी भाग के कुछ राज्यों/संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में चेचक तथा छोटी चेचक ने हाल में भयंकर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ प्रशासित राज्य/क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को यह रोग हुआ है और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस आपदा की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):** (क) और (ख). छोटी चेचक के रोगियों के विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह ध्यान देने योग्य रोग नहीं है। चेचक के बारे में उत्तरी भारत के राज्यों/संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचनाओं से पता लगता है कि केवल पंजाब में यह रोग अधिक फैला और अधिक मृत्युयें हुईं जबकि बाकी क्षेत्रों में अर्थात् बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में यह कम फैला और इस से मृत्युयें भी कम हुईं। १ जनवरी से ३१ मार्च तक वर्ष १९६१ और १९६२ के चेचक रोगियों तथा चेचक रोग से मरे व्यक्तियों के आंकड़े निम्न हैं :—

	१९६१ (१-१-६१ से ३१-३-६१ तक)		१९६२ (१-१-६२ से ३१-३-६२ तक)	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
बिहार	४०	११	४	—
पंजाब	३३८	७२	६१६	१३८
राजस्थान	१,५४१	३४६	१,०४३	२२७
उत्तर प्रदेश	१,४३२	३६०	१,०९६	३६९
दिल्ली	५०२	१२२	४१	६
हिमाचल प्रदेश	१२	३	९	—

(ग) राष्ट्रीय चेचक निवारण प्रोग्राम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६८८.९८ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने योजना को लागू करना आरम्भ कर दिया है और अन्य जल्दी ही लागू करेंगी।

अंगोल से हैदराबाद तक नई रेलवे लाइन

†८४८. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंगोल से हैदराबाद तक बरास्ता नागार्जुनसागर एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

†मूल अंग्रेजी में

1. Small Fox and chicken fox

(ख) यदि हां, तो मामला कहां तक पहुंचा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुन्टूर से नरसरावपेट तक (दक्षिण रेलवे) बड़ी लाइन

†८४९. **श्री म० ना० स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मचिलीपट्टणम–हुबली सेक्शन पर बड़ी लाइन को बढ़ाकर गुन्टूर से नरसरावपेट तक बढ़ाने का विचार है; और

(ख) क्या अब तक इस सम्बन्ध मे कोई अभ्यावेदन आया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं।

(ख) नहीं।

ओलवक्कोट जंक्शन पर शयन कक्ष

†८५०. **श्री प० कुन्हन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना मे ओलवक्कोट जंकशन पर शयन कक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ओलवक्कोट डिविजन के डी० आर० यू० सी० सी० को इस बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस स्टेशन पर दो शयन कक्ष बनाने का विचार है।

पश्चिम रेलवे में रेलवे की भूमि पर मोदी मिल

८५१. { **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत स्याहे रेलवे स्टेशन, नीम का थाना, की भूमि पर मोदी मिनरल ग्राइंडिंग मिल स्थापित की गई है;

(ख) क्या रेलवे मंत्री को गत वर्ष इस सम्बन्ध मे कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मिला था;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस अतिक्रमण को दूर करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) नीम का थाना ग्राम पंचायत के सरपंच, श्री नारायण सिंह, का प्रतिवेदन मिलने पर इस मामले की जांच की गयी और पता चला कि इमारत रेलवे की सीमा से सटकर रेलवे की जमीन से बाहर बनायी गयी है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे पर चक्रधरपुर में ऊपरी पुल

†८५२. **श्री ह० च० सोम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में चक्रधरपुर में मुख्य सड़क पर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल न होने के कारण गाड़ियों (मोटरों) आदि के आने जाने में भारी असुविधा होती हैं, प्राय घन्टों तक रुका रहता है और स्थानीय जनता ने कई बार रेलवे प्राधिकारियों से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसमें देर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). रेलवे फाटक ऐसे स्थान पर है जहां रेल और सड़क दोनों का यातायात बहुत है और इस कारण सड़क के यातायात में असुविधा होना अटल है । यह इस कारण होता है कि सुरक्षा और रेलगाड़ियों को निकालने की आवश्यकता होती है ।

रेल के फाटक के स्थान पर ऊपरी/निचला पुल की योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होती है । बिहार सरकार ने चक्रधरपुर में रेल के फाटक के स्थान पर सड़क के ऊपरी पुल की योजना की अस्थायी रूप से सिफारिश की है परन्तु अभी तक उनसे ऐसा कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें बताया गया हो कि वे किस वर्ष में इस कार्य को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकेंगे ।

चक्रधरपुर में काम करने वाले कुली व मजदूर

†८५३. **श्री ह० च० सोम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राजखर सावां-चक्रधरपुर क्षेत्र, राजखर सावां-नौआमण्डी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे जिला के अन्य भागों में भी इंजीनियर विभाग में पी० डब्लयू आई० के अधीन कुली व मजदूर प्रति मास पहिले सप्ताह में नियुक्त होते हैं और मासान्त मे नौकरी से हटा दिये जाते हैं और ये इन कुली व मजदूरों में से अधिकतर इसी प्रकार १० वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी मजूरी का क्या आधार है और वे कैसे निर्धारित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मजूरी दैनिक आधार दी जाती है जो असैनिक प्राधिकारियों के परामर्श से निर्धारित की जाती है ।

रेलों में स्थान रक्षित कराने की प्रक्रिया

†८५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में स्थान रक्षित कराने की असाधारण रूप से बड़ी प्रक्रिया के कारण व्यक्ति को काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कि यात्रियों को अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े कोई उपयुक्त प्रक्रिया बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) निश्चित प्रक्रिया काफी आसान हैं, यद्यपि भीड़ होने पर इन्तजार करना आवश्यक हो जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वन्य-पशुओं का परिरक्षण

†८५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य-पशुओं के परिरक्षण के लिये देश में जिनके समाप्त होने का भय है, क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने वन्य पशुओं की मिट रही नसलों के परिरक्षण के लिये निम्न कार्यवाही की है या करेगी :—

१. वन्य पशुओं की रक्षा करने के लिये देश भर में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जन्तु आश्रम बनाये गये हैं। आजकल देश में ऐसे ८३ उद्यान तथा आश्रम हैं। इन मे कुछ आश्रम विशेष कर बहुत कल मिलने वाले पशुओं के लिए हैं जैसे सिंहों के लिये गुजरात में गिर आश्रम, भारतीय गैण्डों के लिये असम में कडीरंगा आश्रम, और मनीपुर में बारह सिंगा (ब्राओं एन्टलीयर्ड डीयर) के लिये केवुल लमजाओं आश्रम/राज्यस्थान मे ग्रेट इण्डियन बास्टर्ड के लिये आश्रम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। कम पाये जाने वाले पशुओं को, जहां वे पाये जाते हैं, मारना मना है ।

२. भारत सरकार ने जीवित पशुओं को नमूने के तौर पर निर्यात करने पर और कम पाये जाने वाले पशुओं के बच्चों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाया है ।

(३) कुछ कम मिलने वाली नसल की सामयिक गणना संबंधित राज्य सरकारें उनकी संख्या का ध्यान रखने के लिये करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) भारत सरकार ने १९५२ में वन्य पशुओं के लिये एक भारतीय बोर्ड बनाया था और उसका उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अन्य पशुओं संबंधी सभी मामलों पर सलाह देना था। इस बोर्ड की एक सिफारिश के अनुसार सारे देश में प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहिले सप्ताह मे वन्य-पशु सप्ताह मनाया जाता है जिसमें रेडियो, प्रेस, सिनेमा-तख्तियों, बैठकों, इस्तिहारों पुस्तिकाओं और अन्य प्रचार सामग्री द्वारा वन्य पशुओं की रक्षा करने के उद्देश्य का प्रचार किया जाता है। राज्यों में वन्य-पशुओं के परिरक्षण की योजनायें, जैसे वन्य-पशु आश्रम, राष्ट्रीय उद्यान, आदि बनाना भी राज्यों की विकास योजनाओं मे शामिल की गई हैं। ऐसी योजनाओं के लिये केन्द्र से ५०% तक वित्तीय सहायता मिलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस विषय की राज्य-योजनाओं के लिये कुल २०९ लाख रु० का उपबन्ध है।

रेलों में उच्च श्रेणी के पद

†८५६. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९६०, ३१ मार्च, १९६१ और ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्षों में रेलों मे बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के पद खाली रहे ;

(ख) यदि हां, तो वे कब से रिक्त थे और वे किस किस श्रेणी के थे ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार रेलों में उच्च पदों पर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से काम लेती रही है ;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे खण्डों मे ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें उच्च पदों पर काम करने के लिए कहा गया है ;

(ङ) ये कर्मचारी उच्च पदों पर कब से काम कर रहे हैं और क्या उन्हें निम्न श्रेणी के के वेतन और उच्च श्रेणी के पद के वेतन के अन्तर की राशि दी गई है ; और

(च) रेलवे मंत्रालय ने 'पदोन्नति का नया कार्य' में घोषित श्रेणियों में श्रेणीवार कि.. उच्च श्रेणी के पद ऐसे हैं जो १ अप्रैल, १९५८, १ अप्रैल, १९५९, १ अप्रैल १९६० और १ अप्रैल, १९६१ को भरे न थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में सन्तरे और अनन्नास

†८५७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर में सन्तरे और अनन्नास बड़ी मात्रा मे होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या फलों के परिरक्षण की कोई योजनायें हैं ;

(ग) क्या पौदों तथा फलों को कीड़ों से बचाने की कोई योजनायें हैं ; और

(घ) मनीपुर में और मनीपुर के बाहर इन फलों के विपणन की क्या सुविधायें हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) हां।

(ख) एक फल परिरक्षण कारखाना और नौ फल-परिरक्षण केन्द्र खोले गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) हां। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक तथा मशीन, आदि ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर दिये जाते हैं।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कारों का निर्माण

†८५८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के अन्दर रेल कार बनाने का इरादा करती है ;

(ख) यदि हां, तो उनको कहां पर बनाने का विचार है ;

(ग) क्या इस समय प्रयोग में लाई जाने वाली रेल कारें विदेशों से मंगवाई जाती हैं ; और

(घ) क्या बनाने के वर्तमान प्रस्थापना के सम्य रेल कारों संबंधी अपने देश की मांग पूरी करना संभव होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी पेराम्बूर मे या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। हमे यही आशा है।

बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर टिन-शेड

८५९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन (गोरखपुर-बनारस लाइन) पर जो टिन शेड बनने वाला था वह हटा लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या तीसरे दर्जे के यात्रियों के ठहरने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई ओसारा बनाने की व्यवस्था की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५६-५७ में बेलथरा रोड स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत बनाने का विचार था, लेकिन इस्पात की कमी के कारण यह स्थगित कर देना पड़ा।

(ग) प्लेटफार्म पर छत बनाने की व्यवस्था अब १९६२-६३ के निर्माण कार्यक्रम मे की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल यातायात के लिये रेलवे में टेलीविजन

†८९०. { **श्री प्र० चं० बरुआः**
श्री सुबोध हंसदाः
श्री महेश्वर नायकः
श्री बिष्ण चन्द्र सेठः }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माल यातायात की गति को बढ़ाने के लिये एक बन्द सर्किट टेलीविजन प्रणाली चालू करने पर विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत आएगी ; और

(ग) इस संबंध मे अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)**: (क) नहीं, किन्तु मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड मे इसकी उपयोगिता और लागू किये जाने के संबंध मे अध्ययन करने का विचार है।

(ख) लगभग २०,००० रुपये।

(ग) प्रस्थापना की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

हलवाड से मेहसाना तक सीधी गाड़ी

†८९२. **श्री याज्ञिकः** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे पर बरास्ता सुरेन्द्रनगर, हलवाड से वीरमगाम या मेहसाना तक एक सीधी गाड़ी चलाने का फैसला किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में गुजरात सरकार की राय भी ली है ; और

(ग) हलवाड लाइन के यात्रियों के लाभार्थ सीधी गाड़ी वास्तव में कब चालू की जाएगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). इस समय हलवाड और मेहसाना के बीच एक तीसरे दर्जे की सीधी जाने वाली गाड़ी सेवा ऊपर की दिशा मे ३१७ अप/३४३ अप यात्री गाड़ियां, और नीचे की दिशा में ३४४ डाउन/३२२ डाउन यात्री गाड़ियां चलती हैं। सुरेन्द्रनगर तथा मेहसाना के बीच इस सीधी सेवा गाड़ी को ३५ अप/३६ डाउन की ऐक्सप्रैस से गाड़ियों के द्वारा बदलने की मांगें हुई हैं, किन्तु यह संभव नहीं है क्योंकि ये गाड़ियां अपने अधिकतम अनुज्ञेय भार के साथ चलती हैं ? इस मामले मे गुजरात की राज्य सरकार के अन्तिम विचार मालूम नहीं हुए हैं।

बीकानेर में टलीफोन कनेक्शन

८९३. **श्री प० ला० बारूपाल**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन की मुख्य मंडियों, शहर और कस्बों में कितने नये टेलीफोन लगाने की मांग आई है ; और

(ख) बीकानेर, गंगानगर और चुरु जिलों में वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर डायल सिस्टम की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

(ख) बीकानेर, गंगानगर तथा चुरु जिलों में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल टेलीफोन प्रणाली में परिवर्तित करने का विचार नहीं है। २५ लाइनों का एक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज हनुमानगढ़ कस्बे (जिला श्रीगंगानगर) में चल रहा है। श्रीडूंगरपुर (जिला बीकानेर) में एक अन्य छोटे स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज के लिए मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की नियुक्ति

८६४. **श्री प० ला० बारूपाल**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० और जनवरी, १९६२ के बीच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों से सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये उत्तर रेलवे विभाग मुख्य कार्यालय में आये ;

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया और कितनों का चुनाव किया गया ; और

(ग) उनमें से कितनों को काम पर लगाया गया और कितनों को पैनल में रखा गया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय पहली और दूसरी श्रेणी के पदों के लिए भर्ती नहीं करता। इसलिए उस कार्यालय में कोई आवेदन पत्र नहीं आया। तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ के लिये भूमि का अर्जन

†८६५. **श्री उ० मिश्र**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बेदखल किये गये लोगों को कुछ मुआवजा दिया गया है जिन पर भूमि बिहार के सिंघभूम जिले में राष्ट्रीय राजपथ बनाने के लिये अधिग्रहण की गई है ;

(ख) किस दर पर मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) अब तक मुआवजे की कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल मंडल के डाक व तार कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†८६६. **श्री अ० क० गोपालन**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल मंडल के कितने डाक व तार कर्मचारियों को सरकारी निवास स्थान दिया गया है;

(ख) कितने कर्मचारियों को अभी तक कोई निवास स्थान नहीं दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मुख्य नगरों या कस्बों में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वाटर बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ४०६ ।

(ख) मंडल में कर्मचारियों की कुल संख्या ८५८७ है । मकान किराया भत्ता के स्थान पर, जैसे बताया गया है, सारकारी निवास स्थान दे दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

केरल डाक व तार मंडल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये जाने वाले प्रस्तावित क्वाटरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

त्रिवेन्द्रम	८०
क्विलोन	१८
अलप्पी	३२
कोट्टयम	२५
त्रिचूर	६०
कन्नानूर	५०
कालीकट	३०
एर्नाकुलम	६०
पालघाट	४०
अन्य स्थान	५०
कुल	४४५

समय अनुसूचो भूमि अधिग्रहण पर निर्भर है । आशा की जाती है कि अधिकांश मामलों में, काम चालू योजना अवधि में पूरा किया जाएगा ।

कोजीकोड का बड़ा डाकघर

†८६७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजीकोड बड़ा डाक घर की इमारत के भू-गृहादि को पुन: बनाने की प्रस्थापना १९४५ से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो फैसला होने में असाधारण विलंब होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) कोजीकोड में बड़ा डाकघर इमारत बनाने के लिये भूमि का उपयुक्त टुकड़ा अधिग्रहण करने की कार्रवाई १६४६ में आरंभ की गई थी । राज्य सरकार के पंचाट के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के पश्चात् अगस्त १६५५ में भूमि का कब्जा लिया गया । विविध कारणों से एक से अधिक बार प्लान और अनुमानों में संशोधन होने के कारण, परियोजना के लिये प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संबंधी मंजूरी जून १६६० में दी गई थी । काम का टेंडर स्वीकार कर लिया गया है और शीघ्र ही निर्माण आरंभ होने की संभावना है ।

कासरगोड के समीप चन्द्रगिरी नदी के ऊपर रेल का पुल

†८६८. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड के समीप चन्द्रगिरी नदी के ऊपर रेलवे पुल में कोई त्रुटि पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रुटि पाई गई है ;

(ग) पुल कब बनाया गया था ; और

(घ) क्या हाल की बड़ी दुर्घटनाओं की दृष्टि से जो पुराने त्रुटियुक्त पुलों के कारण हुई हैं, इस पुल को पुनः बनाने का विचार है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) पुल १६०८ में बनाया गया था ।

(घ) पुल की चिनाई में त्रुटि नहीं है अपितु वह बहुत ठोस है । केवल गर्डर कमजोर हैं, जिन के कारण, ५ मील प्रति घंटा की गति संबंधी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । इस पुल पर पुनः गर्डर डालने का काम चल रहा है और चालू वर्ष के अन्त तक इस के पूरा हो जाने की आशा है ।

टेपियोका की खेती और निर्यात

†८६९. श्री अ० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेपियोका की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कोई प्रस्थापनायें हैं ;

(ख) क्या खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ राशि नियत की गई है, क्योंकि इस से विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्योरा क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना के अन्दर केरल में टेपियोका और शकरकंदी की अच्छी किस्मों को बढ़ाने और वितरण के लिय २.८६ लाख रुपये अलग रखे गये हैं ।

(ग) कन्दमूल फसलों, जिन में टेपियोका भी शामिल है, के अनुसंधान को तेज करने की योजना, जो भारत सरकार के खर्च पर २५ लाख रुपये की कुल लागत पर बनाई गई है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है । इस योजना के अधीन बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मैसूर और

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पांच उपकेन्द्रों के साथ त्रिवेन्द्रम में एक केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा केरल राज्य में पहले से चल रहे कन्दमूल फसलों के अनुसंधान के संबंध में अनुसंधान योजनाओं के अधीन किये गये काम के परिणाम स्वरूप, बहुत सी बढ़िया और अच्छी फसल देने वाली टेपियोका की किस्में मालूम की गई हैं। इन किस्मों के केरल के समूचे टेपियोका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैलाने और बांटने का विचार किया गया है। काम आरम्भ किया जा चुका है और चल रहा है।

४३ अप/४४ डाउन नार्थ-बंगाल एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन

†८७०. **श्री च० का० भट्टाचार्य:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाल्दाह और फरक्का के बीच फरक्का से और फरक्का तक चलने वाली ४३ अप/४४डाउन नार्थ बंगाल एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना के कब कार्यान्वित होने की आशा की जाती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी हां।

(ख) अप्रैल १९६३ से पहले नहीं।

मद्रास राज्य के लिये उर्वरक

†८७१. **श्री धर्मलिंगम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के अर्काट जिले में उर्वरकों का संभरण कम है ; और

(ख) १९६१-६२ के लिये मद्रास राज्य को कुल कितने उर्वरक दिये गये थे और कितने राज्य द्वारा मांगे गये थे।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) क्योंकि किसी राज्य के अन्दर आन्तरिक वितरण का मामला राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है, सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) मांगी गई और दी गई नाइट्रोजनस उर्वरकों की मात्रा नीचे दी जाती है :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

मांग	आवंटन
एन० के सम्बन्ध में	एन० के सम्बन्ध में
५२२९६	३७१९२

मद्रास (एगमोर)—ताम्बरम—विल्लूपुरम सेक्शन का विद्युतीकरण

†८७२. { **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के मद्रास (एगमोर)—ताम्बरम्-विल्लूपुरम् सेक्शन के विद्युतीकरण की योजना किस अवस्था में है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किस तारीख या अवधि तक सरकार काम को पूरा करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) मद्रास-(एगमोर) ताम्बरम्-विल्लूपुरम् सेक्शन के विद्युतीकरण की प्रगति इस प्रकार है :—

(१) ६० प्रतिशत सिविल इंजीनियरिंग काम पूरा हो चुका है ।

(२) सब-स्टेशन तथा स्विचिंग स्टेशन सामान के आर्डर दिये जा चुके हैं ।

(३) ए सी मोटर गेज इंजनों और रिमोट कंट्रोल सामान के टैंडरों की छान बीन हो रही है ।

(४) ऊपर के सामान का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । तांबरम से आगे और वडालूर तक ६ किलोमीटर पटरी पर ओ एच ई काम पूरा हो चुका है और ८-१-६२ को उपनगरीय सेवाओं के लिये बिजली दी जा चुकी है ।

(ख) तांबरम्-विल्लूपुरम् संबंधी काम दिसम्बर १९६३ तक और मद्रास (तट) से तांबरम तक मार्च १९६५ तक पूरा हो जाने वाला है ।

बंगलौर–सैलम मीटर लाइन

†८७३. { **श्री उमा नाथ :**
श्री नम्बियार : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर सैलम मीटर लाइन के निर्माण का वास्तविक काम आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह काम किस अवस्था में है ;

(ख) सरकार निर्माण कार्य कब आरम्भ करने का विचार करती है ; और

(ग) सरकार कब निर्माण कार्य पूरा करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). इस १४२ मील लंबी मीटर लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण जो दिसम्बर १९६१ में मंजूर किया गया, चल रहा है और तीन मुख्य पुलों पर निर्माण आरम्भ करने के प्रारम्भिक प्रबन्ध हाथ में ले रखे हैं । वास्तविक निर्माण कार्य, पटरी बिछाने के स्थान का अन्तिम रूपेन फैसला हो जाने और भूमि अधिग्रहण हो जाने के पश्चात् ही आरम्भ होगा । इस निर्माण कार्य को चलाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) १९६५ में लाइन यातायात के लिये खुल जायगी ऐसी आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवेली और सैलम के बीच रेलवे लाइन

†८७४. { श्री उमा नाथ :
श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली और सैलम को ब्राडगेज लाइन के साथ मिलाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यातायात के शीघ्रतापूर्वक साफ होने के लिये निवेली और सैलम को मिलाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सेलम और निवेली के बीच मीटर गेज लाइन पहले से है । इस की क्षमता वर्तमान यातायात को पूरा करने के लिये काफी है । निवेली और सेलम के बीच लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिये, लाइन क्षमता कार्य, अर्थात् क्रौसिंग स्टेशन आदि की व्यवस्था वाले, जिन पर लगभग १७.८९ लाख रुपये लागत आई है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे कर दिये गये थे । लगभग २.८० लाख रुपये की लागत के अतिरिक्त काम भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अनुमोदित किये जा चुके हैं । लाइन क्षमता को, जब कभी आवश्यक अनुभव होगा और बढ़ाने के लिये समुचित कार्रवाई की जायगी ।

बिहार में तपेदिक और कुष्ट के रोगी

८७५. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के दरभंगा जिले में १९५१-५२ में तपेदिक तथा कुष्ट पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या थी तथा १९६१-६२ में इन की संख्या बढ़ कर कितनी हुई ;

(ख) इन की संख्या में यदि कोई भारी वृद्धि हुई है, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन रोगों के प्रसार को रोकने तथा रोगियों के लाभ के लिये कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो वह योजना क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित की गई हैं :—

(१) बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम ।

(२) चलती-फिरती निदानशालाओं सहित क्षय निदानशालाओं की स्थापना ।

(३) क्षय-प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।

(४) क्षय-पृथक्करण शय्याओं की स्थापना ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(५) कुष्ट नियंत्रण योजना ।

(६) क्षय-कुष्ट एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अलवर को कोसी--भरतपुर के साथ मिलाने वाली बड़ी लाइन

†८७६. **श्री का० रा० गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर को कोसी या भरतपुर, बरास्तानगर, के साथ जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने का निश्चय और उसका आरम्भ तीन साल पहले किया गया था;

(ख) क्या उस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, यह काम वर्तमान योजना की अवधि के अन्तर्गत संभवतः शुरू किया जाने वाला है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं। कोसीकलां--भरतपुर/अलवर के बीच बड़ी लाइन पर केवल यातायात सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग). यातायात सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ था कि उस लाइन से काफी नुकसान होगा। इसलिए यह योजना रद्द कर देने का निश्चय किया गया।

बिहार--बख्तियारपुर लाइट रेलवे के अपदस्थ कर्मचारी

८७७. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्तियारपुर से राजगीर तक पूर्व रेलवे की नयी लाइन बनने के बाद बिहार--बख्तियारपुर लाइट रेलवे के अपदस्थ कर्मचारियों ने रेलवे विभाग से नियुक्ति की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाया है; और

(ग) उस पुरानी रेलवे में स्थायी और अस्थायी कुल कितने कर्मचारी थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) बिहार-बख्तियारपुर लाइट रेलवे के जो कर्मचारी १-१-१९६२ को ५० वर्ष से कम आयु के थे और जो शरीर से स्वस्थ और अन्यथा फिर से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये, उनका साक्षात्कार मार्च, १९६२ के पहले हफ्ते में पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों के अफ़सरों के सेलेक्शन बोर्डों द्वारा किया गया। इस सेलेक्शन के फलस्वरूप विभिन्न वर्गों में नियुक्ति के लिए २९४ कर्मचारी उपयुक्त पाये गये हैं। उनकी नियुक्ति के सवाल पर दोनों रेलें विचार कर रही हैं।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने ५० वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों की एक सूची भेजी है जिसमें सिर्फ ३०४ नाम हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गूलमर्ग में रज्जुपथ

†८७८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंगमर्ग को गुलमर्ग के साथ रज्जुपथ से जोड़ने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार ने मंजूर की है;

(ख) उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके वित्तीय पहलू क्या हैं; और

(घ) उस पर जो खर्च किया जायगा उसका बंटवारा केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू और काश्मीर राज्य के बीच किस प्रकार किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पर्यटन के विकास सम्बन्धी तीसरी पंचवर्षीय योजना में २० लाख रुपये की अनुमानित लागत से गुलमर्ग (काश्मीर) में शीतकालीन खेलकूद के विकास की एक योजना शामिल है । यह खर्च केन्द्रीय सरकार खुद करेगी । शीतकालीन खेलकूद के विकास में खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को गुलमर्ग से अलपाथेर तक ले जाने के लिए रज्जुपथ बनाने की भी योजना है । इस योजना का समन्वय अणुशक्ति विभाग की उन योजनाओं के साथ किया जा रहा है जिनके अन्तर्गत उसके वैज्ञानिकों और साजसामान को ले जाने के लिए गुलमर्ग से अफरावत तक एक रज्जुपथ बनाने का विचार है । उस विभाग ने चेकोस्लावाकिया के इंजीनियरों के एक दल के द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया है जिसने रज्जुपथ के लिए एक निश्चित रेखा का सुझाव दिया था । पर्यटन विभाग के कहने पर आस्ट्रिया के एक शीतकालीन खेलकूद विशेषज्ञ ने दिसम्बर १९६० में इस क्षेत्र को देखा और रज्जुपथ की रेखा में कुछ रद्दोबदल करने का सुझाव दिया । जाड़े में गुलमर्ग तक पहुंचने के लिए उसने यह सिफारिश की थी कि तंगमर्ग से गुलमर्ग तक सभी मौसमों में काम आने वाली ऐसी सड़क बनायी जाये जिस पर मोटरें आ जा सकें । यदि जाड़े के महिनों में भारी बर्फ के कारण तंगमर्ग और गुलमर्ग के बीच की सड़क को खुली रखना सम्भव न हो सका तब, उसके सुझाव के अनुसार, तंगमर्ग और गुलमर्ग के बीच भी एक रज्जुपथ बनाया जाये । अणुशक्ति विभाग ने इस योजना के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में सलाह देने के लिए सितम्बर-अक्तूबर, १९६१ में फ्रांसीसी परामर्शदाता इंजीनियर की सेवाएं प्राप्त की थीं । संपूर्ण योजना के खर्च का एक अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन सभी सुझावों की वास्तविक छानबीन कर रहा है । इसलिए ब्यौरे तथा वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

तुंगभद्रा जलाशय गांवों के पास नलकूप

†८८०. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के लोगों की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि तुंगभद्रा जलाशय गांवों के आस पास नलकूप लगाने की संभावनाओं का पता लगाया जाय;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने तथा प्रयोग के तौर पर वहां खुदाई करने के लिए एक या दो कार्यकारी एकक भेजने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या मंत्रालय को मालूम है कि जलाशय के पास होजपेठ के चीनी कारखाने में एक ऐसा ही नलकूप सफलतापूर्वक चल रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स आर्गनाइजेशन के एक भूगर्भशास्त्री ने दिसम्बर, १९६१ में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उसे यह मालूम हुआ है कि उस क्षेत्र में भूगर्भ सम्बन्धी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां नलकूप लगाना उपयुक्त नहीं है।

(ग) पता चला है कि जलाशय के पास होजपेठ के चीनी कारखाने में नलकूप से सिर्फ २,००० गैलन प्रति घंटे पानी मिलता है और कुछ ही घंटे काम करने के बाद वह सूख जाता है। यह एक सफल नलकूप की सामान्य कसौटी पर सच्चा नहीं उतरता, जो निरन्तर पानी निकालने पर प्रति घंटे २०,००० गैलन या उससे अधिक होती है।

कृष्णा नदी घाटी परियोजना

†८८१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कृष्णा नदी घाटी परियोजना शुरू की जायेगी तो मैसूर राज्य के जिला बीजापुर, हुनुगुन्ड तालुके में कुडल संगम नामक स्थान डूब जायगा;

(ख) क्या इस विश्वविख्यात मंदिर को डूबने से बचाने के लिए मैसूर के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति और महत्व का तथा कर्नाटक के सांस्कृतिक महत्व का एक स्थान है;

(ग) क्या यह सच है कि कृष्णा नदी घाटी परियोजना प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र में सीथाइमणि के पास बनायी जा सकती है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि बीजापुर जिले में सीथाइमणि के पास दो पहाड़ों को जोड़ कर यह परियोजना बनाने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। कृष्णा नदी घाटी परियोजना के दो बांधों में से एक अलमत्ती बांध सीथाइमणि के पास बनाया जाने वाला है।

(घ) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे वर्कशापों द्वारा रद्दी लोहे का उपयोग

†८८३. **श्री टॆ० सुब्रह्मण्यम् :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में अब तक रेलवे वर्कशापों में कितना रद्दी लोहा इस्तेमाल किया गया और कितना इस्पात कारखानों में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हुआ; और

(ख) क्या इस अवधि में वह किसी मात्रा में निर्यात के लिए भी उपलब्ध था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) (१) रेलवे वर्कशापों में १९६१ में लगभग ७०,००० टन और १९६२ में (मार्च, १९६२ के अन्त तक) लगभग २०,००० टन रद्दी लोहा काम में लाया गया।

(२) इस्पात कारखानों में उपयोग के लिए १९६१ में लगभग २७,००० टन और १९६२ में (मार्च, १९६२ के अन्त तक) लगभग ५,००० टन रद्दी लोहा उपलब्ध हुआ।

(ख) इस अवधि में किसी भी मात्रा में रद्दी लोहा खास कर निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं हुआ था।

गुन्टकल-हौजपेठ बड़ी रेलवे लाइन

†८८४. { **श्री टॆ० सुब्रह्मण्यम् :**
श्री मोहसिन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में गुन्टकल से हौजपेठ तक बड़ी लाइन बनाने के बारे में १९६२-६३ का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) यह लाइन कब तक बन कर पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस योजना पर विचार हो रहा है।

(ख) अभी यह नहीं बताया जा सकता कि काम कब तक पूरा हो जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना

†८८६. **श्रीमती विमला देवी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश के कितने गांवों में बिजली लगायी जाने वाली है ; और

(ख) इन गांवों को किन-किन विद्युत् प्रणालियों से बिजली दी जायेगी और प्रत्येक प्रणाली से कितने गांवों को बिजली मिलेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): (क) २,००० ।

(ख) सभी गांवों को आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की ग्रिड प्रणाली से बिजली दी जायेगी।

जम्मू और काश्मीर राज्य में सामुदायिक विकास खंड

†८८७. श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में कितने सामुदायिक विकास खण्ड हैं ;

(ख) क्या ये उपर्युक्त खण्ड उस क्षेत्र की, जो पहाड़ी क्षेत्र है और जहां की आबादी बहुत थोड़ी है, आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) उपर्युक्त राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या और अधिक खण्ड चालू करने का सरकार का विचार है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) ५२ ।

(ख) और (ग). अतिरिक्त खण्ड नियत करने के बारे में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार हो रहा है ।

अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा नेता

†८८८. श्री प० ना० कयाल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं की कोई पदालि है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है ; और

(ग) ऐसी पदालि के कितने लोग फिलहाल प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). अवैतनिक खंडीय (डिवीजनल) परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं और अवैतनिक जिला परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं को क्रमशः प्रत्येक नेता को ४,००० और २,००० रुपया वार्षिक सहायक अनुदान देकर नियुक्त किया गया है ।

(ग) ३२ अवैतनिक खंडीय परिवार नियोजन शिक्षा नेता तथा १७ अवैतनिक जिला परिवार नियोजन शिक्षा नेता फिलहाल राज्यों में काम कर रहे हैं जिसका व्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य सरकार	खंडीय नेताओं की संख्या	जिला नेताओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	१	——
आसाम	——	——
बिहार	१	——
गुजरात	१	२

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकार	खंडीय नेताओं की संख्या	जिला नेताओं की संख्या
जम्मू तथा काश्मीर . . .	——	——
केरल	२	५
महाराष्ट्र . .	५	३
मध्य प्रदेश .	६	२
मद्रास	२	१
मैसूर	१	——
उड़ीसा	——	३
पंजाब	२	——
राजस्थान . . .	१	——
उत्तर प्रदेश .	३	——
पश्चिम बंगाल .	३	——
दिल्ली	४	——
हिमाचल प्रदेश . .	——	१
जोड़ . .	३२	१७

परिवार नियोजन रुजालय

†८८६. **श्री प० ना० कयाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन रुजालय चलाने के लिये स्वयंसेवी संगठनों को वर्ष १९६१ में कितनी रकम मंजूर की गयी थी ;

(ख) ऐसे संगठनों की सच्चाई जांचने के लिये सरकार कौन से तरीके अपना रही है ; और

(ग) क्या ऐसे संगठनों के कामकाज का निरीक्षण करने के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई प्रणाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) परिवार नियोजन रुजालय चलाने के लिये वर्ष १९६१ में स्वयंसेवी संगठनों को १८,७९,१९६ रुपये के सहायता अनुदान मंजूर किये गये थे।

(ख) भारत सरकार से सहायता अनुदान के लिये आवेदन करने वाले संगठन को अपनी सच्चाई के बारे में साधारणतया निम्नलिखित प्रमाण पत्र पेश करने पड़ते हैं कि :—

(१) यह संगठन एक रजिस्टरशुदा संस्था है ;

(२) इसकी नियमित रूप से बनायी गयी एक प्रबन्ध समिति है।

(३) यह जनता के लिये समाज कल्याण कार्य करता है और कोई मुनाफा नहीं कमाता।

†मूल अंग्रेजी में

(४) सहायता अनुदान उसी प्रयोजन के लिये काम में लाया जायेगा। जिसके लिये कि वह मंजूर किया गया है।

(५) जनता को, केवल स्वीकृत अनुसूची के अनुसार गर्भ निरोधक वस्तुओं के वितरण को छोड़ कर सेवा निःशुल्क दी जायगी।

(६) हिसाब किताब के लेखा-परीक्षित विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भेजे जायेंगे।

(७) जैसे बनाया जायगा उस प्रकार प्रगति विवरण भेजे जायेंगे।

(८) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से जो परिसम्पद् प्राप्त किये जायेंगे, वे भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित नहीं किये जायेंगे।

(९) हिसाब किताब ठीक ढंग से रखा जायेगा और भारत सरकार या राज्य सरकार उसकी जांच कर सकती है।

(१०) जो सहायता अनुदान प्राप्त होगा उसके खर्च के सम्बन्ध में यथासम्भव कमखर्ची बरती जायेगी।

(११) उसकी सचाई और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह काम करता हो, एक प्रमाण पत्र।

(ग) जी हां। भारत सरकार प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन के सहायक निदेशक के वेतन और भत्तों का पूरा पूरा खर्च उठाती है। यह सहायक निदेशक परिवार नियोजन रुजालयों की देख रेख करने और उनके कामकाज में कोई दोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये उत्तरदायी होता है। सहायता अनुदान के लिये स्थानीय संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों से आये हुए आवेदन पत्रों पर सामान्यतया राज्यों के परिवार नियोजन से सम्बद्ध सहायक निदेशकों की सिफारिशों के आधार पर ही विचार किया जाता है। रुजालयों को सहायता अनुदान देना जारी रखने की मंजूरी देने के लिये इन पदाधिकारियों की विशिष्ट सिफारिशें जरूरी होती हैं। इन पदाधिकारियों को सम्बन्धित संस्थाओं के, जिन्हें सहायता अनुदान दिया गया हो, हिसाब किताब भी जांचने पड़ते हैं और उन्हें मंजूर किये गये सहायता अनुदान के सम्बन्ध में प्रयोग-प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर भी करने होते हैं।

भारत सरकार ने दो प्रादेशिक परिवार नियोजन पदाधिकारी नियुक्त किये हैं जो भारत सरकार से मिली हुई सहायता से राज्यों में स्थापित किये गये परिवार नियोजन रुजालयों का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दूसरे पदाधिकारी भी जहां कहीं दौरे पर जाते हैं वहां परिवार नियोजन रुजालयों का निरीक्षण करते हैं और स्वयंसेवी संगठनों के कामकाज की जांच पड़ताल करते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि

†८९०. { **श्री प० ना० कयाल :**
{ **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री २८ मार्च, १९६२ के **अतारांकित** प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में प्रस्तावित पुनरीक्षित ढांचा अभी विचाराधीन है।

१८ वर्ष से कम आयु के रेलवे कर्मचारियों की भरती

†८९१. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों को १८ वर्ष से काम आयु पर ही भरती कर लिया गया था तथा जो अभी भी रेलवे में काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशन मास्टरों ने जन्म तिथि में परिवर्तन करना स्वीकार किया था क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी लिखित जन्म तिथि का लाभ उठा चुके थे और १८ वर्ष से कम आयु में ही भरती हो चुके थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में परिवहन सहकारी समितियां

†८९२. { **श्री गुलशन:**
{ **श्री बूटा सिंह:**

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में अब तक कितनी सहकारी समितियों का पंजीयन हुआ है ;

(ख) इन पंजीबद्ध परिवहन सहकारी समितियों में से कितनी परिवहन सहकारी समितियों के मालिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित समितियों द्वारा कितने मार्गों के परमिट अब तक दिए गए हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहनमंत्री** (श्री राज बहादुर) : (क) ६४।

(ख) अनुसूचित जातियां २।

अनुसूचित आदिम जातियां और पिछड़े वर्ग कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटा रेलवे स्टेशन यार्ड में मिशनरी स्कूल

८९३. श्री बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा रेलवे स्टेशन के यार्ड में एक ईसाई मिशनरी स्कूल चल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त स्कूल के लिये रेलवे की सीमा में उन्हें भूमि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनको एक कमरा, जो भूत बंगले के नाम से प्रसिद्ध है, दिया गया; और

(घ) अन्य संस्थाओं को रेलवे विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार सुविधा देने बाबत क्या नियम हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). सोफिया मिशन स्कूल को टाइप ३ के दो क्वार्टर लाइसेंस पर दिये गये हैं। यह स्कूल कोटा रेलवे बस्ती के पास प्राइवेट जमीन में बना हुआ है।

(घ) सामान्यतः रेलवे बस्तियों में या उनके पास जो गैर रेलवे स्कूल स्थित हैं और जो रेल कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें रेलवे की खाली जमीन या इमारत का लाइसेंस देने के सम्बन्ध में उनके आवेदन पत्रों पर स्थिति के अनुसार विचार किया जाता है। रेल-प्रशासन ऐसे स्कूलों को फर्नीचर और अन्य सामान की खरीद के लिये वित्तीय सहायता भी देते हैं; इसके अलावा इस तरह के जो स्कूल अपना खर्च पूरा नहीं कर पाते, उन्हें सहायक अनुदान भी दिया जाता है।

तम्बाकू पर लाइसेंस फीस

†८९४. श्री कार्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू पर लाइसेंस फीस कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों को उचित मूल्य पर बीज और खाद देने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति उचित मूल्य पर इस समय की अच्छे किस्म का बीज दे रही है। केवल तम्बाकू उत्पादकों को खाद देने सम्बन्धी भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तम्बाकू उत्पादकों को खाद और उर्वरक उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार अन्य किसानों को।

मीटर गेज लाइन को बगहा तक बढ़ाना

८९५. श्री क० ना० तिवारी: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल एवं उत्तर बिहार से कलकत्ता आदि स्थानों के लिये जूट गुड्स पटसन की वस्तुयें, चीनी, तीसी, लकड़ी, गंडक प्रोजेक्ट के लिये भारी सामानों को तथा अन्यान्य सामानों को ले जाने और उधर से लोहा, कोयला, सीमेंट, ले आने में मीटर गेज की लाइन पूरी तरह से उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समस्तीपुर तक गई मीटरगेज को बगहा तक बढ़ाना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क): जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता। 'बगहा' (Wagah) नाम का कोई स्टेशन नहीं है और मीटर लाइन भी इस समय समस्तीपुर में खत्म नहीं होती। शायद माननीय सदस्य का मतलब बगहा (Bagaha) स्टेशन से है और उनका प्रश्न बड़ी लाइन को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में है।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†८९६. **श्री जेधे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध संभरण योजना के डिपुओं के कर्मचारियों द्वारा दुग्ध के ग्राहकों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं ;

(ख) क्या पुराने से नये सिक्कों में गिनती करने में अधिक पैसे लिये जाने के बारे में भी शिकायतें आई हैं।

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन काम करने वाले एक डिपू मैनजर के विरुद्ध किसी छोटी मोटी शिकायत को छोड़ कर, उन कर्मचारियों के व्यवहार के विरुद्ध कोई सामान्य शिकायत नहीं हुई है।

(ख) कभी कभी इस प्रकार की शिकायतें, कि कोई डिपू मैनेजर पुराने सिक्कों को नये सिक्कों में बदलते समय वह एक नया पैसा अधिक लेता है, प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी हां।

(क) संबद्ध कर्मचारियों को ठीक नाम लेने के संबंध में हिदायत जारी कर दी गई है। गलती सुधार ली गई है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर राज खारसवान में ऊपरी पुल

†८९७. **श्री ह० थ० सौध** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दक्षिणपूर्व रेलवे पर राज खरसवान रेलव जंक्शन पर, रेलवे के दफ्तरों और प्लेटफार्मों पर दक्षिण की ओर कोई ऊपरी पुल नहीं है और पिछले पांच वर्षों या लगभग उतने समय के अन्दर वहां बहुत सी घातक दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे तुरन्त वहां एक ऊपर का पुल बनाने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख) . स्टेशन दक्षिण की ओर रहने वाले रेलवे कर्मचारी हावड़ा किनारे के फाटक से स्टेशन पर आ सकते हैं। दक्षिण की ओर को मिलाने के लिये पैदल ऊंपरी पुल का विस्तार उचित नहीं समझा गया।

रेलवे को किसी घातक दुर्घटना के मामले का पता नहीं है।

डाक-तार विभाग का मोटर सर्विस सेक्शन, दिल्ली

†८९८. **डा० मेलकोटे**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि डाक वह तार विभाग के मोटर सर्विस सैक्शन, दिल्ली ने मोटर की बाडी बनान का काम आरम्भ कर दिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च हुई और कितने बाड़ियां बनाई गईं ;

(ग) यदि खर्च करने के बावजूद भी अब तक कोई बाडी बनाई नहीं गई, तो इसके क्या कारण थे और इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां; प्रयोगात्मक आधार पर।

(ख) अब तक ६४४५ रुपये ७० नये पैसे खर्च किये गये हैं। काम पांच बाडियों पर आरम्भ किया गया था। लगभग ७५ % से ८५ % तक काम तीन बाडियों पर पूरा हो चुका है। अन्य दो बाडियों पर, ऊपर के ढांचे के लिये फर्श और घेरे आदि के चैनल तैयार किये जा चुके हैं।

(ग) जिस ठेकेदार को श्रमिकों की व्यवस्था करने का काम दिया गया था, वह इस बात के बावजूद कि उसने तीन बार कार्यकर्ता बदले, विभाग द्वारा अपेक्षित स्तर तक बाडी बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमिकों की व्यवस्था नहीं कर सका। ठेकेदार ने काम बन्द कर दिया है और अब शष काम को विभागीय तौर पर पूरा करने का विचार किया जा रहा है।

गोहाटी रेलवे स्टेशन

†८९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि नारंगी के नये गोहाटी रेलवे स्टेशन के पीछे दीवार बनाने का काम गौहाटी विकास प्राधिकार की इस चेतावनी के बावजूद कि साथ वाली सड़क को चौड़ा करने की उस प्राधिकर की योजना के सिलसिले में उस दीवार को गिराना पड़ेगा, जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे और गौहाटी प्राधिकार के बीच कोई समझौता होने तक आगे का निर्माण कार्य क्यों रोक नहीं दिया जाता ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पी० डब्ल्यू० डी० सड़क के साथ नारंगी मालशैड क्षेत्र के लिये चारदीवारी बनाने का काम प्रायः पूर्ण हो चुका है। यह निर्माण सुरक्षा के लिये तथा रेलवे भूमि पर अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिये जरूरी समझा गया था। तथापि चारदीवारी फीकास्ट आर० सी० पोस्टों और पैनलों के साथ बनाई गई है ताकि यदि किसी भविष्य की तारीख पर, इस सड़क का विकास कार्य प्राधिकार द्वारा किया जाय, तो उनको फिर से बनाया जा सके।

पानी भर जाना

†९००. **श्रीमती मैमुना सुलतान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ में प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी भूमि जल में डूब रही ;

(ख) इस में से कितनी भूमि अब तक कृषि योग्य बनाई गई है ; और

(ग) एसी अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये और क्या कार्रवाइयां की जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) से (ग). सूचना विविध राज्य सरकारों से मांगी गई थी किन्तु अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोपाल में टेलीफोन के कनक्शन

†९०१. { **श्रीमती मैमुना सुल्तान :**
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में एक स्वचालित टलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां।

(ख) लगभग २८.५३ लाख रुपये ।

(ग) विस्तृत प्लान और विशिष्ट ब्योरे तैयार किये गये हैं और अनुमोदित हो चुके हैं। इमारत बनाई जा रही है और एक्सचेंज उपकरण के लिय आर्डर दिये जा चुके हैं।

कोयना परियोजना

†९०२. **श्री नाथ पाई :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोयना परियोजना को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: (क) और (ख) . भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को कोयना जल-विद्युत परियोजना के प्रक्रम -१ पर होने वाला व्यय पूरा करने के लिये ऋण के रूप में सहायता दे रही है। १९६१-६२ के अन्त तक इस काम के लिय राज्य सरकार को ३२.३० करोड़ रुपय की राशि दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने और अधिक सहायता की मांग नहीं की ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

ट्रक वालों के सबंध में शिकायत

†९०३. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें हुई हैं कि जब तक ट्रंक काल चल रही होती है, ओपरेटर बात करने वाले व्यक्ति को यह कह कर कि दूसरी ट्रंक काल के लिये वे बात बन्द कर दें, कॉल काल बाधा डालते हैं और इस प्रकार पहली काल का समय बर्बाद करत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) समय समय पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं ।

(ख) जब बात करने वाले को बाधा अनुभव हुई हो तो उसको ट्रंक काल पर अतिरिक्त समय दे दिया जाता है ।

हरदोई स्टेशन के समीप सिपाही की मृत्यु

†९०४. **श्री बसू मतारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाहाबाद का केशरसिंह नाम का एक हैड कांस्टेबल २२ अप्रैल को हरदोई स्टेशन के पास मर गया, जब उसने अपने कब्जे अधीन एक अपराधी को पकड़ने का प्रयत्न किया, जो गाड़ी से कूद गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी, हां । २२-४-६२ को हेड कांस्टेबल श्री केशरसिंह, अलाहाबाद के दो अन्य सिपाहियों के साथ एक सिद्धदोषी कैदी को साथ नैनी जेल से गरेली जेल तक ला रहा था । जब गाड़ी लखनऊ-बालामऊ सक्शन पर दिलावर नगर और रहीमाबाद स्टेशनों के बीच चल रही थी, रद्दी किया हुआ कैदी, टट्टी की ओर गया और उस ने चलती गाड़ी से कूदने का अवसर पा लिया । हैड कंस्टेबल जो बिल्कुल पीछे था, कैदी को पकड़ने के लिये चलती गाड़ी में से कूद पड़ा, किन्तु वह कुचला गया और तुरन्त मारा गया । खतरे की जंजीर खेंची गई और कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक गई । हैड कांस्टेबल का मृत शरीर उठा लिया गया और पोस्ट मारटम परीक्षण के लिये हरदोई ले जाया गया । इसी बीच रद्दी किया हुआ कैदी अन्य दो में से एक कंस्टेबल द्वारा पकड़ लिया गया ।

टूना मछलियों सम्बंधी अनुसंधान

†९०५. **श्री फ० गो० सेन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे मत्यस्पालन अनुसंधान वैज्ञानिकों ने भारत में टूना मत्स्यपालनों के लिये कोई अनुसंधान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की प्रगति तथा शम्यता कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल:)**: (क) भारत के तटों के साथ पकड़ी गई टूना मछली के शरीर विज्ञान तथा शरीर पद्धति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुसंधान आरम्भ किया गया है ।

(ख) टूना भारत के तटीय जलो में महत्वपूर्ण मत्स्यपालन नहीं । यह केवल भारतीय समुद्र के केवल मिनिकाय द्वीप के इर्द गिर्द है । वर्ष भर में लगभग ५ लाख रुपये की यह मछली पकड़ी जाती है । भारत के आस पास गहरे समुद्रों में टूना संसाधनों का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

कम्पाउन्डरों और ड्रेसरों के लिये सेलेक्शन ग्रेड

९०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६२ में केन्द्रीय सरकार के हस्पालों के कम्पाउन्डरों और ड्रेसरों के लिये किसी सेलेक्शन ग्रेड को मंजूर किया गया था :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां । १३ फरवरी १९६२ से अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कम्पाउण्डरों और ड्रसरों के लिये सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये गये हैं । केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कम्पाउन्डरों के लिये सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). यह विषय विचाराधीन है । अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आठ कम्पाउण्डरों और नौ ड्रेसरों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारी

९०७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में समस्त कार्यालयों में ८० प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सी० एच० एस० स्कीम के अन्तर्गत ८० प्रतिशत डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी अभी अस्थायी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सी० एच० एस० के डाक्टरों की लिस्ट पिछले एक वर्ष से संघ लोक सेवा आयोग के पास उन को स्थायी करने के सम्बन्ध में पड़ी हुई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार किया और ८० प्रतिशत अस्थायी पदों, जिन में चतुर्थ श्रेणी के पद भी शामिल हैं, को स्थायी करने का निश्चय किया है बशर्ते कि वे कम से कम ३ वर्ष से लगातार अस्तित्व में रहे हों ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). जिन पदों पर सम्बन्धित डाक्टरों को स्थायी करने का विचार है, उन पदों के स्थायी होने पर या तो वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल कर दिये गये हैं या उन के शामिल किये जाने की संभावना है । केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का इनिश्यल कांस्टिट्यूशन अप्रैल १९६१ से आस्थगित रखा गया है । केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित नियमों के प्रारूप को, जो अक्टूबर १९६१ में संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । जिन पदों के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल किये जाने की सम्भावना है उन पर मेडिकल अफसरों के स्थायीकरण के विषय को, उक्त सेवा के आस्थगन के समय से लेकर जो बातें सामने आई हैं उन पर विचार किये बिना, अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका । यह विषय इस समय संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है ।

कपास की कम उपज

†६०८. **श्री चांडक:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपास की खेती का क्षेत्र संसार में सब से बड़ा है और प्रति एकड़ कपास की उपज सब से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** (क) भारत में कपास की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है, किन्तु प्रति एकड़ संसार में सब से कम तो नहीं, किन्तु कम अवश्य है ।

(ख) प्रति एकड़ कपास की उपज को बढ़ाने के लिये निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

(१) सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था

(२) उत्तम बीजों, खादों और उर्वरकों के उपयोग के लिये सुविधायें प्रदान करना

(३) पौधा परिरक्षण उपाय

(४) बेहतर पालन तरीकों, अर्थात् ठीक समय पर बोना, लाइनों में बोना, उचित स्थान छोड़ना, उखाड़ना आदि, को लोकप्रिय बनाना ।

मशीनी फार्मों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

६०९. **श्री चांडक:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूरतगढ़ (राजस्थान) फार्म की भांति अन्य राज्यों में फार्म खोलने की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस के सर्वेक्षण के लिये एक सर्वेक्षण समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो क्या यह दामले समिति है ; और

(ग) क्या इस समिति ने कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट की प्रति टेबल पर रखी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) २२ मार्च, १९६१ को तारांकित प्रश्न न० १०३६ के उत्तर में बताये अनुसार दामले समिति की पहली रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही से संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं । कुछ और प्रस्ताव इस समिति के विचाराधीन हैं तथा इस की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

दिल्ली दूध योजना

†६१०. **श्री फ० गो० सेन:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्षों की अल्प अवधि के अन्दर दूध की गाड़ियों का ऐसा रूप क्यों हो गया है कि वह पुरानी खरीदी हुई प्रतीत होती हैं ;

(ख) उन की मरम्मत आदि की कितनी लागत आती है ;

(ग) क्या कुछ त्रुटियां पाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) दिल्ली दूध योजना के कार्यों का क्षिप्र गति के विलय होने के कारण, दूध की गाड़ियां और टैंकर दिन में १८ से २० घंटे तक चलाये जाते हैं और वे प्रति वर्ष ३०,००० से ४०,००० मील चलते हैं। इन परिस्थितियों में उनका मूल रूप कायम नहीं रह सकता।

(ख) एक दूध की गाड़ी को चलाने और मरम्मत आने की औसत लागत १९६१-६२ में ९५ नये पैसे प्रति मील थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

दिल्ली के गांवों में क्षयरोगियों के लिए चलते फिरते चिकित्सालय

†९१२. श्री दी० चं० शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के गांवों में क्षयरोगियों के लिये चलते फिरते चिकित्सालय चालू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के २००—२५० गांवों में क्षयरोगियों को उन के घरों पर सेवा की व्यवस्था करने की एक योजना पर दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है। १००—१२५ गावों की सेवा करने के लिए एक-एक चलता फिरता चिकित्सालय चालू करने का विचार है। आरम्भ में, एक्सरे तथा प्रयोगशाला साज सामान से लैस एक क्षय-रोग चिकित्सालय सम्भवतः चालू किया जायेगा। चलते फिरते चिकित्सालय सप्ताह में खास खास दिनों पर रोग के निदान और इलाज के लिये गांवों में जायेंगे।

पंजाब में गांवों में पानी पहुंचाने की योजनाएं

†९१३. श्री दलजीत सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में पंजाब सरकार ने गांवों में पानी पहुंचाने की कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं; और

(ख) अभी तक कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १०४]।

रूपड़–नंगल बांध सेक्शन में सुविधाओं की व्यवस्था

†९१४. श्री दलजीत सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के रूपड़–नंगल बांध सेक्शन में १९६१–६२ में कोई सुविधाएं दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किस प्रकार की सुविधाएं दी गयी हैं और उन पर कितनी रकम खर्च हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नंगल बांध और भानूपली के बीच हाल्ट स्टेशन

†६१५. श्री दलजीत सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल बांध और भानूपली के बीच एक (हाल्ट स्टेशन) मंजूर किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसे बनाने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) नंगल बांध और भानुपली के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। जांच पड़ताल से यह पता चला है कि यह स्टेशन लाभप्रद नहीं होगा। फिर यह हाल्ट स्टेशन रूपड़-नंगल बांध सेक्शन में होने के कारण कुछ पूंजी व्यय पंजाब सरकार को करना था जो वह नहीं करना चाहती थी। इसलिए यह योजना आगे नहीं बढ़ पायी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

किराये की इमारतों में डाक-तार घर

†६१६. श्री दलजीत सिंह: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले में कितने डाकखाने फिलहाल किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ में डाकखाने की कितनी इमारतें बनायी गयीं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) ५८।

(ख) कोई नहीं।

पंजाब में डाक तार विभाग की इमारतें

†६१७. श्री दलजीत सिंह: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) डाक तार विभाग की इमारतें बनाने के लिए दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पंजाब राज्य के लिए कुल कितनी रकम मंजूर की गयी थी; और

(ख) अभी तक कितनी और कौन-कौन सी इमारतें बनायी जा चुकी हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क)

दूसरी पंचवर्षीय योजना	३६.३६ लाख रुपया
तीसरी पंचवर्षीय योजना	
पहले दो साल (६१-६२ और ६२-६३) . .	२७ लाख रुपया

†मूल अंग्रेजी में

बाकी तीन साल के लिए रकम निर्माण कार्यों की प्रगति के आधार पर नियत की जायेगी ।

(ख) २७, जैसा कि अनुबन्ध में बताया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १०५]।

कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र

†९१८. श्री पु० र० पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र और संस्थाएं काम कर रही हैं जिन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है;

(ख) उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन केन्द्रों और संस्थाओं को किस आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है;

(घ) क्या उन केन्द्रों और संस्थाओं के प्रशासन, कार्यप्रणाली और उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(ङ) क्या सरकार ने उन केन्द्रों और संस्थाओं के कार्य का मूल्यांकन किया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित संस्थाओं में ७ कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये हैं :—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

(२) गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना

(३) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास

(४) विश्वभारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल

(५) कृषि कालेज, ग्वालियर मध्य प्रदेश

(६) कृषि कालेज, जोरहाट (असम)

(७) सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, आनन्द (गुजरात)

साथ ही खाद्य और कृषि मंत्रालय अपने हित के कृषि-आर्थिक अध्ययन चालू करने के लिए इंस्टिट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ, दिल्ली को भी अनुदान देता है ।

(ग) इन केन्द्रों और संस्थाओं पर किया गया पूरा पूरा खर्च भारत सरकार से सहायता-प्रदान के तौर पर दिया जाता है ।

(घ) इन केन्द्रों का प्रशासन प्रशासक/परामर्शदातृ निकाय द्वारा किया जाता है जिसमें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधि भी होता है ।

(ङ) जी हां । अलग अलग प्रत्येक केन्द्र रिपोर्ट और लेखे इस मंत्रालय को पेश करता है और एक निदेश समिति जिसमें मंत्रालय का प्रतिनिधि भी होता है, समय समय पर इन केन्द्रों के काम की छानबीन करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन को फिर से बनाना

†९१९. **श्री तिम्मय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सिटी के रेलवे स्टेशन को आधुनिक शैली से फिर से बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) वर्तमान यार्ड और स्टेशन की इमारत में रद्दोबदल करने की योजनाओं पर विचार हो रहा है ।

(ख) इस समय ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि कई वैकल्पिक योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जांच पड़ताल की जा रही है ।

कानपुर–बालामऊ सेक्शन पर कालीमिट्टी स्टेशन का निर्माण

†९२०. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर–बालामऊ सेक्शन (उत्तर रेलवे) पर कालीमिट्टी स्टेशन के निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था;

(ख) यह कार्य काफ़ी समय से अधूरी अवस्था में क्यों छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस स्टेशन के निर्माण का कार्य फिर प्रारम्भ किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो यह स्टेशन कब से चालू हो जायेगा; और

(ङ) यदि उपरोक्त प्रश्न (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) कालीमिट्टी स्टेशन, जिसका नाम अब फतेहपुर चौरासी रखने का विचार है, पर ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट बनाने का काम अगस्त, १९५९ में शुरू किया गया था ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित स्टेशन का इस्तेमाल करने वाली आबादी के विभिन्न वर्गों में इस बात पर मतभेद था कि स्टेशन कहां बनाया जाय । इसलिए काम तेजी के साथ नहीं किया जा सका । १९५९ में अंतिम रूप से ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट बनाने का फैसला किया गया काम १९५९ में शुरू हुआ और १९६० में खत्म हो गया । स्टेशन बन जाने के बाद सबंधित अधिकारियों में इस स्टेशन का सही नाम रखने के बारे में मतभेद के कारण जल्द फैसला न हो सका ।

(घ) हाल्ट १५ जून, १९६२ तक यातायात के लिए खोल दिये जाने की संभावना है ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

तार की सुविधाएं

†९२१. **श्री ब० वर्मा:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निघासन जिला खेरी (उत्तर प्रदेश) में तहसील मुख्य कार्यालय है;

(ख) क्या सिंघाई में जो वहां से मुश्किल से ६ मील दूर है और जो पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, तार की लाइन है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या उस लाइन को सिंघाई से निघासन तक ले जाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) करीब करीब छः महीने के समय में ।

उत्तर प्रदेश में पलिया कलान में चीनी कारखाना

†९२२. श्री बा० वर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला खिन (उत्तर प्रदेश) में पलिया कलान में एक चीनी-कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किसे ; और

(ग) उसके बनाये जाने की क्या संभावनाएं हैं ?

†खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

फरक्का बांध

†९२३. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह बांध बनाने में कुछ कठिनाइयां पैदा होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनका मुकाबला किस प्रकार करने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहिम): (क) से (ग). जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

परियोजना स्थल पर बस्ती के लिए जमीन ले ली गयी है और निर्माण के लिए व्यवस्था हो रही है । निर्माण कार्य से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ अस्थायी ढांचे पहले ही खड़े किये जा चुके हैं । सीमेंट और अन्य वस्तुओं का भंडार रखने के लिए गोदाम बनाये जा चुके हैं। परियोजना में कार्यालय तथा रिहायशी आवास का नापजोख तय किया जा चुका है और क्वार्टर तैयार करने के लिए व्यवस्था की गयी है । एक ब्लाक का नक्शा आदि बनाया जा चुका है । १५० कर्मचारी क्वार्टर बनाने के लिए निर्माण आदेश जारी किये जा चुके हैं । आगे १२० क्वार्टरों और एक फील्ड होस्टेल का काम शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फरक्का तक मुख्य सड़क और रेल संचार तथा बांयी ओर का बांध पूरा कर दिया गया है। एक किनारे पर कलकत्ते से और दूसरे किनारे पर खजूरीघाट से मालदा तक राष्ट्रीय राजपथ का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। रेलवे अधिकारियों ने परिवहन की सुविधाएं दी हैं और साज सामान का फरक्का स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गया है।

(ख) और (ग). ऐसी कोई कठिनाई नहीं है और न उसकी कोई संभावना है, जिस को दूर न किया जा सकता हो। पहले से योजना बनाकर कठिनाइयों और गतिवरोध को यथा संभव कम किया जायगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागालैण्ड में भारतीय वायु सेना के एक डाकोटा विमान का गिरना

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं। और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

नागालैण्ड में भारतीय विमान बल के डाकोटा का गिरना।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इसी विषय पर कई पूर्व सूचनायें मिली हैं। श्री हेम बरुआ, श्री अ० र० चक्रवर्ती, श्री स० मो० बनर्जी और श्री रघुनाथ सिंह ने पूर्व-सूचनायें दी हैं। सब से पहली पूर्व-सूचना श्री हेम बरुआ की थी।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: सरकार को इस सभा को बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय विमान बल का एक डकोटा विमान ७ मई, १९६२ को हमेशा की तरह साधारण तौर पर सम्भरण के लिये जाते हुए ११ बज कर ३५ मिनट पर नागालैण्ड में गिर गया था। वह विमान जोरहाट में तैनात 'स्काड्रन' का था। उस विमान पर विमान बल के चार और 'आर्मी अदर रैंक्स' के चार—इस प्रकार आठ कर्मचारी थे। आठों मारे गये। उन कर्मचारियों को उस क्षेत्र में उड़ानें भरने का पर्याप्त अनुभव था। चालक स्वयं भी उस 'स्क्वाड्रन' में २६ दिसम्बर, १९६१ में तैनात हुआ था। और लगभग २,००९ घण्टों तक उड़ानें भर चुका था। इतना अनुभव काफी होता है। अभी तक दुर्घटना के कारण का पता नहीं चला है विमान बल के नियमों के अनुसार जांच न्यायालय की नियुक्ति का आदेश दिया जा चुका है।

जांच पूरी हो चुकने और उसका प्रतिवेदन मिलने तक दुर्घटना के सम्बन्ध में अन्य कोई ब्यौरा या उसके संभावित कारण बताना संभव नहीं है। अभी तक सेना को इसके फलस्वरूप एक विमान की ही हानि का समाचार मिल पाया है। किसी असैनिक की मृत्यु या उसकी सम्पत्ति-हानि का पता अभी तक नहीं चला है। जांच इसकी भी की जायेगी।

मृत व्यक्तियों के निकट सम्बंधियों को सूचित किया जा चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या दुर्घटनास्थल का पता लगाया जा चुका है और क्या हमारे सैनिक वहां पहुंच कर शवों तथा उनके साथ की चीजों को लाने में सफल हो चुके हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** एक हेलीकोप्टर ने वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन मौसिम की खराबी की वजह से उसे सफलता नहीं मिली। उस दुर्गम और बड़े कठिन से क्षेत्र में सेना रखना बड़ी कठिनाई का काम है। उन पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे उड़ने वाले विमानों को वायु वेग के कारण नीचे उतरना पड़ता है। उसमें बड़ा खतरा रहता है। सरकार इसे समझती है। लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं।

†**श्री हेम बरूआ:** क्या डाकोटा विमान की उड़ान के समय मौसिम खराब था कौर क्या किसी ने विमान को उसकी सूचना दी थी? क्या उसके बाद भी, खतरा देखकर भी, डाकोटा विमान ने उड़ान स्थगित नहीं की थी?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस सम्बन्ध में काफी सोच विचार और अनुभव के बाद कुछ बड़े चौकस नियम बना दिये गये हैं। हर विमान को उड़ान भरने से पहले उन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। और इस मामले में वास्तव में हुआ क्या था—इसकी जांच चल रही है। इसलिये अधिक ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार यह नहीं लगता कि किसी ने कोई लातरवाही की होगी। और सम्भरण का करने वाले विमानों को खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मौसिम की खराबी के कारण ऐसी और भी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। उनको रोकने के लिये, निरापद बनाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस क्षेत्र में जितने भी उपाय किये गये हैं सभी विशेष हैं। इसलिये कि विमान को अच्छी हालत में रखने के लिये पूरी सावधानी बरती जाती है और उन शर्तों को पूरी किये बिना कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। वहां अनुभव हीन चालकों को भेजा ही नहीं जाता। लेकिन मौसिम की खराबी और भूमि के ऊबड़-खाबड़पन को कोई क्या कर सकता है। और यदि दुर्भाग्य से उस क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही करनी ही पड़े तो उसे बचने का सवाल ही नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४९२ में प्रकाशित भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१।

(दो) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५१ में प्रकाशित भारतीय तार (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६१।

(तीन) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०२० में प्रकाशित भारतीय तार (बारहवां संशोधन) नियम, १९६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—८३/६२।]

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९२ ।

(दो) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८४/६२]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लेखे का वार्षिक विवरण और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के लेखे का वार्षिक विवरण और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८५/६२] ।

———

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा करेंगे :

†**श्री मुरारका** (झूंझनू) : सरकार के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जनता पर प्रत्येक वर्ष और अधिक करों का भार लादती चली जा रही है। योजना के लिये संसाधन जुटाने और न्यूनता की पूर्ति के लिये वित्त मंत्री को नये नये कर लगाने पड़ते हैं और साथ ही मूल्यों में स्थायित्व बनाये रखना पड़ता है और अधिक उत्पादन के लिये प्रेरणा देनी पड़ती है, जिससे बचत और विनियोजनों दोनों की वृद्धि हो । इसलिये उनका काम आसान नहीं है ।

वित्त मंत्री से दूसरी शिकायत यह है कि अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर कम लगाये जाते हैं । इस बार जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, उनमें से अधिकांश का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता । चाय, माचिस, दवाइयों, इत्यादि पर लगाये गये उत्पादन शुल्क का भार सीधा जनता पर पड़ता है । उत्पादन शुल्कों के रूप में १० करोड़ रुपये ४४ करोड़ ४० लाख जनता से वसूल किये जाने हैं ; अर्थात् प्रति व्यक्ति २० नये पैसे प्रति वर्ष पड़ेंगे ।

एक मुख्य तर्क यह पेश किया जाता है कि केवल पूंजीवादी देशों में ही प्रत्यक्ष करों का अनुपात अप्रत्यक्ष करों से अधिक होता है और समाजवादी देशों में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात अधिक होता है । रूस में प्रत्यक्ष कर १५ प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर ८५ प्रतिशत है, जबकि हमारे देश में उनका अनुपात ३३ और ६७ का है । अमरीका में प्रत्यक्ष कर ८६ और अप्रत्यक्ष कर केवल १४ प्रतिशत है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

बात सीधी सी है। प्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व तभी मिल सकता है जबकि व्यक्तिगत आय अधिक हो। इसलिये भारत जैसे देश में अप्रत्यक्ष करों का ही मुख्यतः सहारार लेना पड़ेगा।

जनता ने आम चुनावों में वित्त मंत्री की अप्रत्यक्ष करों की नीति के पक्ष में मतदान किया है।

एक और शिकायत रखी जाती है कि वित्त मंत्री घाटे की अर्थ-व्यवस्था करते हैं। विकास शील अर्थ-व्यवस्था में यह अनिवार्य होता है। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यही नीति सर्वोत्तम है।

इस नीति की एक बड़ी सफलता यह है कि इतने कर लगाने के बाद भी देश का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त नहीं हो पाया है।

इस आय-व्ययक की सब से बड़ी विशेषता, इसकी वैज्ञानिकता है। इस आय-व्ययक ने कर-ढांचे को बड़े वैज्ञानिक ढंग से संवारा है। पूंजी लाभ कर इत्यादि में प्रस्तावित सुधार इसी दृष्टि से किये गये हैं। चाय के निर्यात पर शुल्क घटाने का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री का कथन है कि तृतीय योजना काल में अतिरिक्त करों से ११०० करोड़ रुपये राजस्व के रूप में वसूल करने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष के अतिरिक्त करों से उनको ४५० करोड़ रुपये पाने की आशा है। इस वर्ष उनको इससे ४०० करोड़ रुपये मिल जायेंगे। इस तरह अगले तीन वर्षों के लिये केवल २५० करोड़ रुपये बच रहेंगे।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या योजना के नाम पर अतिरिक्त करों के रूप में वसूल की गई यह राशि योजना के लिये प्रयुक्त की जा रही है? इसका समुचित ढंग से उत्तर दिया जाना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अतिरिक्त करों के रूपमें ४५० करोड़ रुपये की अनुमति राशि के स्थान पर ८०८ करोड़ रुपये वसूल किये गये थे, लेकिन उसका अधिकांश भाग गैर-विकास संबंधी कार्यों पर व्यय किया गया था। गैर-विकास सम्बंधी व्यय १९५१-५२ में ५१८ करोड़ से बढ़कर १९५५-५६ में ५८६ करोड़ रुपये हो गया था। द्वितीय योजना काल में गैर-विकास सम्बंधी व्यय केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित रूप से प्रतिवर्ष ३०० करोड़ रुपये बढ़ गया था।

इससे दो खतरे पैदा हो जाते हैं। एक तो यह कि योजना के नाम पर वसूल की गई राशि योजना के लिये प्रयुक्त न हो। दूसरा यह कि योजना के लिये प्रयुक्त होने पर भी योजना के लक्ष्य पूरे न हो पायें।

उदाहरण के लिये द्वितीय योजना काल में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य २२० लाख टन था, लेकिन केवल १३८ लाख टन ही होकर रह गया था। इसी प्रकार अन्य लक्ष्यों में भी यही हुआ। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य २५ प्रतिशत वृद्धि का था, लेकिन २० प्रतिशत वृद्धि ही होकर रह गई।

योजना की कार्यान्विति की सबसे बड़ी खामी विभिन्न परियोजनाओं की प्राप्ति की मन्द गति है और समय पड़ने के साथ-साथ परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती जाती है, क्योंकि आवश्यक सा सामग्री का मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। इसलिये सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जो ठीक समय पर परियोजनाओं का कार्य पूरा करा सके। एक मद का लक्ष्य पूरा न होने का प्रभाव दूसरे लक्ष्यों पर भी पड़ता है।

और, दूसरी कठिनाई उससे यह हो जाती है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति डावांडोल हो जाती है।

तीसरी कठिनाई यह पैदा हो जाती है कि परियोजनाओं के समय पर सम्पन्न न होने से मुद्रा मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं । इसलिये सभी परियोजनाओं को निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना अत्यावश्यक है । इसलिये एक सतर्कता समिति इसके लिये गठित की जानी चाहिये ।

मैं योजना की आलोचना नहीं कर रहा हूं । योजनीकरण तो देश के लिये अत्यावश्यक है । आज तो फ्रांस और इंग्लैण्ड जैसे देश भी योजनीकरण का सहारा लेना चाहते हैं ।

मैं समझता हूं कि सरकारी व्यय में अपव्यय समाप्त करने की काफी गुंजाइश है । लोक लेखा समिति को अपने प्रतिवेदन में प्रतिवर्ष अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है, पर उन पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता । सभी विभागों को ऐसी समितियों द्वारा बताई गई अनियमितताओं पर पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिये । लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को उचित महत्व दिया जाना चाहिये ।

जब लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति अनियमितताओं का उल्लेख करती है, तो उन अनियमितताओं की जांच के लिये दूसरी समिति नियुक्त की गई है । इस समिति ने जो मन्त्रालय ने किया है उसी का समर्थन किया है और महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति की जांच को छोड़ दिया है ।

मैं कहता हूं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के उपरान्त यदि किसी जांच की आवश्यकता हो तो किसी स्वतन्त्र न्यायिक पदाधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए । महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति, जो कि उच्चतम संस्था की प्रतिनिधि है, के प्रतिवेदनों में विभागीय समिति द्वारा परिवर्तन किये जाते हैं । यह संसदीय प्रणाली में नुक्स है जिसे दूर करना चाहिये ।

आय व्ययक में निर्यात के साथ जो व्यवहार किया गया है वह बहुत असन्तोषजनक है । केवल चाय के निर्यात को ही प्रोत्साहन दिया गया है ।

पटसन से बने हुए सामान पर उत्पाद-शुल्क लगा दिया है । इससे देश में इस समान की खपत में कमी होगी । निर्यात करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । वित्त मन्त्री ने निर्यात के नाम पर दस प्रतिशत अवहार दिया है । जो लोग लाभ पर निर्यात कर रहे हैं उन्हें तो अवहार मिलता है, जो लोग हानि पर निर्यात कर रहे हैं उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी । निर्यात को बढ़ाने पर कई समितियों और आयोगों ने बल दिया है, परन्तु आयव्ययक का यह बहुत मायूस करने वाला पहलू है ।

वित्त मन्त्री ने सरकारी उपक्रमों को उनके उत्तरदायित्वों और तृतीय पंचवर्षीय योजना को उनसे जो आशाएं हैं उन की याद दिलाई । सरकारी उपक्रमों में विद्युत् संयंत्र, सिंचाई के काम, उर्वरक संयंत्र और इस्पात संयंत्र इत्यादि हैं ।

यह कहना तो कठिन होगा कि विद्युत् संयंत्र और बिजली के काम से क्या मिलेगा, यह लगभग निश्चित है कि औद्योगिक तथा वाणिज्य उपक्रम हमारी आशाओं को पूरा नहीं करेंगे । हमारे बड़े शासकीय उपक्रमों की प्रबन्धकीय समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी । इस दिशा में बहुत कम किया गया है ।

इस समय इन उपक्रमों का प्रबन्ध सक्रिय और अवकाश प्राप्त तजरुबे वाले प्रशासकों के हाथ में है । यद्यपि वे उद्योग की गाड़ी को चलाते तो रहते हैं परन्तु प्रबन्ध के सम्बन्ध में कार्य कुशलता ही पर्याप्त नहीं है ।

[श्री मुरारका]

अन्त में मेरा सुझाव है कि योग्य सरकारी पदाधिकारियों के अवकाश प्राप्ति की आयु यथोचित समय से बढ़ा देनी चाहिये । ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने में समय लगता है । हमारे पास उन कामों को सम्भालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं । जब ये व्यक्ति सक्रिय होते हैं, उन्हें अपना जीवन अकेलेपन में व्यतीत करना पड़ता है जबकि हमें उनकी बहुत आवश्यकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : इस आय व्ययक को समाजवादी कहना उचित नहीं । यह समझदार व्यक्ति का बजट है जो कि कल्याण की बात करता है और उन लोगों की जेबों में से धन निकालता है जिनका निर्वाह कठिनाई से होता है । वह सामाजिक न्याय की बातें करता है परन्तु उसने 'धन कर' और व्यय कर को क्रमशः हटा दिया है । यह पूंजीतन्त्रीय आय व्ययक है जिसमे कहीं कहीं कल्याण का उल्लेख भी है जिसे गलती से समाजवाद कहा जाता है ।

परन्तु इस आय व्ययक और पिछले आय-व्ययक में एक अन्तर है । इसमे निगम कर, पूंजी लाभ कर और वित्त कर मे थोड़ी वृद्धि के रूप में थोड़ा प्रत्यक्ष कर लगा दिया है । इससे स्पष्ट है कि जनता अपने लिये हानिकारक नीतियों को हटाने के लिये जोर डाल सकती है और यह कदम सही ओर है ।

हमने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्यक्ष कर अधिक होना चाहिये । हमें उत्तर मिलता रहा है कि उसमें चरम सीमा तक पहुंच सके हैं । यह तथ्य कि इस विधेयक में मोरारजी देसाई जैसे वित्त मन्त्री ने प्रत्यक्ष कर लगाया है यह स्पष्ट करता है कि इसमे हम चरम सीमा तक नहीं पहुंच गए हैं, परन्तु अभी और गुंजाइश है ।

मैं व्यय कर के हटाये जाने के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । इसके लिये श्री मुरारजी देसाई ने यह कारण बताया है कि न तो यह बहुत राजस्व लाता है न यह बचत के लिये अच्छा है । श्री कृष्णमाचारी ने कहा कि इस कर के चालू होने में समय लगेगा और इसके नतीजे एक या दो वर्ष में नहीं पता चल सकते । परन्तु श्री मुरारजी देसाई ने तीन वर्ष में इसे हटा दिया है । कर से बचने की रोक के लिये इस कोशिश को भी खत्म कर दिया है ।

महारानी गायत्री देवी जी ने जो कल कहा उसके विषय में कुछ कहना चाहती हूं । उन्होंने निर्धन व्यक्तियों के कर भार के विषय में कहा और धनी व्यक्ति के कर भार के बारे में भी कहा । मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं क्या हमारे वित्त मन्त्री ने व्यय-कर को हटा कर राजाओं का पक्ष नहीं लिया । फिर उसने कहा कि निजी भत्तों को उस समय हटाया जाए जब निवृत्ति वेतन हटाए जाएं ।

जब वित्त मन्त्री जी व्यय कर हटा कर कहते हैं कि उपभोग कम करिए, क्या हम नहीं पूछ सकते हैं कि किस का उपभोग कम कराना चाहते हो ? यह उन लोगों के उपभोग के विषय में कहते हैं जो और अधिक कम नहीं कर सकते । मध्य वर्ग के लोग, छोटे छोटे व्यापारी, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, खेतीबाड़ी का काम करने वाले मजदूर और मध्यवर्ग के किसान जो कि अपने बच्चों को दो समय खाना, अपने बच्चों की शिक्षा का व्यय, अपना मकान किराया और दवाइयों इत्यादि का खर्च बर्दाश्त करने में कठिनाई समझते हैं इन लोगों के उपभोग में कमी के बारे में कहा जाता है ।

अब मैं मूल्यों के बारे में कुछ कहती हूं । सरकार को उत्पादन शुल्क और अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि उन्होंने मूल्यों को काबू में रखने से इंकार कर दिया । मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । मकानों के किराए बढ़ गए हैं और सरकार कई जगह शहर महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता नहीं देती । ऐसी परिस्थितियों में किस का उपभोग आप कम करना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्क के बारे में हर बार बताया जाता है कि उपभोक्ताओं पर उनका प्रभाव अधिक नहीं होगा। परन्तु ऐसा होता नहीं है। चाय, कपड़ा, माचिस और दूसरी वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है। यह शुल्क मालिकों की जेबों में से नहीं आता, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ पड़ता है।

अब मैं सरकार की हथकरघा उद्योग जैसे छोटे पैमाने पर उद्योगों के विषय नीति पर कुछ कहना चाहता हूं। सरकार छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों को एक स्तर पर रखना चाहती है। सरकार को छोटे उद्योगों को बन्द होने से रोकने के लिये उनकी रक्षा करनी चाहिए।

निर्यात को बढ़ाने के लिये निर्यात शुल्क कर वापसी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि हम विदेशीय विनिमय कमाने के लिये अपने निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस कर वापसी द्वारा राज्यकोष को लूटने का विचार नहीं करना चाहिये। दूसरे, चाय और पटसन जिनसे हमें मुख्यतः विदेशीय विनिमय मिलता है वह उन निर्यात करने वाली संस्थाओं पर निर्भर हैं जिन में अधिकतर विदेशीय लोग हैं। तीसरे "फौरन बौटम्ज़" हमारे व्यापार के ढंग और मुकाबला करने की शक्ति निर्णय करती हैं।

यदि विदेशीय व्यापार विदेशीय विनिमय प्राप्त करने के लिये हो, तो यह राज्य-व्यापार निगम के हाथों म होना चाहिये।

मजदूरों की मज़दूरी को मूल्यों के मुकाबला करने की शक्ति न रखने के लिये उत्तरदायी माना जाता है। वे मुनासिब लाभ हैं उन को क्यों नहीं? बीजने के समय से पहले कृषि सम्बन्धी कच्चे माल का निम्नतम मूल्य निर्णनय करने से इंकार मूल्यों में परिवर्तन का कारण है।

अब में आखिर में विकास के बारे में कहना चाहती हूं। वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को बड़ा करने पर भी हम जनता की अधिक पाठशालाओं, अधिक सड़कों इत्यादि के लिये मांगें पूरी नहीं कर सके। हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते? मुराजी देसाई ने बम्बई में कहा कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। जीवन बीमा निगम की निधि का प्रयोग करना क्यों असम्भव है? राजाओं के निजी भतों को क्यों कम नहीं किया जाता।

हमें विकास चाहिये। यदि बढ़ते हुए उत्पादन और आय से असमानताएं बढ़ती हैं तो उससे क्या लाभ? यह आय व्ययक हमारे समाज में जाग्रति और उस का शीघ्र विकास नहीं कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : (जम्मू तथा काश्मीर) : मेरे विचार में यह आय व्ययक न तो पूंजीतन्त्रीय है और न समाजवादी। कांग्रेस की नीति के अनुसार जितना समाजवादी होना चाहिए उतना नहीं है पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी करों का बोझ आम व्यक्ति और मध्यवर्ग के लोगों पर पड़ा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम समाज का समाजवादो ढांचा बनाना चाहते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। यह तभी होगा जब आय व्ययक से जनसाधारण को कुछ सहायता मिले।

तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही है। विभिन्न परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिये गये हैं। हमारी सफलता उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये।

जब किसी परियोजना को आर्थिक मंजूरी मिल जाती है तो केन्द्रीय मन्त्रालय या सरकार का कोई दूसरा विभाग अधिक कर्मचारियों की भर्ती करता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। प्रशासनिक स्तर पर केन्द्रीय मन्त्रालयों में आपस में और राज्य सरकारों के साथ बेहतर मेल-जोल होना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

हमारे प्रधान मन्त्री ने बारम्बार इस बात पर बल दिया है कि हमारे समाज का ढांचा समाजवादी होना चाहिये। परन्तु प्रधान मन्त्री जी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्हें विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की ओर ध्यान देने के लिये बहुत कम समय मिलता है। हमें उप प्रधान मन्त्री का स्थान बनाना चाहिये जो केवल विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ही अपना पूरा समय लगाएं। योजना और उसके क्रियान्वयन में अधिकतर मेल जोल होना चाहिये।

महारानी गायत्री देवी जी ने जनसाधारण के प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है। मैं इन राजाओं से पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी साम्राज्य मे वे रियासतों के मालिक थे तब उनके हृदय में जनता के लिये सहानुभूति नहीं घुसी। अब उन्होंने देखा कि देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है और हमें कोई नहीं पूछेगा तो उन्होंने लोगों से सहानुभूति प्रकट करनी आरम्भ कर दी। मैं श्रीमती गायत्री देवी जी कहता हूं कि चूंकि अब वह जनता की प्रतिनिधि हैं, जयपुर के महाराजा और उनके परिवार के अन्य सदस्य अपने निजी थेलियों को छोड़ दें।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री जी से कहता हूं कि करों को न बढ़ाया जाए बल्कि प्रशासनिक व्यय में कुछ कमी के साधन ढूंढे जायें ताकि जनसाधारण को कुछ सहायता मिल सके।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्हों ने आय-व्ययक तैयार करने में अत्यधिक कर लगाने और घाटे की अर्थ व्यवस्था के बीच का रास्ता निकाला है, क्योंकि इन दोनों तरीकों से मुद्रास्फीति बढ़ती। श्री मोरारजी देसाई ने १४७ करोड़ रुपये का कुल घाटा होते हुए भी हमें संतोष का मौका दिया है।

कुछ सदस्यों ने विदेशी सहायता लेने का विरोध किया है। मैं समझती हूं कि कम विकसित देशों के लिये विदेशी सहायता अत्यधिक आवश्यक है। मैं उन देशों की आभारी हूं जिन्हों ने हमें सहायता दी है।

यह बहुत हर्ष का विषय है कि अप्रत्यक्ष करारोपण का अनुपात पहली बार कम हुआ है और इस के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

निगम कर में वृद्धि का भी स्वागत है। पूंजीपतियों के लिये ५ प्रतिशत अधिक निगम कर देना कठिन नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगले वर्ष इसे कुछ और बढ़ा देना चाहिये।

वित्त मंत्री पूंजी लाभ कर और सम्पत्ति कर बढ़ा के लिये भी बधाई के पात्र हैं। किन्तु मैं उन से व्ययक हटाये जाने के मामले में सहमत नहीं हूं। यद्यपि इस से आय कम होती थी, फिर भी इसे जारी रखना चाहिये था।

मेरे विचार में केवल करारोपण द्वारा देश की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। हमारी कठिनाइयां सामाजिक असमानताओं प्रशासननीय अनियमितताओं और कार्यपालिका की अक्षमता के कारण उत्पन्न होती हैं।

मेरा सुझाव है कि उद्योग के असंगठित क्षेत्र में और कृषि के संगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये। उद्योग के संगठित क्षेत्र में सामहिक सौदाबाजी और मजूरी की दरों के प्रमापीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिये। दूसरे निचली स्तर के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने चाहियें। निजी व्यापार में वेतनों पर भी नियंत्रण होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

हमारे लाखों लोगों को सरकार की सामाजिक कल्याण नीतियों के द्वारा ही आर्थिक दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

कर तो हर वर्ष लगाये जाते हैं किन्तु सरकार को यह भी मालूम होना चाहिये कि करापवंचन कितना हो रहा है । करापवंचन करने वालों के लिये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिये ।

पिछले कुछ वर्षों में बेरोज़गारी में ३५ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है । अनुसंधान से मालूम हुआ है कि न तो कृषि क्षेत्र में और न शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के साधन बढ़े हैं । इसलिये सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर जोकि अधिक श्रमिक नियोजित कर सकते हैं, अधिक ध्यान देना चाहिये ।

कहना पड़ता है कि सरकार अपने सब कोशिशों के बावजूद मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकी । हमारी योजनाएं चाहे कितनी बड़ी हों, मूल्य नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जन साधारण को खाना-कपड़ा और मकान के रूप में जो कुछ मिले, वहीं सब से बड़ी बात है ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन् के बहुत से माननीय सदस्यों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बजट प्रस्ताव पेश करने के लिये बधाई दी है । मैं भी उन बधाई देनें वालों में शरीक हो जाती हूं ।

यह सही बात है कि हमारे देश में बहुत काम हो चुका है और अभी भी हो रहा है । लेकिन कुछ लोग जोकि अंधे हो कर देखते हैं उन को देश में कोई तरक्की होती नहीं दिखाई देती ....

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : क्या किसी आनरेबुल मेम्बर्स को अन्धा कहना उचित है ?

श्रीमती लक्ष्मीबाई : वे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है मगर ऐसी बात नहीं है। देश में काफी काम हुआ है और देश ने प्रोग्रेस भी की है । लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि इस से ज्यादा अच्छा काम हो सकता था और इस के मुकाबले देश अधिक तरक्क कर सकता था बशर्त्ते कि ऐसी बातें जोकि आनरेबल मेम्बर्स कहते हैं और वह सही भी है उन को सरकार मानती और उस के अनुसार अमल करती ।

"जनवाक्यं कर्त्तव्यं"

ज्यादा लोग जो कहते हैं उस को मानना चाहिये और उस को दृष्टि में रख कर अपना कानून बनाना चाहिये । अब इतना बड़ा हाउस बैठता है और कई बातों की सूचना देता है लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है । इस में गवर्नमेंट की गलती मैं नहीं समझती क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि यहां एक प्लानिंग कमिशन बैठा है, बहुत बड़े तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, उन के मशविरे में कुछ गलती है, मैं ऐसा महसूस करती हूं । जितना वह प्लान करते हैं उस में से ६० परसेंट प्लानिंग तो हमारे देश के लिए मुफीद ही नहीं होती है । प्लानिं कमिशन वाले बैठ कर सारे प्लान्स बनाते हैं लेकिन खेद का विषय है कि वह बाहर के मुल्कों बैकग्राउन्ड में इन को बनाते हैं । सब कुछ वहां की किताबों से ले कर लकीर के फकीर की मानिन्द बनाते हैं लेकिन यहां की हालत देख कर नहीं बनाते हैं । फ़र्स्ट प्लान चला गया, सेकेंड प्लान चला गया और अब थर्ड प्लान हमारे सामने आया है । इस की [illegible] आउटलाइन बनाते वक्त सब एम० पीज़० को बुलाया और डिसकशन भी किया । कई एक [illegible] उस में रक्खी गईं मगर प्लान में उन को इम्पलीमेंट करने के लिये तैयार नहीं होते हैं । यहां की हालत को ध्यान में न रख कर बाहर के मुल्कों की नकल करते हुए जो प्लान रखा जायगा जाहिर है कि उन प्लान्स में डिफैक्ट्स रहेंगे । मैं अपील करती हूं कि आप यह बातें उन तक पहुंचा दीजिये ।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

प्लानिं कमिशन वालों को इस मुल्क की हालत को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिं करनी चाहिये। उन को खास तौर से इस देश के एग्रीक्लचरिस्ट्स लोगों अर्थात् देहात में बसने वाली जनता की जरूरियात को ध्यान में रख कर अपने प्लान्स बनाने चाहिएं।

अब मैं पंचायत समितियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। पूज्य बापू ने जिस राम-राज्य का स्वप्न देख था उस में पंचायतों का प्रमुख स्थान था। पंचायतों का हमारे देश में बहुत महत्व है और यह एक बहुत अच्छी चीज है। असली लोकतंत्र के ढांचे में पंचायतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे गांवों में जो पंचायत समितियां स्थापित हैं वे आमा तौर पर अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि उन को तजुर्बा नहीं है और पढ़े लिख नहीं हैं इसलिय कभी कभी उनके काम में गड़बड़ हो जाया करती है। जहां तक मेरे अन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है यह पंचायतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इन ग्राम पंचायतों की बदौलत हम को जनरल एलेक्शन्स में बहुत मदद मिलती है। पंचायतों से काफी गड़बड़ हमारी कम हो गई है।

हमारे आनरेबुल दोस्त बाज़ दफा एसी बातें कह देते हैं और वह इतनी बेहूदा बात होती हैं कि जिस से काफी तकलीफ हमें पहुंचती है। हमारी जो नीति होती है व प्लान होता है उस को वे लोग बेढंगा बताते हैं और उस का जवाब हमें देना पड़ता है। जाहिर है कि हम गैर जिम्मेदारी से उन की बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं। अब हमारे वह आनरेबुल दोस्त काफी गैरजि मेदाराना बात करते हैं लेकिन कुछ बात जो वह कहते हैं सत्य भी होती हैं और उन बातों का हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है और उन का जवाब हमें नहीं मिलता है।

यह सही है कि आप ने गांवों में पंचायतों को बहुत पावर्स दी हुई हैं लेकिन वहां की हालत क्या है? दुकाने तो खुली हुई हैं लेकिन वह खाली हैं, सामान नहीं है, पैसा नहीं है। प्लान की सेंकड स्टेज से हम बाहर आ गये हैं लेकिन वहां पर पैसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन है, जीप्स हैं, एक्सटशन आफिसर्स हैं मगर एग्रीक्लचरिस्ट्स को मदद करने के लिय वहां पर फंड्स नहीं हैं। इसलिय पंचायतों को खाली पावर देने से ही काम चलने वाला नहीं है। मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगी कि वह देखें कि पावर्स के साथ साथ इन को जरूरी फंडस भी मिल और मेरा सुझाव है कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स का जो टोटल रवेय हो उस में से कम से कम २५-३० फीसदी पैसा पंचायतों को जाना चाहिये ताकि वह ठीक से काम कर सक। मैं रहूं या न रहूं लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि यदि यह ग्राम पंचायत अच्छे काम करेगी, जिला परिषद कायम कर के उन के द्वारा काम चलाया जायेगा तो १०–२० ाल के बाद म० पीज़० की तादाद कम की जा सकेगी, इतनी तादाद नहीं रह जायेगी और इतना खर्चा यहां करने की जरूर नहीं होगी गांवों की पंचायतों और जिला परिषदों को ताकत देने से ही सच्चा प्रजातंत्र इस देश में स्थापि होगा। हमारे देश में जो प्लानिंग होता है, उस में बहुत ग़लतियां हैं। प्लानिं कमीशन ने कहा है कि थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के टारगट्स पूरे होने पर गांवों में ५,३०० की जन-संख्या पर एक इंजीनियर, ५,००० पर एक डाक्टर और पच्चीस हज़ार पर एक एग्रीकल्चरल ग्रेज्युट मिलेगा। अभी तक तो तीस फ़ीसदी टारगट्स भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जब थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के टारगट्स पूरे हो जायेंगे, तो पच्चीस हज़ार की जन-संख्या पर एक एग्रीलकल्चरल ग्रैज्युएट होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एगीकल्चर इतना तुच्छ सबजक्ट है। वह एक टैक्निकल सबजक्ट है। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि जो लोग ग़रीब हैं और जिन के पास दिमाग़ नहीं है एग्रीकल्चर उन के हाथ में रह गया है, जिस का परिणाम यह है कि हम को बाहर के मुल्कों से अन्न मंगाना पड़ रहा है। अगर एग्रीकल्चर का काम साइंटिफ़िक तरीके से किया जाय, तो प्राडोक्शन अच्छा होगा और हम को अपने देश के लिये बाहर से अन्न लाने की ज़रूरत

नहीं पड़ेगी । अगर यहां पर किसानों को ठीक प्रकार से मदद मिले, उनको समय पर पानी और खाद दी जाय, उन को सुधार सुधरे हुए तरीकों से बुवाई, कटाई और कीड़े आदि मारना सिखाया जाये, तो हमारे देश में पर्याप्त अन्न पैदा हो सकता है । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने भी कहा है, आखिर हम कब तक बाहर का गहुं, चावल और नमक आदि आते रहेंगे ? प्लानिंग कमीशन से यह बात पूछने वाला कोई नहीं है ।

प्लानिंग कमीशन वाले यहां बैठ बैठ सीलिंग निश्चित करने का कानन बनाने की बात करने हैं । हिन्दुस्तान में सब से पहले हैदराबाद स्टेट में हम ने सीलिंग लगाई थी, क्योंकि वहां पर उस की ज़रूरत थी । हम ने यह तय किया था कि एक एग्रीकल्चरिस्ट की, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बैसिक इनकम ८०० रुपये सालाना हो और सीलिंग उस से लगभग साढ़े चार गुना, अर्थात ३,६०० रुपये सालाना हो, चाहे बड़ी से बड़ी फ़ैमिली हो । लेकिन इस के मुकाबले में हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन में एक एक साहब ढाई ढाई हज़ार रुपय महीना पाते हैं । वे दूसरों के बारे में तो सीलिंग लगा लगाने का मश्वरा देते हैं, लेकिन अपने लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं । हम देखो हैं कि प्लानिंग कमीशन पर होने वाला खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है । १९५३ में वह १३,२५ हज़ार रुपये था और १९५७-५८ में वह बढ़ते बढ़ते ६७,६१ हजार रुपय हो गया । अब जो बजट हमारे सामद रखा गया है, उस में उस के लिये ९५,२३ हज़ार रुपये रखा गया है, जिस का अर्थ यह है कि १९५३ से आज तक प्लानिंग कमीशन का खर्च आठ गुना बढ़ गया है ।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि इस देश का ६४ से ७० परसेंट रेवेन्यू एग्री कल्चर से आता है, लेकिन एग्रीकल्चर का काम करने वालों के लिए ३,६०० रुपये सालाना आमदनी की सीलिंग रखी गई है, जब कि यहां पर एक आदमी को तीन हज़ार तक वेतन मिलता है । जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, सब ैसा चोरी हो जायेगा, पटवा ी और पटेल सब खा जायेंगे । ऐसे प्लान यहां पर बनाये जाते हैं । ये बातें यहां पर कहते हु ए मुझे कोई शक या शर्म नहीं है । विरोधी पक्ष वाले जो कुछ कहते हैं, उन की बात ो छोड़ दीजिये, लेकिन हम लोग अपने तजुर्बे के आधार पर जो कुछ कहते उस को तो सरकार को सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा, लेकिन वह सुनती नहीं है । इस से हम को बड़ा दर्द होता है ।

जहां तक एडूकेशन का सम्बंध है, उस के क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ है । कहीं मल्टी-परपज़ स्कूल हैं, ो कहीं बेसिक स्कूल हैं, कहीं इंगलिश स्कूल हैं, कई प्रकार के स्कूल हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ीक प्रकार से नहीं हो रही है । आज स्थिति यह है कि बहुत सुन्दर प्लान चल रहे हैं, कांग्रेस बड़ा काम कर रही है और सरकार में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देने वाला और बताने वाला कोई नहीं है । आज उन को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है । सब लोग गड़बड़ करते रहते हैं । यहां से ले कर वहां तक चोरी होती है और सच्चे दिल से काम कोई नहीं कर रहा है । इस लिए बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है ।

जब मैं स्टुडेंट थी, ो हमारे यहां आन्ध्र प्रदेश में लोग कहा करते थे कि इंगलिश कमज़ोर है, उसकी ट्यूशन लगानी चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्नेकुलर लैंग्वेजिज़ में, तेलगू और कन्नड़ में, ट्यूशन लगानी पड़ती है । इस का क्या कारण है पहले इंगलिश में बच्चे कम परसेंटेज में पास होते थे, लेकिन आज वर्नेकुलर लैंग्वेजिज़ में भी कम परसेंटेज में पास होते हैं । मैं कहना चाहती हूं कि एडकेशन ही हमा ी सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद है । उस से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और देश के अच्छे और योग्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है । दूसरे मुल्कों में एडकेशन पर जितनी तवज्जह ी जा ी है, उतनी हमारे मुल्क में नहीं ी जा रही है ।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

हमारे बीच में जो सब से खतरनाक और शैतान चीज है, वह है बाजार-भाव और कोई उस को रोकने की कोशिश नहीं करता है। मैं गांव-गांव फिरती रहती हूं हमारे यहां बहुत गुड़ बनता है और उस के अलावा आलू, प्याज और मिर्च भी पैदा होते हैं। जब फ़रवरी में, इलैक्शन से कुछ पहले, हम किसानों के पास गये, तो हम ने देखा कि उस समय, जब कि गड़ बनता है, बीस से पच्चीस रुपये प्रति पल्ला, जो कि १२० सेर का होता है, गुड़ का भाव है। किसान को कटाई मजदूरी और गुड़ की पकाई पर बहुत खर्च करना पड़ता है। वह बेचारा रोता है। चूंकि वह पहले ही पैसा एडवांस लेता है, इस लिए कर्ज देने वाला अपना पैसा लेने के लिए उस के पीछे पीछे भागता है। तुरत पैसा प्राप्त करने के लिए किसान सारा गुड़ बाजार में बीस, पच्चीस रुपये के भाव पर बेच देता है और रात-दिन गुड़ बाजार में जाता रहता है। मैं ने उस समय देखा कि किसानों ने गन्ना काटा नहीं और बैलों के खाने के लिए छोड़ दिया। जब मैं ने इस का कारण पूछा, तो मुझे बताया गया कि हम को गुड़ पकाने का बर्तन नहीं मिलता, इस लिए गन्ना बैलों के लिए छोड़ दिया। यही हालत मिर्च वग़ैरह की है। बाजार में गुड़ आने के बाद उस को एक दो महीने गोदाम में बन्द रखा जाता है और फिर उस का भाव ७०, ७५ रुपये तक बढ़ा दिया जाता है। यह खतरा शैतान है। उगाने वाले और खाने वाले को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन बेचने वाले की जेब भर जाती है।

मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूं कि सब लोग यही कह रहे हैं कि प्राइसेज पर कंट्रोल किया जाये, लेकिन वह बार बार कहते हैं कि प्राइसेज में राइज नहीं हुआ है। लेकिन वह इस बारे में क्या जानते हैं? वह कभी कुछ खरीदते नहीं हैं। उन को मालूम नहीं है कि बाजार में क्या चीज मिलती है। तीन साल पहले जब मैं दिल्ली आई थी, तो साबुन दो रुपये १२ आने के भाव पर मिलता था, लेकिन आज वह चार रुपये चार आने में मिलता है।

मैं कहना चाहती हूं कि पैसा प्राप्त करने के लिए सरकार सब तरह के टैक्स लगाये, लेकिन उस पैसे को खर्च करते समय पूरा ध्यान रखे। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वेस्टेज होता है। सेक्रेटरीज और दूसरे बड़े बड़े अफ़सर प्लेन और रेल में सफ़र करते हैं, लेकिन बैठ कर काम करने वाले कम हैं। एक्जीक्यूशन कम होता है।

मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं। वह बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। टैक्सिज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि भ्रमर एक एक फूल से पराग ले कर उस की हनी, शहद, बनाता है। यह आवश्यक है कि खर्च करते वक्त पैसे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज लाखों करोड़ों रुपये की स्कीमें बनती हैं, जिन के लिए पैसा पंचायतों से दिल्ली तक पहुंचता है। पुराने जमाने में नदियां नीचे जाती थीं, लेकिन आज वे नीचे से ऊपर जाती हैं--पैसा नीचे से ऊपर जाता है। अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि खर्च करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ताकि वेस्टेज कम हो।

धन्यवाद।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : हमारे देश में पदाधिकारियों का बर्ताव उत्तरदायित्व से रहित है और उस में संविधान के लिए आदर नहीं है। हम देखते हैं कि लोक सेवा समिति के प्रतिवेदन, उन की सिफारिशों और सुझावों की अवहेलना की जाती है। ऐसा ७ साल से चल रहा है।

आय-व्ययक का यह ध्येय होता है कि संसद का नियंत्रण रहे। सरकार द्वारा किया गया व्यय निश्चित ढंग में हो और निश्चित प्राधिकारी द्वारा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस अपवित्र ढंग से पदाधिकारी संविधान की अवहेलना करते हैं उसे समाप्त किया जाये। पया किसी एक विभाग का नहीं होता। इस पैसे का हिसाब संसद् को देना होता है और यह निश्चित ढंग और निश्चित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए।

हमें हर कोई यह कहता है कि हम देश के कल्याण कार्यों के लिये हम अपनी कमर कसें। हम इस से भी अधिक कर सकते हैं। हम अपने देश के लिए जीवन त्याग कर सकते हैं। परन्तु यह सुझाव उन व्यक्तियों से आते हैं जो स्वयं विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

विदेशों में हमारे दूत मण्डलों के बर्ताव की ओर देखिए। यदि हम लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों को देखें तो पता चलेगा कि हमारे इन दूत मण्डलों में किस प्रकार धन खराब किया गया।

दूत-मण्डलों में बहुत खर्च किया जाता है। बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य साज सामान का प्रयोग पदाधिकारियों के घरों में होता है। कोई किराया नहीं लिया जाता। गलत हिसाब बताया गया है और गलत बिल दिये गये हैं। इस प्रकार के कई आरोप हैं। इस बीमारी को समाप्त करना चाहिए। यदि ऐसे पदाधिकारी हैं जो संविधान और संसद् की अवहेलना कर सकते हैं और वे स्वेच्छा काम करना चाहते हैं तो वे नौकरी में रखे जाने के योग्य नहीं हैं।

अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि हमारा व्यय आमदनी में से होना चाहिए और इसलिए वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कर लगाने चाहिएं। कर लगाने से पूर्व जो फिजूल का सरकारी खर्च है उसे बन्द करना चाहिए। यदि हम विभिन्न सरकारी प्रतिवेदन और उपलब्ध जानकारी को देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम अपने देश में फिजूल खर्च करते हैं।

इस के कई उदाहरण में, परन्तु मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा। हम ने चांदी के संशोधन का कारखाना आरम्भ किया है। यह कारखाना पुराने सिक्कों से चांदी निकालने के लिए है। इस की क्या आवश्यकता थी। सिक्के बाजार में उस में जितनी चांदी है उस के मूल्य पर बेचे जा सकते थे। अब जब सिक्के समाप्त हो गये हैं तो इस कारखाने का क्या किया जाये? जिस पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं।

'इण्डियन एयरलाइन्ज़ कारपोरेशन' में १२ 'वाईकिंग' वायुयान जो कि ३,३५,००० रुपये प्रति वायुयान के मूल्य से खरीदे थे, २०,००० रुपये प्रति वायुयान के मूल्य पर बेच दिये गये। सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। ये पदाधिकारी संसद् सदस्यों से अपने को अधिकतर योग्य समझते हैं। इन के इस रवैये को ठीक करना चाहिए।

अब रहा प्रश्न संसद् के नियंत्रण का। कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने लेखे नहीं प्रस्तुत किये हैं। १९५३ से उन के लेखों का परीक्षण करने की कोशिशें असफल रही हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से कहता हूं कि जो रुपये पैसे के मामले में गड़बड़ें होती हैं, उन को बन्द करना चाहिए यदि देश की प्रगति में बाधा न डालनी हो।

प्रत्येक स्थान पर ऐसी मिसालें मिलेंगी, यहां रुपये पैसे के मामले में गड़बड़ होती है। जो पदाधिकारी इन के लिए उत्तरदायी हैं वे तो ऐश करते हैं और सारा बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है।

[illegible] श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि देश में व्यापार पर एकाधिकार होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु राज्य व्यापार निगम द्वारा मिलनी चाहिए, साम्यवाद का ध्येय गरीब लोगों को गुलाम बनाना है। यह नहीं होगा। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या सरकार द्वारा व्यापार के

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

एकाधिकार से कुछ लाभ भी है । क्या राज्य व्यापार निगम और इण्डियन एयरलाइन्ज कारपोरेशन जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं से कुछ लाभ हुआ है । इन से बहुत कम लाभ होता है । जब कि इतना रुपया खर्च करके उन से लाभ उठाना चाहिए, उन से तो लाभ होता नहीं, कर लगाये जाते हैं या बढ़ाये जाते हैं ।

मुझे कर से आपत्ति नहीं परन्तु जो रुपये जान बूझ कर निष्फल जाते हैं उन पर मुझे आपत्ति है और इस का उत्तरदायित्व कुछ एक पदाधिकारियों पर है । बोझ गरीबों पर पड़ता है । छोटी छोटी वस्तुओं पर कर लगाये दिये गये हैं जिस से छोटे उद्योगों को हानि पहुंची है ।

वित्त मंत्री जी ने निगम कर को बढ़ाने का सुझाव दिया है । यह कर सामान्य अंशों के लिए घातक होगा ।

राजाओं के निजी भत्तों के बारे में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जी ने जिक्र किया था । इस बारे में मैं यह कहता हूं कि हमें निजी भत्तों को इसलिए नहीं विरोध करना चाहिए कि वे राजाओं को दिये जाते हैं । इन भत्तों के बारे में इस सदन में आश्वासन दिये गये थे । हमें उन्हें पूरा करना है ।

श्री गणपति राम (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का न्याय है कि किसी के लिए तो ४० मिनट दिया जाये और किसी के लिए एक मिनट भी नहीं । अब हमारे सरीख लोग भी बजट पर बोलना चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आया कि किसी को पार्टी लीडर होने के नाते समय दिया जाये, किसी को फार्वर्ड बैंचेंस होने के नाते समय दिया जाय, और किसी को लेडी होने के नाते समय दिया जाय लेकिन हम बैंकबेंचर्स को समय न मिले । इस लिए मैं चाहूंगा कि हम बैंक बेंचस को भी समय दिया जाय । चूंकि यह कौमन लोगों का बजट इस लिए कौमन लोगों को बोलने का भी अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर विषय की ओर सदन् का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं । भारतीय जनता ने राज्य-क्रांति के द्वारा भारतवर्ष की आजादी हासिल की । महात्मा गांधी के आशीर्बाद से यह भूखंड न्यास के रूप में थाली के रूप में हमें प्राप्त हुआ है । लेकिन पूर्व से एक भंयकर खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे जाहिर होता है कि हमारे भूखण्ड का एक बहुत बड़ा भाग शायद १० वर्ष के बाद हमारे हाथ में नहीं रहेगा । मेरा लक्ष्य असम की तरफ है । सन् १९५१ में असम की आबादी ९०,४३,७०७ थी । जब कि आज असम की आबादी १ करोड़ १८ लाख है अर्थात् दस वर्ष के अंदर २८ लाख १६ हजार आबादी असम की ज्यादा हुई । १९६१ की सेंशस रिपोर्ट से यह बात जाहिर होती है कि असम की आबादी ३४·३ परसेंट ज्यादा हुई है । लेकिन इसी के साथ सेंशस की रिपोर्ट को देखने से आपको मालूम होगा कि मुस्लिम आबादी ३८ परसेंट बढ़ी और बाकी आबादी सिर्फ ३४ परसेंट बढ़ी । सन् १९५१ में जहां हिन्दुओं की आबादी ६५ परसेंट थी, मुसलमानों की आबादी २२ परसेंट थी, ईसाईयों की आबादी ६ परसेन्ट और ट्राईबल एरियाज की आबादी ५·८ परसेंट थी १९६१ में हमारे कैलकुलेशन के अनुसार क्योंकि सेंशस में जाति के अनुसार आंकड़ नहीं दिय गय हैं, हिन्दुओं की आबादी ६१ परसेन्ट हो गई अर्थात् ४ परसेंट कम हो गई । मुसलमानों की आबादी २६ परसेंट हो गई यानी २२ परसेंट से ४ परसेंट ज्यादा हो गई । लेकिन बंगाल के पेपर्स आजकल जैसा दे रहे हैं उसके अनुसार देखा जाये तो होता यह है कि ५७ परसेंट हिन्दुओं की आबादी है और ३० परसेंट मुसलमानों की होगी । चूंकि यह बंगाल के पेपर्स हैं इस लिए मैं यह नहीं कह सकता कि वे ठीक हैं या नहीं लेकिन मैंने जो हिसाब लगाया है उसके अनुसार हिन्दुओं की आबादी ६१ परसट और मुसलमानों की आबादी २६ परसेंट है । इसी हिसाब से अगर आबादी

ज्यादा होती गई तो क्या यह होगा कि सन् १९७२ में जाकर जब दूसरा सेंशस होगा तो मुसलमानों की आबादी ४० परसेंट हो जायेगी और हिन्दुओं की आबादी ४७ परसेंट हो जायेगी .

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : इस से बजट में क्या होगा ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं बजट पर चर्चा के दौरान में किसी भी विषय पर बोल सकता हूं । यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है ।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : आप सही कहते हैं ।

इसके साथ ही साथ जो ११ जिले असम के हैं उनमें से ४ जिलों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं । वह जिले हैं नौगांव, ग्वालपाड़ा, दोरांग और सिल्चर । यहां की ४० परसेंट आबादी मुसलमान हो गई । आप सेंशस की रिपोर्ट उठा कर देखिये कि क्या कहा गया है । अब अगर इन ४ जिलों में ४० परसेंट मुस्लिम आबादी हो गई, नेफा एरिया असम से मिला हुआ है और उसका क्या हश्र होने वाला है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं । एक तरफ तो नागालैंड की डिमांड है । और दूसरी तरफ यह मुस्लिम इनफिलट्रेशन है। फल इसका यह होगा कि भारत की आजादी के साथ जो भूखंड हमें प्राप्त हुआ था वह भूखंड हमारे हाथ में रहेगा या नहीं इसमें हमको संदेह मालूम होता है । मेरे संदेह का कारण क्यों है इसको मैं उदाहरण देकर बतलाता हूं कि बर्मा ने सन् १९४७ में अपने को कांस्टीट्यूशन में एक सैकुलर स्टेट डिक्लेयर किया। लेकिन वर्मा में अराकान एरिया ठीक ईस्ट पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और वहां पर मुस्लिम इनफिलट्रेशन जसा कि ईस्ट पाकिस्तान से वस्ट पाकिस्तान में हो रहा है असम में भी उसी प्रकार का इनफिलट्रेशन प्रारम्भ हुआ । उसका फल यह हुआ कि अराकान में मुजाहिद पार्टी संगठित की गई । उस ने वर्मा गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि चूंकि अराकान एरिया में हमारी आबादी ४० परसेंट से कुछ ज्यादा है लिहाजा हम वर्मा के साथ नहीं रहना चाहेंगे । या तो हमारी एक सैप्रेट स्टेट होगी या फिर हम ईस्ट पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं । यूक्रन के लोगों ने जैसे कि वर्मा में एक आवाज उठाई कि हमारी एक सैप्रेट स्टेट होगी उसी प्रकार से मुजाहिद लोग ने आवाज उठाई कि वर्मा में हमारी अलग स्टेट होगी । उसका फल क्या हुआ यह आप अखबारों में देखते रहते हैं । रेलगाड़ियां चलना असम्भव हो गया और रायट्स हुए । इस सब का परिणाम क्या हुआ ? लास्ट इयर वर्मा ने डिक्लेयर किया कि वह एक नान सैकुलर स्टेट है । जो स्टट सन् १९४७ में सैकुलर स्टेट थी वही बर्मा सन् १९६१ में नौन सैकुलर स्टेट हो गई । वर्मा वालों ने इस खतरे को देखा कि अगर हम इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तो इस से भी बुरा हश्र होने वाला है । इसका नतीजा यह होगा कि वर्मा का एक तिहाई हिस्सा जो कि वर्मा का भाग है वह वर्मा के हाथ से निकल जायेगा । या तो सैप्रैट स्टेट होगी या वह पाकिस्तान में जाकर शामिल हो जायेगा ।

जो लोग वर्मा के इतिहास को जानते हैं, . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बजट के बारे में कुछ कहें ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह सब कुछ बजट के बारे में ही है । जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसका सम्बन्ध मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स से है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस चर्च में बर्मा के विषय में कहना उचित नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो कुछ बर्मा में किया है, वह हिन्दुस्तान में भी वही करने जा रहा है। इस लिए उस खतरे से हमको सावधान रहना चाहिए। मैंने आपके सामने एक कन्क्रीट एग्ज़ाम्पल रखी है।

इसके अलावा बर्मा में एक और घटना हुई। यहां से, पाकिस्तान से लोग वहां गए, उन्होंने बर्मी औरतों से शादियां कीं और उनके बाल बच्चे हुए, जिनको वे छोड़ कर चले आए। इस प्रकार जब उनकी जन-संख्या काफी बढ़ गई, तो वह जहरबादी कौम कहलाई। उन लोगों ने बाद में एक सेपरेट स्टेट की आवाज़ उठाई। पारसाल बर्मा में हिन्दू-मुस्लिम रायट हुए—बौद्ध लोगों और मुसलमानों में नहीं बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानों में बड़ पैमाने पर रायट हुए।

आज ईस्ट बंगाल से आसाम में इतने ज्यादा लोग चले आ रहे हैं। हमें उनको रोकना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उन लोगों को अपने देश में आने से रोक नहीं सके हैं।

इसके बाद आप देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान से रोज़ १२५, १४०, २००, ३०० लोग, जो कि माइनारिटी कम्यूनिटी के हैं, बाकायदा वैस्ट बंगाल में चले आ रहे हैं। उसका फल क्या हुआ ? जैसा कि आज कल बंगाल के अखबार बहुत ज़ोरों से कह रहे हैं, उसका फल यह हुआ कि मालदह में रायट हुआ और पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर वहां पर गए। इस रायट के बाद एक महीने के अन्दर ईस्ट पाकिस्तान में गोपालगंज, ढाका, राजशाही, पावना, रंगपुर और बरीसात आदि जगहों पर रायट हुए। लेकिन वहां जाने के सम्बन्ध में हमारे हाई कमिश्नर को वह सहूलियत नहीं दी गई, जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को दी गई। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि १९५० में जो नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ था, वह आज लागू है या नहीं। उस पैक्ट का प्रीएम्बल इस प्रकार है—

"अल्प-संख्यक रक्षा के लिए अपनी सरकार की ओर देखें।"

उस पैक्ट में एक धारा यह भी है कि अगर अल्प-संख्यकों पर अत्याचार हो, तो पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान में जा सकते हैं और हिन्दुस्तान के लोग पाकिस्तान में जा सकते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में खुदा-न-खास्ता कोई रायट होता है, तो यहां की सरकार की तरफ़ से जो सहूलियतें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को दी जाती हैं, वे सहूलियतें ईस्ट पाकिस्तान में, जहां कि सात जगह रायट हुए, हमारे हाई कमिश्नर को क्यों नहीं दी जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि अगर उनको वे सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं, तो रेसीप्रोकल बेसिस पर हम को भी उसी नीति का अनुकरण करना चाहिए।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : वे इस विषय पर मार्ग प्रदर्शन करें। माननीय सदस्य बजट पर नहीं बोल रहे। वह ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिन पर विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय बोला जा सकता है।

†**श्री श्रीनारायण दास**: सामान्य चर्चा से पूर्ण अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सामान्य चर्चा मे सदस्यों को आर्थिक नीति और कर सम्बन्धी मामलों पर ही बोलना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बर्मा के बारे में कहने का इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे बजट पर ही बोलें। माननीय अध्यक्ष जी ने पहले ही वे सब बातें स्पष्ट कर दी हैं जो कि बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान में कही जा सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह: गोआ के करीब बीस हज़ार लोग पाकिस्तान में हैं। उन लोगों को पाकिस्तान सरकार की तरफ़ से यह अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो वे पाकिस्तान के सिटीज़न हो जायें, या उन को पाकिस्तान को छोड़ना होगा। दो तीन दिन पहले इस सदन में इस बारे में सवाल भी उठाया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान के सोलह हज़ार नैशनल सीमैन के तौर पर कलकत्ता में रजिस्टर्ड हैं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने यहां रहने वाले गोआ के लोगों के बारे में इस प्रकार का कानून बनाती है कि या तो वे पाकिस्तान के सिटिज़न्ज़ हो जायें, या उन्हें पाकिस्तान छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो फिर हमें भी ईस्ट पाकिस्तान के सोलह हज़ार लोगों के बारे में यह कानून बनाना चाहिये कि या तो उनका हिन्दुस्तान का नैशनल होना होगा, या उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ना चाहिये।

अब मैं बजट पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तेरह मिनट ले चुके हैं। अब दो मिनट में वह ख़त्म कर दें।

श्री रघुनाथ सिंह: जहां तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है, १९५२ में, जब कि यह देश रीपब्लिक बना, हमारा एक्सपोर्ट ७२९ करोड़ और इम्पोर्ट ९७१ करोड़ का था, जिन में २४२ करोड़ रुपये का गैप था। उस के बाद १९६० में हमारा एक्सपोर्ट ६२३ करोड़, एम्पोर्ट १,०११ करोड़ और इस प्रकार गैप इन दि वैलेंस आफ़ ट्रेड ३८८ करोड़ का हो गया, जब कि इस अवधि में हमारे देश में डेवेलपमेंट और तरक्की हुई। इस का अर्थ यह है कि इन दस बरसों में हमारा एक्सपोर्ट १०६ करोड़ रुपये का कम हुआ और इम्पोर्ट ४० करोड़ रुपये का ज्यादा हो गया। अगर यही स्थिति रही, तो हमारी इकानोमी ठीक ढंग से नहीं चल सकती।

इस सम्बन्ध में मैं एक उपाय बताना चाहता हूं कि बाहर का व्यापार कैसे बढ़ सकता है। जहां तक साउथ ईस्ट एशिया का सम्बन्ध है, मलाया में हिन्दुस्तानियों की तादाद १० परसेंट, सिंगापुर में ८ परसेंट, और बर्मा में ११ परसेंट है। इसी प्रकार मारीशस में हिन्दुस्तानियों की तादाद ७५ परसेंट और फ़िजी में भी ७५ परसेंट है। इसी प्रकार ईस्ट अफ़्रीका और केनिया में भी हिन्दुस्तानियों की आबादी है। मैं इन स्थानों पर गया हूं। वहां पर हिन्दुस्तानियों की सब से बड़ी कम्पलेंट यह है कि वहां पर हिन्दुस्तान की एम्बैसीज़ व्यापार के सम्बन्ध में उन के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं करतीं। अगर सरकार चाहे, तो वह सारे साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट अफ़्रीका में और अफ़गानिस्तान और ईरान में अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। इस देश के आदमी हर स्थान पर मौजूद हैं। वे भारतीय वंश के लोग हैं और हमारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इस तरफ़ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। थाईलैंड का जितना कपड़े का व्यापार है, वह प्रायः सभी हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। इसी प्रकार से मलाया का सारा व्यापार करीब करीब हिन्दुस्तानियों और चीनियों के हाथ में है। लेकिन हम अपने सामान को बेचने के लिये इन से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ठोस कदम उठायें। आप यह भी जानते हैं कि तीन कामन मार्किट्स का सिस्टम इस वक्त है। एक यूरोपियन कामन मार्किट है, एक अफ़्रीकन कामन मार्किट है और साउथ ईस्ट एशिया की कामन मार्किट भी तीन देशों की आ गई है। इन तीनों कामन मार्ट्सि के पीछे सिद्धान्त क्या है? इसके पीछे केवल आर्थिक सिद्धान्त ही काम नहीं कर रहा है, राजनीतिक सिद्धान्त भी काम कर रहा है और वह राजनीतिक सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार पावर ब्लाक बने हुए हैं उसी तरह से छोटे छोटे अधिक पावर ब्लाक बनाये जायें। आर्थिक क्षेत्र के लिये हमें भी कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि हिन्दुस्तान के जो

[श्री रघुनाथ सिंह]

समीपवर्ती देश हैं, जहां हिन्दुस्तानियों की आबादी है, उनके साथ सम्पर्क बढ़ा करके हम अपने व्यापार में वृद्धि करें।

†**श्री व० बा० गांधी:** (बम्बई नगर--मध्य दक्षिण) : इस आय-व्ययक में कई अच्छी बातें हैं। मैं केवल दो के विषय में कहता हूं--एक तो इस आय-व्ययक में निर्यात को सहायता और दूसरी आयोजित अर्थ व्यवस्था में चालू उपभोग का काम।

इस बजट में निर्यात के प्रोत्साहन और विकास के लिये १ करोड़ रुपये की रकम रखी गई है।

दूसरी बात एक महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्ध रखती है, वह है चालू उपभोग और नियोजन मे सम्बन्ध। इस को बड़ी अच्छी तरह से कहा गया है।

हमारे देश में स्फीती और अधिक झुकाव है। हमें स्फीति में और वृद्धि नहीं करनी चाहिये इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान वित्त मंत्री के २३ अप्रैल, १९६२ के भाषण के पैरा १५ की ओर दिलाना चाहता हूं।

वित्त मंत्री ने जिस मूल्यों के विषय नीति का उल्लेख किया है उस के बारे में रेलवे बजट से उदाहरण ले कर कहना चाहता हूं।

रेलवे बजट के ध्येय २१ २६ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना था। इसके लिये रेलवे के भाड़े की दर और यात्रियों के किराये बढ़ाने के लिये प्रस्ताव था।

रेलवे ऐसा उद्योग है जिसमें स्फ़ीती की गुप्त शक्ति काफी है क्योंकि रेलवे सेवा ऐसी वस्तु है जो कि बहुत सी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन की लागत का एक भाग होता है। यही बात विद्युत्-संयंत्रों, सिंचाई के काम और दूसरी ऐसी सेवाओं पर लागू होती है जो कि दूसरी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के खर्च में गिनी जाती हैं। इस पैरा में एसे उद्योगों जिन की स्फीती की गुप्त शक्ति दूसरे उद्योगों से अधिकतर होती हैं।

हमें कर सम्बन्धी नीति में बहुत सावधान होना चाहिये। हमें अधिक राजस्व के लिये कुछ उद्योगों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिये और और कुछ उद्योगों को छूना चाहिये।

जब रेलवे बजट इस सदन के सामने था तो मैं हैरान था कि क्या रेलवे के भाड़े और दर बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों से भी सलाह ली गई थी।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे बजट वित्त मंत्री की सलाह से बनाया जाता है। इस में आपस में मेलजोल के न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री व० बा० गांधी:** हमें एसे अर्थशास्त्र जानने वाले व्यक्तियों की एक संस्था बनानी चाहिय जोकि सब मंत्रालयों से आज़ाद हों जोकि मंत्रणा देने का काम करें और प्रधान मंत्री के साथ लगाई जाए।

श्री बागड़ी: (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहब, भारत की जनता आज इस मुअज़िज़ एवान की तरफ निगाह लगाए बैठी है कि कैसा बजट यह सदन उनके लिये पास करता है।

†मूल अंग्रेजी में

नए चुनावों के बाद आज जब कि भारत के करोड़ों इन्सानों ने अपना विश्वास दे कर इस सदन के मुअजिज़ मेम्बरान को यहां भेजा है, तो ये देखना चाहते हैं कि वे मेम्बर इस देश को क्या नई देन देते हैं। लेकिन जब यह नई देन जनता के सामने जाएगी और जनता इस नई देन को देखेगी और परखेगी और जब जनता इसको इस्तैमाल करेगी तो जनता यह महसूस करेगी कि जनता के साथ घोर विश्वासघात किया गया है। करोड़ों इन्सानों के मुंह में से चाहे वह चाय का दाना हो या तम्बाकू का टुकड़ा हो या दियासलाई की माचिस की सींक हो, उसको किस बेदर्दी के साथ गरीब कमेरों से टैक्सों द्वारा छीना गया है, और उसका उपयोग क्या किया जाता है? उसके द्वारा खर्चा बढ़ाया जाता है। टैक्स इसी नाते बढ़े हैं कि मिनिस्ट्रियां बढ़ गई हैं। एक जनसंघी सज्जन ने तो यहां तक कहा कि वायदे निभाओ। कौन से वायदे निभाने के लिये कहा है? राजे महाराजों के साथ जो वायदे किए हैं उनको निभाने की बात कही जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि उस वायदे को निभाने की जरूरत है जो कि इस देश के करोड़ों लोगों के सामने किया गया और जिस वायदे को इस देश के त्यागी पुरुषों ने किया, जिसको वादशाह जफर ने और आखिरी शहीद गांधी ने किया। वह वायदा यह था कि इस देश के बेकस इन्सानों की कमाई जिसको लूटने का एक मात्र साधन अंग्रेज़ था उसके जाने के बाद उस कमाई को नहीं लूटा जाएगा।

मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो इस देश का साहुकार इस देश की जनता को लूटता है और दूसरी तरफ इस सरकार का नेहरू सेठ लूटता है। पेनिसिलिन का टीका, जो तपेदिक का टीका है और जिसकी लागत तीन आने होती है उसका १२ आने इस देश की गरीब बीमार जनता के फेफड़ से किस बदर्दी के साथ लिया जाता है और उसका रस और खून चूस कर एयाशी के साधन किए जाते हैं। तो किस तरीके से इस देश के गरीब लोगों की आशा और विश्वास बंधेगा।

गांधी जी ने अपनी एक गुजराती पुस्तक में लिखा है, और मैं समझता हूं कि कहीं वह भविष्य सच न हो जाए। उन्होंने उस पुस्तक में जिसका नाम--बिहार में कौमी आग--है पृष्ठ ३६० पर लिखा है :

> "स्वतन्त्रता जैसा अमूल्य रत्न हमारे हाथों में आ रहा है और हम उसे खो रहे हैं। स्वराज्य का यत्न करने के लिये हमें फिर एक एक को मरना पड़ेगा। स्वराज्य लेने का पाठ तो लिया पर संभालने का पाठ नहीं सीखा। हमारी राजसत्ता ब्रिटिश की तरह बन्दूक के जोर से नहीं टिक सकेगी। अनेक त्याग और तपों के बाद कांग्रेस ने प्रजा का विश्वास प्राप्त किया हैं। परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले प्रजा की सेवा करने के बदले मालिक बन जायेंगे तथा स्वामित्व दिखाएंगे तो मैं कदाचित जीवित रहूं या नहीं पर इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह आगाह करने की हिम्मत करता हूं कि देश में बगावत होगी और सफेद टोपी वालों को जनता चुन चुन कर मारेगी?"

मैं मानता हूं कि प्लान के लिए रूपए की जरूरत है। लेकिन आज करोंड़ो रुपया इनकम टैक्स का बड़े बड़े साहूकारों की तरफ बकाया पड़ा है और सरकारी मैशिनरी उसको वसूल नहीं कर पा रही है। अगर किसान की तरफ दो रुपया भी कर और लगान का हो तो उसको जेल में डाल दिया जाता है लेकिन मिल मालिकों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों से, जिनका रुपया कांग्रेसी सज्जनों के चुनावों में चैकों द्वारा जाता है, टैक्स का बकाया वसूल नहीं किया जाता। करोड़ों रुपया पेंडिंग में पड़ा है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आपने चुनाव में खर्च नही किया।

श्री बागड़ी : मैंने जनता का पैसा खर्च किया लेकिन राजा महाराजाओं का नहीं किया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर इस बजट में कोई टैक्स घटाया गया है तो वह कारपोरेशन टैक्स घटाया गया है, जिन विदेशी कम्पनियों पर टैक्स बढ़ना चाहिए था उसको कहीं कहीं घटाया गया है। जो खर्चा टैक्स बडे लोगों पर लगता था उसको घटा दिया गया है। लेकिन माचिस, तम्बाकू और चाय पर बढ़ा दिया गया है जिसको हिन्दुस्तान का हर गरीब और खाना बदोश तक इस्तैमाल करता है।

आप देखें कि कितने टैक्स की चोरी होती है। जितनी प्राइवट लिमिटेड कम्पनियां है वे तमाम इनकम टैक्स की चोरी करती हैं। उनका तरीका यही है कि खर्च ज्यादा दिखा देती हैं और इस तरह इनकम टैक्स से बच जाती हैं। मैं मिसाल के तौर पर वताना चाहता हूं कि भिवानी के अन्दर भिवानी-लुहारु ट्रांस्पोर्ट कम्पनी लिमिटिड लुहारु है, और दिल्ली में जो कृष्णा बस सर्विस कम्पनी लिमिटिड दिल्ली व गंजीबार बस सर्विस हांसी की बसें चलती हैं, अगर इनके हिसाब को देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने लाखों रुपए का खर्चा दिखा रखा है। इनके हिसाब की जांच से सरकार को काफी आमदनी हो सकती है।

हमारे देश में वहुत से लोगों को करोड़ों रुपया इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। यह पेंशन इनाम बहुत से राजा महाराजाओं को मिलती है। यह इनको किस सेवा और खिदमत के सिले में मिलती है। ये राजे माहाराजे वे लोग हैं जो कौमी तहरीक के जमाने में महात्मा गांधी जैसे इन्सान को कहा करते थे :

या रहेगा किराड़, या रहेगा बराड़

ऐसे लोगों को वाइदा निभाने के नाम पर कितनी बेशर्मी के साथ वजीफे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उनको पेंशन मिलती है। मैं अर्ज करूं कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरु ने अपनी आटो--बायोग्राफी में लिखा है कि एक दफा उनको पंजाब को एक रियासती जेल में घोड़ों की पेशाब वाली जगह में बन्द कर दिया गया था। उन्होंने लिखा है कि--मैं एक दफा वहां से आ गया तो दोबारा वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन मेरा फ़र्ज था उस जेल में जाने का क्या इन्हीं सेवाओं के बदले में इन लोगों को ये पेंशनें दी जा रही हैं। क्या इस देश के मासूम गरीब लोगों को पीसनें वाले और दरिन्देनुमां अंग्रेजों की मदद करने वाले इन्सानों को पेंशन दी जानी चाहिए ? मैं समझता हूं कि यह पेंशन नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के अवाम के साथ बेवफाई का पक्का सबूत दिया जा रहा है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही, और टैक्सों का भार इसी तरह से बढ़ता रहा, और लॉ एंड आर्डर इसी तरीके से मफलूज होता रहा तो वह दिन दूर नहीं मुझे यह कहते भय लगता है --कि देश में अनार्की हो जाए और महात्मा गांधी जैसे महान आदमी को वह बात सच हो जाए कि धोली टोपी वालों को लोग चुन चुन कर मारें। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यह देश के लिए बुरा होगा और इसको रोकना चाहिए। लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है।

आज इस देश के अन्दर बड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप पंजाव की तरफ जाइए कितने सिनेमा और कोल्ड स्टोरेज हैं जिन में इनकम टैक्स की चोरी होती है। कोई पूछने वाला नहीं है। सैंयां भए कोतवाल। पंजाब के मुख्य मंत्री के लड़के उन बातों को करते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर आम जनता में भ्रष्टाचार चलेगा ही।

दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम सिद्धान्तों पर चलते हैं। आप गरीबों से पैसा लेते हैं और डिफेंस पर यह कह कर खर्च करते हैं कि हम देश की सीमाओं को कायम रखना चाहते हैं, अपने देश की आजादी को मैं कायम रखना चाहते हैं। मैं आपके मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि अभी दो रोज हुए कि हमने अखबारों में पढ़ा कि दो सौ नागा होस्टाइलस हिन्दुस्तान की सरहदों को पार करके पाकिस्तान में फिजो से मिलने के लिए चले गए और हमारी फौज मुंह ताकती रह गयी। इन अफसरों के लिए और मिनिस्टरों के लिए अपने देश के गरीब मासूम इन्सानों के मुंह में से एक एक दाना और दूध का एक एक कतरा टैक्सों द्वारा छीनते हैं। इन्ही अफसरों के सामने से अलानिया तौर पर वे लोग जो हमारे देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं वरमला हमारे देश की स्वतंत्रता को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान में फिजो से मिलने और पाकिस्तान से मिल कर और साठ गांठ करके हमारे देश की आजादी को तबाह करन के लिए चले गए और हमारी मैशिनरी उन को नहीं रोक सकी। अगर आप सिद्धान्त की बात कहते हैं तो इसी सवाल पर डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी सेना नाकाम रही और उन आदमियों को रोक नहीं सकी।

इसके बाद एक बात मैं और अर्ज करूंगा। सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त फिरका परस्ती का है। सब से ज्यादा खतरा इस देश की कौमियत के टूटने का है। आज देश के अन्दर हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई का सवाल नहीं है। आज देश की एकता का सवाल है। यह एकता कैसे कायम हो सकती है। एकता तब कायम हो सकती है जब इस देश के लिए जीवन बलिदान देने वाले महान पुरुषों की जिन्दगी का उल्लेख इस देश के अन्दर फैलेगा। इस देश के अन्दर आज उन महापुरूषों को भुलाया जारहा है। वहादुर शाह जफर जैसे कौम परस्त का जो हिन्दुस्तान की जंग आजादी के लिए लड़े और जिनके चार शाहजादों को वलिदान किया गया, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। क्या चांदनी चौक में उनका बुत नहीं बनाया जा सकता था। क्या नवाब साहब झज्जर का बुत नहीं लगाया जा सकता था, या राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का बुत नहीं लगाया जा सकता था। क्या बिड़ला भवन को जहां महात्मा गांधी शहीद हुए आज कौमी मिल्कियत करार नहीं दिया जा सकता। जब तक कौम के तरीके से नहीं सोचा जाता तब तक कौमियत नहीं आ सकती।

मैं आप लोगों के मार्फत अर्ज करूंगा कि अगर इस देश को बचाना है तो यह गरीब लोगों पर जो टैक्स लगाये गये हैं उन टैक्सों को हटाया जाय, भ्रष्टाचार रोका जाये और चीजों के भावों को बढ़ने से रोका जाय। यह टैक्सेज बड़े लोगों पर लगाया जाये। ऐक्सपेंडीचर टैक्स बड़े और धनी लोगों पर लगाया जाय। इस के अलावा राजा, महाराजाओं को जो पैंशन या प्रिवीपर्स वगैरह मिलती है उसको बंद किया जाये और वह जब्त कर ली जाये। जितना भी पैसा इनकमटैक्स का बकाया रहता है वह सारा का सारा वसूल कर लिया जाय। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज की जांच पड़ताल के लिये एक कमेटी बनाई जाये। उस से आपको यह मालूम होगा कि कितना इस देश का पैसा, कौमी खजाने का पैसा लूट लूट कर खा गये हैं लेकिन बात कौमियत की करते हैं।

इस देश के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि प्लानिंग को आगे ले जावो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस देश के जिम्मेदार लोग सरमाया विदेशों के बैंकों के खजाने में दाखिल करते हैं और बात कौमियत की करते हैं।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

अगर उन में देशभक्ति का जज्बा है तो वह उसे यहां पर क्यों न लायें । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर ऐसी बात है तो उस की पड़ताल की जानी चाहिए । **अगर इस तरह से सारे लोगों का हिसाब किताब देखा जाय और पड़ताल की जाय तो हमें विदेशों से बहुत सरमाया मिलेगा ।

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आक्षेप बहुत आपत्तिजनक है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिएं । इन आरोपों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाएगा। कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें ।

श्री बागड़ी : उस सरमाये को अपने कब्जे में लेकर कौमी प्लान कामयाब किया जा सकता है । अगर उन में कौमियत का जज्बा है तो बाहर के मुल्कों में जो पैसा है उस को हमें इस प्लानिंग में क्यों न दिया जाय । दूसरों से तो जो एक एक पैसा टैक्सों द्वारा छीनने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है . . . लेकिन इन धनी लोगों का विदेशी सरमाया पड़ताल करके जब्त नहीं किया जाता ।

†उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री बागड़ी: चलिए मैं यह नहीं कहता । उनका हिसाब मत लो क्योंकि यह मिनिस्टर हैं ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्लानिंग के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार चलता है । गरीब लोग जब सरकारी कर्मचारियों के पास रजिस्ट्री करवाने या छोटी मोटी अदालतों में किसी काम के लिए जाते हैं तो उन से यह कह कर चंदा लिया जाता है कि प्लान जो पूरा करना है । उन से जब्री तौर पर पैसा लिया जाता है और कहते हैं कि यह प्लानिंग के वास्ते चंदा है और पैसा मिल जाने पर ही कहीं जाकर उनका काम किया जाता है। अब यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है ? . .

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री बागड़ी: बस मैं एक मिनट में खत्म किये देता हूं ।

इस तरीके से गरीब लोगों से जब्री पैसा वसूल कर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मैं साफ तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि सारे देश की सरकारी मशीनरी मफलूज हो रही है । एक तरफ तो यह हालत है और दूसरे तरफ बाहर के सेठों द्वारा देश को लूटा जा रहा है । वह लूट केवल बाहर के सेठों द्वारा न होकर इस देश के सेठों द्वारा भी की जा रही है । फर्क बाहर के सेठों और नेहरू सेठ में केवल इतना है कि लूटते तो दोनों हैं पर बाहर के सेठ जनता को लूटते तो हैं लेकिन लूट कर जमा भी करते हैं परन्तु यह हमारा नेहरू सेठ जनता को लूट कर खर्च करता है, जमा नहीं करता है और सरकार के अंदर बैलेंस निल का निल दिखाते हैं। मैं इन चन्द शब्दों के साथ आप की मार्फत सदन से चाहूंगा कि ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए मेरे दोस्त वह

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

†मूल अंग्रेजी में

दिन याद करें जबकि वह झोंपड़ियों में जा जा कर गरीब लोगों से वोटों की भीख मांगते फिरते थे। मैं अपने कांग्रेसी सज्जनों से खास तौर पर कहूंगा कि इस बजट पर अपने विचार प्रकट करते समय वह अपनी छाती पर हाथ रख कर और गांधी जी को याद कर के, अपने विचार प्रकट करें। उन को यह याद रखना है कि करोड़ों गरीब लोगों और खाना-बदोश लोगों ने अपना वोट देकर उनको जिताया है। उन लाखों और करोड़ों गरीब इंसानों का दिल में ध्यान रखते हुए इस बजट में गरीब लोगों पर जो टैक्स लगाया गया है उसे खारिज करें और ऐसा करें कि राजा, महाराजाओं की पेंशन वजीफ आदि को खत्म कर दें। साथ ही यदि आप मिनिस्ट्रों की पलटन को भी हटा दें या काफी कम कर दें तो भी फायदा होगा।

†श्री हिम्मत सिंह (गोड्डा) : वित्त मंत्री महोदय ने जो आय व्ययक की प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं उसका परीक्षण किया जाना है। इसका परीक्षण करते हुए हमें उन भाषणों का ध्यान रखना है जोकि २३ अप्रैल, और १४ अप्रैल, को सदन में दिये गये हैं। "१९६१–६२ के आर्थिक सर्वेक्षण" में जो कुछ कहा गया है उसको भी सामने रखा जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हमारी अर्थ व्यवस्था के कुछ निश्चित क्षेत्रों में—जैसे यातायात, कोयला, विद्युत् शक्ति तथा इस्पात की कुछ किस्मों में बहुत असंतुलन मौजूद है। इस असन्तुलन को पूरा किया जाना चाहिये। इन सारी चीजों का सामुदिक प्रगति की दृष्टि से परस्पर काफी महत्व है। हमें इस के लिये निराश नहीं होना चाहिए प्रत्युत तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। कई प्रकार के कर लगा कर वित्त मंत्री महोदय ने धन एकत्रित करने का प्रयत्न किया है। नये करों का ढांचा बहुत ही विस्तृत आधार पर खड़ा है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि अप्रत्यक्ष करों का अधिक शहरी लोगों पर पड़ेगा। इस परिस्थिति में जो इस आय व्ययक को पूंजीवादी कह रहे हैं वे गलत हैं। श्री मोरारका का कहना ठीक है कि जो भी नये कर लगाये गये हैं उसका बहुत ही कम प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर पड़ने वाला है। शहरी लोग आगे ही देहातियों के मुकाबले में अधिक कर दे रहे हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने निगमों के कर को बढ़ा कर ४५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत कर दिया है। व्यक्तिगत कर बढ़ा दिये गये हैं, और भी कई तरह के कर लगाये जा रहे हैं कि फिर भी कहा जा रहा है कि यह पूंजीवादी बजट है। वित्त मंत्री का यह सुझाव कि नये ऋणों के लिए अधिकतर साम्य पूंजी की ओर देखा जाय न कि बैंकों की ओर। यह सुझाव काफी अच्छा है और स्वागत योग्य है। इस के बावजूद होना यह चाहिए कि अपेक्षित ऋणों को धन कर से मुक्त रखा जाय। और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आवश्यक उपबन्ध कर लिया जाय।

बहुत माननीय सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों का उल्लेख किया है। कहा गया है कि उन से कुछ लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। इस बारे में मेरा तो एक ही निवेदन है कि हमें इस दिशा में कुछ प्रयत्नशील होना चाहिए और सरकारी उपक्रमों की हालत सुधारनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये अधिक अच्छी क्षमता और अधिक नफ़े की व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। लगभग ७०० करोड़ रुपया राष्ट्र का इन सरकारी उपक्रमों में लगा हुआ है। चार पांच प्रतिशत का भी लाभ होने लगे तो ३० से ३५ करोड़ तक प्राप्त हो जायेगा और कमी काफी पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हिम्मत सिंह]

माननीय वित्त मंत्री जी निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसदृष्टि से उन्होंने चाय के निर्यात के लिए कुछ रियायतें दी हैं। परन्तु चाय कीमतों का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, अतः सरकार को इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा कि निर्यात की दृष्टि से जो करों में रियायत दी गयी है और उस से जिस लाभ की आशा की जा रही है वह अन्य चीजों की कीमतों के ऊंचे स्तर से समाप्त तो नहीं हो जायेगा। प्लाई वुड और चाय के बक्सों का भाव भी काफी बढ़ गया है और रेल का किराया भाड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार के लिए यह बात भी विचाराधीन है कि क्या जूतों में जो रबड़ लगाया है उस पर भी "मर्सराइजड" अधिकतर बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर लगाया जाना चाहिए अथवा नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है वह प्रश्न हिन्दू मुस्लिम का नहीं है। वह प्रश्न आसाम और पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश है। इसकी ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावशाली पग उठाये जाने चाहिएं। प्रशासन में व्यय कम करने की बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों की संख्या कम करने के विचार से उनकी परीक्षणात्मक जांच की जानी चाहिए।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** (नीलगिरी) : मैं वित्त मंत्री महोदय के आय व्ययक का स्वागत करती हूं, यह ठीक है कि हम चाय के निर्यात के लिए करों में सुविधायें दे रहे हैं। परन्तु हमारा ध्यान चाय के छोटे-छोटे उत्पादकों की ओर भी जाना चाहिये। उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है। एक एकड़ से ५० एकड़ वाले उत्पादक बहुत मुसीबत में हैं। विशेषकर नीलगिरी में चाय का उद्योग भारी संकट में गुजर रहा है। यहां ६००० से अधिक छोटे उत्पादक हैं। सामान्य चाय की कीमत कम हो रही है यहां तक कि वह उत्पादन कर से भी कम हो गयी ह। छोटे उत्पादक अपने इस प्रयास को जारी रखने में भारी कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में हमें शीघ्र ही कोई प्रभावशाली पग उठाना होगा अन्यथा इसका बुरा प्रभाव हजारों परिवारों पर पड़ेगा। चाय पर जो शुल्क लगाया जाय उसे चाय की बिक्री के मूल्य को देख कर निर्धारित किया जाना चाहिए। उत्पादन की मात्रा को देख कर शुल्क निर्धारित नहीं होना चाहिए।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दस नये पैसे की वृद्धि क्रय के मूल्य आधार पर लगनी चाहिये न कि भार के जो चाय चार रुपया प्रति किलो बिकती है, उसे अन्तर्देशीय निर्यात शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिये। चाय बोर्ड उत्पादकों के लिये गोदामों की व्यवस्था करें तथा उन्हें "स्टाक" की प्रतिभूति के आधार पर उनकी चाय के मूल्य के एक भाग की अग्रिम धन के रूप में अदायगी करे। बोर्ड इन गोदामों से मध्य पूर्व में चाय के निर्यात के प्रबन्ध करे।

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि आज छः बजे संसद् के दोनों सदनों की ओर से राष्ट्रपति जी को विदाई-अभिनन्दन पत्र दिया जा रहा है। मुझे विश्वास

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि माननीय सदस्य उस समय तक यहां रहेंगे। अतः हम अपनी कार्यवाही ५.३० बजे तक रखेंगे ताकि माननीय सदस्य सीधे उसके बाद अभिनन्दन समारोह में भाग ले सके।

सामान्य आय-व्ययक-सामान्य चर्चा--जारी

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर): कल से जो चर्चा हो रही है उसमें कई महत्व-पूर्ण बातें कही गयी हैं। एक बात पर बार बार जोर दिया गया है कि जिस समाजवाद की बातें हम करते हैं उसके सम्बन्ध में हम स्पष्ट नहीं हैं। हम यह भी नहीं जानते कि जिस समाजवाद का हम शोर मचा रहे हैं वह हमें कहां ले जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज संसार के बड़े-बड़े समाजवादी आन्दोलनों में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। एक निश्चित प्रकार की विचारधारा से अथवा दृष्टिकोण से मामला स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर अपने समाजवाद का निर्माण करना होगा। अगले रोज प्रधान मंत्री नये समाज के निर्माण की बात कर रहे थे। मेरा मत यह है कि अपने अतीत को सामने रखते हुए कांग्रेस एक विशेष प्रकार की नीति पर चल रही है। श्री जवाहर-लाल नेहरू हमारे नये समाज के निर्माता हैं और उस समाज का आधार समाजवादी समाज की विचारधारा है। यही हमारी नीति है और इसे ही कार्यन्वित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मतभेद होते हुए भी श्री नेहरू उनमें एक अच्छा सन्तुलन कायम रखने में सफल हुए हैं। हम एक समाजवादी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा यह प्रयत्न किया है कि इस विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार किया जाय। यह विचार बिलकुल गलत है कि इस सम्बन्ध में उसमें कोई मतभेद है।

वित्त मंत्री महोदय ने यह दावा ठीक ही किया है कि देश भर में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में बहुत काफी सुधार हुआ है। रोजगार के सम्बन्ध में भी स्थिति काफी सुधरी है। परन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे कुछ बेचैनी भी पैदा होती है और वह हमारी खाद्य की स्थिति है। आज जिस प्रकार से खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी गति चल रही है उससे यह आशंका पैदा होती है कि आने वाले समय में हम अपनी खुराक की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि हमें अपने खाद्य उत्पादन का तीन गुना अधिक बढ़ाना होगा। हमें २८० लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। हमें सोचना है कि इस गम्भीर समस्या को कैसे हल किया जाये।

इस समस्या के दो अंग हैं। एक यह कि अधिक से अधिक सिंचाई की जाय ताकि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई के योग्य बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को पूर्ण रीति से उपयोग करने के साधन भी अपनाये जा रहे हैं। कृषि तथा सिंचाई के आधुनिक औजारों का भी सम्भरण किया जा रहा है। यह खेद की बात है कि जहां तक अनाज के उत्पादन का सम्बन्ध है, समाज का निम्न वर्ग समस्या की गम्भीरता को अनुभव नहीं कर रहा है। हमें विभिन्न योजनाओं से उत्पन्न पूरे सामर्थ्य को प्रयोग में लाना होगा। हमें अपने खुश्क खेती के तरीकों में भी सुधार करना होगा। इस विषय में कण्टूर बांध को उच्चतम अग्रिमता दी जानी चाहिये।

भारत भर में मोटे तौर पर २८०० लाख एकड़ भूमि है। जिस पर सिंचाई हो सकती है। परन्तु केवल २५ प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है अतः आधुनिक साधनों से उन्हें खेती योग्य बनाया जाना चाहिये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ओर सदन का ध्यान में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० गि० दुबे]

आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है कि मैसूर राज्य में ९०००० एकड़ भूमि पर वन हैं। इतनी वन सम्पदा भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक विकास बोर्ड बनाया जाये ताकि मैसूर राज्य की इस वन सम्पत्ति का पूरा-पूरा प्रयोग करके राष्ट्र के हित में इसका लाभ उठाया जाये।

अब मैं सरकारी उपक्रमों की ओर आता हूं। कुछ सदस्यों की ओर से यह कहा गया है कि करों का भार बढ़ रहा है। गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं और अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर बनते जा रहे हैं। यह बात ठीक है परन्तु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हमने सरकारी उपक्रमों का रास्ता छोड़ दिया तो समाजवादी समाज का निर्माण खटाई में पड़ जायेगा। कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जायेंगी अतः इस दिशा में बड़ी समझदारी से काम करना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में इस तरह सुधार किया जाये कि वह राजकीय पूंजीवाद में न परिवर्तित हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं आय व्यय का समर्थन करता हूं।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा): मैं वित्त मंत्री को उनके आय व्यय के लिये मुबारकबाद देता हूं। यद्यपि समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों ही पक्षों की ओर से आय व्ययक का विरोध किया जा रहा है परन्तु इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत ने निश्चित रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। देश निरन्तर धीरे-धीरे एक समाजवादी समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। शिक्षा में भी काफी प्रगति हो रही है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये कि जब तक किसी देश में कर नहीं लगाये जाते उस देश का विकास नहीं हो सकता। अतः कर लगाने पर तो मैं कोई आपत्ति नहीं कर सकता परन्तु एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को जनता पर यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि करों के रूप में जो धन सरकार जनता से वसूल करती है उसका उचित प्रयोग किया जाता है।

इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के कम विकसित अंगों की दशा को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाय। तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियां जो अभी बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं को उठाना जाय। उन्हें सेवाओं में समुचित भाग दिया जाय। जब तक पिछड़े वर्ग समाज के अन्य अंगों के तुल्य नहीं हो जाते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का होना सम्भव नहीं है। इन समुदायों में से प्रत्येक राज्य में एक या दो मंत्री लिए जायं। इससे उनमें कुछ विश्वास की भावना आ जायेगी। इस सम्बन्ध में एक और बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये वह यह कि विकास के मामले में किसी प्रकार की प्रादेशिक असमानता समानता नहीं आनी चाहिये। मेरा राज्य आसाम साधनों से परिपूर्ण है परन्तु आसाम का कोई उच्चस्तरीय नेता नहीं है। अतः उसकी हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। मैं प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आसाम की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध रूप से प्रवेश हो रहा है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। समय पर सचेत हो कर हमें इस अवैध प्रवेश को रोकना चाहिये। मुझे भय है कि यदि समय पर कार्यवाही न की गई तो परिस्थिति बहुत खराब हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि उन्हें इस अवैध प्रवेश के आंकड़े भी प्राप्त करने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बूटा सिंह (मोगा) : १६ दिन हुए वित्त मंत्री महोदय ने जो आय व्यय सदन में प्रस्तुत किया था उस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार देश का आय व्यय ही होता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसका बड़े वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस आय व्ययक को प्रस्तुत करके वित्त मंत्री महोदय ने यह प्रकट किया है कि उन्हें इस बात की विशेष चिन्ता नहीं कि इस आय व्ययक के परिणामस्वरूप क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि किसी अनाड़ी दर्जी ने कमीज़ सी हो जो पहिनने वाले को फिट ही नहीं बैठ रही। केवल आंकड़ों की जादूगरी अवश्य दिखाई गई है। मेरा तो यह स्पष्ट मत है कि कराधान की प्रस्तापनाओं को सोच समझ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे काफी कठिनाइयां पैदा हो जाने की सम्भावना है। आपने फरमाया कि आप १५० करोड़ के घाटे का आय व्ययक प्रस्तुत कर रहे हैं और ७१.७ करोड़ वह नये करों से प्राप्त कर लगे।

मैं नहीं कह सकता कि यह सब जानबूझ कर हो रहा है अथवा वैसे ही हो रहा है। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से हमारी आर्थिक स्थिरता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन में भी भारी गतिरोध आ चुका है। देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि इस मार्ग पर चल कर हमारे पदासीन मित्र अपना समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। नये लगाये गये करों से लोग नये नये उद्योगों में पूंजी लगाने से निश्चित रूप में संकोच करेंगे।

४४.५ करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर जनता के गिरे हुए स्तर पर और भी आघात हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि यह बजट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जिसकी जनसाधारण के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

खेद की बात है कि सिखों की मांग को ठीक नहीं समझा गया है। सारे देश में तथा विश्व में भी उनके प्रति गलत प्रचार किया गया है। प्रधान मंत्री से विशेषतः और सभा से मैं यह अपील करता हूं कि सिखों की सही मांग को ठीक से समझा जाये और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

चुनाव के दौरान में जो लोग कांग्रेस के विरुद्ध थे अब उनके साथ सरकार बुरा बर्ताव कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ऐसा बर्ताव कर रही है जो उसके लिये अशोभनीय है।

†श्री गौरी शंकर (फतेहपुर) : यह बजट समाजवादी नहीं है। और न यह समाजवादी समाज की स्थापना करने में सहायक ही होगा। यह बजट निर्धनों को और भी निर्धन बना रहा है।

परियोजनाओं तथा योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सभी विकास परियोजनाओं सम्बन्धी काम गर-सरकारी ठेकेदारों को दिये जाते हैं। ये ठेकेदार 'प्राविधक पदाधिकारियों को रिश्वत देते हैं यही कारण है कि निर्माण कार्य घटिया किस्म का हो रहा है। और इस प्रकार लोग अंत में ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कार्य सहकारी संस्थाओं को दिया जाये। ऐसा करने से भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायेगा। निर्माण कार्य भी ठीक होगा। साथ ही सरकारी प्रविधिक पदाधिकारियों को रिश्वत आदि का लोभ भी न रहेगा और वे अच्छा काम होने पर ही सर्टीफिकेट देंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री गौरी शंकर]

उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ कमाया जा रहा है। इस बजट से भी उन्हीं को अधिक लाभ होगा। 'आयात अनुज्ञप्तियों' देने की प्रथा में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि ये अनुज्ञप्तियां यदि बोली लगा कर दी जायें तो भ्रष्टाचार जो आज इस क्षेत्र में काफ़ी व्याप्त है घट जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के कार्य-संचालन में गड़बड़ है। वहां के प्रबन्ध प्राधिकारी पूरे मन एवं लगन से कार्य नहीं कर रहे हैं। अकार्यकुशलता काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों से वांछित उत्पादन नहीं हो रहा है।

छोटे पैमाने के उद्योगों तथा हथकरघे के उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ये काम ऐसे हैं जिन्हें कि ग्रामीण लोग आसानी से कर सकते हैं।

आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है जिससे साधारण लोगों की स्थिति और भी बिगड़ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि गरीब जनता पर कर लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच होड़ लग रही है।

अगर देश में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो यह आवश्यक है कि सरकार जो कुछ कहती है वह करके भी दिखाये।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों का वेतन कहने को तो २,२५० रुपये है किन्तु उनको औसतन ६००० रुपये पड़ते हैं। यह एक बुरी बात है। यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो देश अवनति की ओर निश्चय ही जायेगा।

कुछ पूंजीपति सत्तारूढ़ दल के अपने आदमी हैं। वे सरकार को चुनाव निधि में धन देते हैं तो सरकार उनको अन्य लाभ पहुंचाती है।

करापवंचन, सरकारी धन का दुरुपयोग तथा व्यय के विनाश की बुराइयों से गड़बड़ तथा अराजकता की ओर चले जाने की संभावना है। जैसाकि व्यापारिक व्यवसायों द्वारा उसको चुनाव निधि में धन देने से प्रकट होता है; सत्तारूढ़ दल पूंजीपतियों की सहायता पर अधिक निर्भर करता है।

यह बजट प्रत्यक्षतः इस बात का निर्देश करता है कि यह पूंजीवाद की ओर ले जाने वाला है न कि कल्याणकारी समाज की स्थापना करने वाला।

†**श्री शिवचरण गुप्ता** (दिल्ली सदर): बजट प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं। विरोधी पक्ष के सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह सरकारी क्षेत्र की अधोगति बताने वाला ही है। बजट पर तीसरी योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाये। बजट में रखी गई प्रस्तावनाओं से योजना की नींव पक्की हो गई है। यह कहना गलत है कि समस्त अप्रत्यक्ष करों से निर्धनों पर प्रभाव पड़ेगा। जिन वस्तुओं पर कर लगाने की प्रस्तावना की गई है, उनका उपयोग विशेष वर्गों द्वारा किया जाता है।

अब सवाल यह उठता है कि तीसरी योजना के लिये खर्च कहां से आयेगा। इसकी पूर्ति के लिये विदेशों से धन लेना होगा तथा देश में अपनी आय बढ़ा कर भी। यही कारण है कि

†मूल अंग्रेजी में

पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी बजट में अप्रत्यक्ष कर लगा कर आय बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

विकास व्यय के ढांचे को देखते हुए जान पड़ता है कि हमारे द्वारा सभा समाजवादी समाज के उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की संभावना है। बजट में योजना के लिये अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध करने का प्रयास किया गया है।

ये अप्रत्यक्ष कर उन्हीं लोगों पर लगायें जा रहे हैं जिन में कि कर देने की क्षमता है। बजट नितान्ततः समाजवादी प्रकार का है। इसका कारण देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कायम रखने का हमारा संकल्प है। सरकार यह प्रयत्न करती रही है और करती रहेगी कि देश में एकाधिकार की प्रवृत्तियों को काबू में रखें।

जहां तक कि भूमिहीन श्रमिकों की बात है। यह ठीक है कि पहली दो योजनाओं में उनके लिये कुछ नहीं किया गया है किन्तु तीसरी योजना में उनकी हालत सुधारने की दिशा में प्रयत्न किया जायेगा।

तीसरी योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भी पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा विचार है कि कृषि उत्पादन बढ़ कर ३० प्रतिशत अधिक हो जाये। ग्रामीण तथा छोटे कुटीर उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया जायेगा।

जनता का पूरा पूरा सहयोग सरकार को मिले इसके लिये भी पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा। साथ ही मेरा एक सुझाव है कि कर संग्रह की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा अपवंचन को रोका जाये। लोगों में यह भावना भी उत्पन्न की जाये कि देश के विकास में वे भी समान भागीदार हैं।

श्री मौर्य (अलीगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दिये बिना आगे नहीं जा सकता कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और मैं कहे बिना नहीं रह सकता हूं

बड़ी खुशनसीबी जो फरियाद सुन ली
दुआ उनको दें या कि किस्मत को अपनी।

आज से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में इस देश में पहली बार लोकशाही ने जन्म लिया था। उस लोकशाही या जनतंत्र के मानी हैं कि वह "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित हो। बैंथम की भी थ्यूरी यह है "मैक्सीमम गुड फार दी मैक्सीमम नम्बर आफ पीपल" अगर इस सिद्धान्त के ऊपर लोकशाही आधारित नहीं है तो इस तरह की व्यवस्था को लोकशाही कहना लोकशाही का मखौल या मज़ाक उड़ाना है।

आज का जो बजट आदरणीय फाईनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया है इस सदन के सामने, यदि मैं उसके बारे में यह कह दूं कि वह "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है और यदि उसके आगे बढ़ कर मैं यह कह दूं कि उसके सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं जो लोकशाही की जड़ के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करते हैं, तो ये दोनों बातें अपनी जगह पर सत्य होंगी। आज के बजट को उठा कर देखा जाए तो पता चलेगा कि जो मामूली आदमी हैं, जो कठोरकर्मा व्यक्ति हैं, जो शोषित वर्ग के इंसान हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको आज तक जब से हम आज़ाद हुए हैं, और राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तब से एक लहमा भी आराम की सांस लेने को नहीं मिला है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगे हैं। इस बजट में भी यही किया गया है। कपड़े पर आपने आघात किया है, सिग्रेट, तम्बाकू और बरतन आपने नहीं छोड़े हैं ये वे चीज़ें हैं जोकि वह रोज़ाना की जिन्दगी

[श्री मौर्य]

में इस्तेमाल करते हैं। एक मजदूर जिसको आपने इस आजादी में से कोई भी भाग नहीं दिया है, उसके ऊपर आपने ४४.५ करोड़ रुपये के टैक्स और बढ़ा दिये हैं जबकि पिछले बरस भी उसके ऊपर ५७.५ करोड़ रुपया बढ़ाया जा चुका है। एक शोषित समाज का इंसान होने के नाते क्या मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं इस सदन में कि जिस रेट से आप शोषितों को रौंदते हैं, कठोरकर्मा को रौंदते हैं, क्या उन्हीं शक्तियों के साथ आप उन पूंजीपतियों को भी रौंदते हैं जिनकी बदौलत आज बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में आई है? हो सकता है कि भावावेश में आकर मैं कोई ऐसी बात कह जाऊं जो कि सदन के किसी माननीय सदस्य या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बुरी लगे। परन्तु वही इस भावावेश के दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस बहुत ही आलीशान भवन में बैठने का मुझ जैसे एक मजदूर को पहली बार मौका मिला है और दूसरी बात यह है कि मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं जो रोजाना पैसा कमाता है और शाम को आकर अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। अगर वह एक दिन मेहनत न करे तो दूसरे दिन उसके घर में चूल्हा नहीं सुलगता। जब मैं देखता हूं कि भारतवर्ष की आमदनी का तीस प्रतिशत हिस्सा चार परसेंट इंसानों तक ही सीमित रह जाता है तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह राम राज्य नहीं आया है, आज वह लोकशाही नहीं आई है जिसके ख्वाब महात्मा गांधी जी देखा करते थे। आज जब हम देखते हैं कि भारतवर्ष में खेती से सम्बन्धित जो इंसान हैं, जो कुछ भी भारतवर्ष में पैदा होता है, उसका तीस परसेंट फायदा यहां पर ढाई परसेंट इंसानों को ही मिल जाता है और बाकी लोग यहां पर बेबहरा रह जाते हैं तो इन बातों को देख कर मन में रोष सा प्रकट होता है। वह रोष कोई बनावटी नहीं, वह अपनी जगह पर सही है। मल्टिपल टैक्स यहां पर बढ़ाये जा रहे हैं ये एक ही चीज पर बार बार टैक्स लगाया जाता है। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिन पर कि दस दस बारह बारह या चौदह चौदह दफे टैक्स लगाया जाता है इस तरह का टैक्स लगाने से यहां उद्योग बढ़ नहीं सकते इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकती है। मैं इस पक्ष में हूं कि जो मल्टिपल टैक्स हैं उनको बढ़ावा न दिया जाय। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने एक्सपेन्डिचर टैक्स को बड़ी शान के साथ बड़े सिद्धान्त के आधार पर समाप्त किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक तरफ हम दूसरे मुल्कों से भिखारी बन कर भीख मांगते हैं, और दूसरी तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ७० लाख रुपये के लगभग जिसको और ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, उसको एक कलम के साथ समाप्त कर देते हैं, ऐसी हालत में किस बात को सही माना जाय? क्या आपकी बातको सही माना जाय? इस पर आर्गूमेंन्ट दिया जाता है कि बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से आदमियों को लगाना पड़ता है, तब वह पैसा वसूल होता है। यह कोई आर्गूमेंन्ट नहीं। इसको सुन कर मैं सोचता हूं कि इस मुल्क के अन्दर यह जो ७० लाख की आमदनी है वह बढ़ कर एक दिन ७ करोड़ की भी आमदनी हो सकती है। मेरा अपना तो यह अध्ययन है कि वहां पर सब साधन नहीं बरते गये, जो बरते जाने चाहियें थे अगर वे सब साधन बरते जाते तो यह आमदनी और भी ज्यादा हो सकती थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रोफेसर कैलडोर का कहना है कि एक्सपेन्डिचर टैक्स वैल्थ टैक्स और इनकम टैक्स में बहुत बड़ा लगाव है। यह जो एक्सपेन्डिचर टैक्स है जिस के लिये फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने समाप्त करने को कहा है, अगर इस को समाप्त कर दिया जाता है तो खर्चे का हिसाब न रखने पर और आमदनी का हिसाब रखने पर ठीक हिसाब नहीं रह पायेगा और काले बाजार का पैसा ज्यादा बढ़ जायेगा। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज एक बाजार में, जो कि खुला बाजार है, स्टाम्प लगा कर और ज्यादा व्याज के ऊपर पैसा मांगें तो आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन

अगर काले बाजार में पैसा मांगें और कोई लिखा पढ़ी भी न करें तो भी कम व्याज पर पैसा मिल जाता है। आखिर यह पैसा कहां से आता है ? यह पैसा उस काले बाजार का पैसा है जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है एक्स्पेन्डिचर टैक्स को समाप्त करके। मैं प्रार्थना करूंगा मेरी ऐनी विनती है कि इस टैक्स को समाप्त न किया जाय।

मैं इस बात को मानता हूं कि कारपोरेशन टैक्स में ५ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है यह ५फी सदी बढ़ोतरी जो आज ५० फीसदी तक आ गई है, उसके लिये मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ तो वे अमरीका और इंगलैंड की मिसालें देते हैं टैक्स के सम्बन्धमेंऔर दूसरी तरफ इस बात को भूल जाते हैं कि जो कारपोरेशन टैक्स इस देश में है वह संसार के सभी मुल्कों से कम है : उसको और बढ़ाया जा सकता है।

अब मैं सदन के सामने डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। जो सीधा सीधा टैक्स लगता है वह पूंजीपतियों पर जा कर पड़ता है और जो उलट फेर से टैक्स लगता है, जिस को इनडाइरेक्ट टैक्स कहते हैं, वह गरीब और कठोरकर्मी आदमियों पर पड़ता है। आप देखिये कि इस की बढ़ोतरी किस रफ्तार से और किस खूबी से फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय कर रहे हैं। सन् १९५१-५२ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कुल टैक्स ७३९ करोड़ रु० का था, सन् १९६०-६१ में वह १,२९१ करोड़ रु० का रहा। सन् १९६१-६२ में वह लगभग १३९१ करोड़ रु० का है। उस में डाइरेक्ट टैक्स सन् १९५०-५१ में १३० करोड़ रु० का था। सन् १९६०-६१ में वह २०६ करोड़ रु० का था। इस में ७६ करोड़ रु० की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ इनडाइरेक्ट टैक्स के फ़िगर्स को देखिये। सन् १९५०-५१ में वह २२७ करोड़ रु० का रहा। सन् १९६०-६१ में यह इनडाइरेक्ट टैक्स ५६२ करोड़ रु० का रहा, यानी इस में ३३५ करोड़ रु० की बढ़ोतरी हुई। क्या मैं यह पूछने का दावा कर सकता हूं कि आप किस तरह से टैक्स लगाते हैं ? आप उन लोगों को, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, रोटी और रोजी नहीं देना चाहते, लेकिन जो इन्सान अपने हाथ से काम करना नहीं सीख सके, जो एक तरह से हरामखोर हैं, हलालखोर नहीं हैं, जिन का वर्किंग क्लास से सम्बन्ध नहीं है, उन पर टैक्स लगाने मे आप के हाथ कांपते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ कांपते हैं क्योंकि आप को चुनाव के समय कानपुर के किसी बड़े पूंजीपति से पैसा मिलता है इस वजह से उन पर टैक्स लगाने में आप का हाथ रुकता है। मैं आप का ध्यान उस बगावत की ओर ले जाना चाहता हूं जो इस सदन में तो नजर नहीं आती है या बहुत मामूली तौर पर नजर आती है, लेकिन हिन्दुस्तान के कोने कोने में क्षण क्षण में कण कण से उस क्रान्ति की झनकारें बजती चली जा रही हैं और उस क्रान्ति की झनकारों में किसी भी क्षण देश में बढ़ती हुई शैतानियत को हड़प सकती हैं। यह तो मैं ने आप को इनडाइरेक्ट टैक्सों के आंकड़े दिये।

अब मैं आप का ध्यान स्टेट टैक्सेज़ की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। सन् १९५०-५१ मे २८१.०५ करोड़ का कुल टैक्स था, सन् १९६१-६२ में ६११.६५ करोड़ का टैक्स था। उस में डाइरेक्ट टैक्स सन् १९५१-५२ में १३२.४५ करोड़ का था और सन् १९६१-६२ मे वह २४२.९१ करोड़ का रहा, यानी इस में ११०.४६ करोड़ की बढ़ोतरी रही। इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ सन् १९५१-५२ मे १४८.६० करोड़ के रहे और सन् १९६१-६२ में वह ३६८.६५ करोड़ का रहा, यानी इस में बढ़ोतरी २२०.०५ करोड़ की रही ——मैं यहां पर थोड़ी देर के लिये यह चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मेरी बात सुन लें। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मैं यहां

[श्री मौर्य]

पहली बार बोल रहा हूं और फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय के न सुनने से मैं कुछ हताश होता हूं, मुझ को इस से डिसऐप्वाइंटमेट होता है। कम से कम मुझे बढ़ावा देने के लिये वे मेरी बात सुन लें। --डाइरेक्ट टैक्स ५९ फीसदी बढ़े और इनडाइरेक्ट टैक्स २५० फीसदी बढ़े। इस व्यवस्था को मैं पूंजीवादी व्यवस्था की रखवाली करना कहता हूं। सन् १९४७-४८ से ले कर सन् १९६१-६२ तक डाइरेक्ट टैक्सेशन में गिरावट हुई है और इनडाइरेक्ट टैक्सेशन में बढ़ोतरी हुई है। मैंने देखा कि पूरे देश में जहां भी एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स का सवाल आया वहां सरकार का कहना है, सरकार के जिम्मेदार कर्मचारियों का कहना है कि पूरे हिन्दुस्तान में लगभग १०० आदमी ही ऐसे हैं, जिन के पास ५० लाख या ५० लाख से ज्यादा सम्पत्ति है। लेकिन मैं यह कहने का दावा करता हूं, यह कहने की जुर्रत करता हूं, इस सदन मे, कि यह बात सत्य से परे है। बहुत से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोग दिल्ली में ही जा कर देखें और वहां के आंकड़े लें तो शायद दिल्ली में ही इतने पूंजीपति निकल आयेंगे मेरा खयाल है कि १०० आदमियों के जो आंकड़े दिये गये हैं जिन के पास कि ५० लाख या उस से ज्यादा की सम्पत्ति है, वे दिल्ली ही में पूरे हो जायेंगे, पूरे देश की तो बात ही क्या है। मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी राज्य सभा के चुनाव हुए। उस में कानपुर के एक पूंजीपति ने जरा से चुनाव में १ लाख ४५ हजार रुपये खर्च कर के सदन में आने की जुर्रत की और वे आ भी गये। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा खर्च कहां से हुआ (अन्तर्बाधा) मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब मैं आप की तरह बुड्ढा हो जाऊंगा तो आप के सवाल का जवाब भी देता जाऊंगा गौर बोलता भी जाऊंगा, अभी मुझ को बोलने दिया जाय।

इस सदन के मेरे एक आदरणीय माननीय सदस्य श्री हरवानी ने एक बात कही थी और फरमाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिल तो पूंजीवादी है लेकिन उन का दिमाग समाजवाद की तरफ है। जो कुछ उन्होंने कहा उस में मैं थोड़ा उलट फेर करना चाहता हूं। वास्तव में हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिमाग समाजवाद की ओर नहीं है, पूंजीवाद की ओर है, उन का हृदय समाजवाद की ओर है, और चूंकि उन के हृदय पर अभी तक दिमाग काबू पा रहा है इस वजह से उन पर समाजवाद का कोई असर नजर नहीं आता है। इस सदन के बहुत से आदरणीय सदस्यों ने हिन्दुस्तान के मुकाबले मे इंगलैंड और अमरीका की बात कही। उन्होंने वहां का ब्यौरा देते हुए बताया कि यहां पर टैक्स कम हैं। लेकिन उन सब आसानियों को देखा जाय या जनता को इंगलैंड और अमरीका में मिलती हैं और जो सुविधायें हिन्दुस्तान म मिलती हैं तो उन में जमीन और आसमान का फर्क दिखायी देगा। मेरा अपना विचार है कि जब यह अवस्था है तब इस प्रकार की तुलना करना सही नहीं होगा।

मैं इनकम टैक्स की ओर भी आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं आज इनकम टैक्स की व्यवस्था को देखा जाये तो मालूम होगा कि वह बहुत ही गलत तरीके से चल रही है ऐसे बहुत से पूंजपति और उद्योगपति हैं जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स पूरा नहीं दिया है और उन के खिलाफ कोई कार्रवाही होती भी है तो जैसा कि कांग्रेस के एक मैम्बर साहब ने सदन में कहा था, उनको स्वयं मिनिस्टर शरण देते हैं। दूसरे इनकम टैक्स आफिसर को सीधे सीधे इस बात का अधिकार नहीं है कि अगर वह पाये कि कोई भी पूंजीपति या कोई भी विशेष व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है तो उन की किताबों पर फौरन छापा मार कर अपने क़ब्जे मे ले सकें। ऐसी ताकत इनकम टैक्स आफीसर को नहीं दी गयी है। उस बेचारे को पहले कमिश्नर की परमीशन लेनी होती है और जब तक वह परमीशन लेता है तब तक उस खबर का लीकेज हो जाता है और पूंजीपति को पता चल जाता है और वे एकाउन्ट बुक्स जिन को पकड़ कर देश का भला हो सकता था गायब हो जाती हैं और उन की जगह दूसरी आ जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि इनकम टैक्स आफिसर को इस बात की ताकत दी जाये और

कानून में ऐसा प्राविजन किया जाये कि इनकम टैक्स आफिसर सीधे सीधे बगैर कमिश्नर की परमिशन के अगर कहीं इनकम टैक्स की चोरी हो रही है तो एकाउन्ट बुक्स को छापा मार कर अपने कब्जे में कर सके जिस से कि जो गलत काम करते हैं और देश के धन के साथ खिलवाड़ करते हैं उन के खिलाफ कदम उठाया जा सके।

बहुत से माननीय सदस्य जो यहां टीका टिप्पणी करते हैं मैं उन का ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहता हूं। टीका टिप्पणी करना आसान है। इस सदन में बैठ कर आसमान की बात करना भी आसान है, लेकिन वह अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि जब वे वोट मांगने गये थे तो उन्होंने जनता से क्या कहा था। आप की पंचवर्षीय योजनाओं का रुपया दिल्ली से खर्च होना शुरू होता है और ग्रामीण जनता के पास पहुंचते पहुंचते एक नया पैसा रह जाता है। हमारा कहना है कि पंचवर्षीय योजना का पैसा ऊपर से खर्च न हो, नीचे से खर्च हो। पहले वह गावों में खर्च हो। अगर दिल्ली में पंचवर्षीय योजना का रुपया खर्च नहीं होगा तो यहां के रंग महलों में, अशोक होटल में और एग्रर कंडीशन्ड बंगलों में कोई फर्क नहीं पड़ सकता लेकिन अगर यह पैसा जनता जनार्दन के लिये खर्च नहीं होगा तो वहां बहुत से इन्सान बेमौत मर जाते हैं।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहूंगा बहुत से लोग यहां पर यह बात कहते हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग, कि हम इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो जो बच्चा आज मिनिस्टर के यहां या किसी पुलिस कप्तान के यहां पैदा होने वाला है, और जो बच्चा बिड़ला या डालमिया के यहां पैदा होने वाला है और जो बच्चा एक मजदूर और किसान के यहां पैदा होने वाला है उन सब के खाने पीने और शिक्षा की व्यवस्था समान है क्या ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सौ वर्षों में भी आप समाजवाद नहीं ला सकते। यह समाजवाद एक मखौल और एक धोखा है इस देश की गरीब जनता के साथ। समाजवाद इस तरह से नहीं आयेगा। आज देश का यह दुर्भाग्य है कि पहाड़ पर भी मिट्टी डाली जा रही और खाई में भी मिट्टी डाली जा रही है। इस देश में पहाड़ भी हैं और खाइयां भी। अगर आप ईमानदारी से भी पहाड़ पर और खाई में मिट्टी डालें तो जब पहाड़ आसमान तक पहुंच जायेगा। उस समय तक खाई जमीन तक ही आ पायेगी। रिपबलिकन पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा तो यह कहना है कि अगर आपको समाजवाद लाना है तो पहाड़ों को काट कर खाई में डालिये ताकि देश में समानता का राज हो जाये। और हम बहुजन सुखाय के सिद्धान्त के अनुसार आगे बढ़ सकें। हम देखते हैं कि लोकशाही के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है खास तौर से जब इस सदन में राजा महाराजा बैठे हुए हैं। क्या ये लोकशाही के प्रतीक हैं। हम किस तरह की लोकशाही पर चल रहे हैं ? चाहे वे कांग्रेस के हों या विरोधी दलों के, ये राजे महाराजे, जिन्होंने हमेशा देश का शोषण किया वह जनता के प्रतीक बन कर जनता के नेतृत्व करते हुए जनता के हित के लिये कार्य कर सकते हैं इस का मुझे विश्वास नहीं है। उन के शीशमहलों की, जिन में उन्होंने आराम किया है एक एक ईंट से बदनसीबों के खून की बदबू आ रही है। इन से कैसे कोई तवक्की की जा सकती है।

आज आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए आपसे यही विनती करता हूं कि जो टैक्स लगाए जाएं उनकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो पहाड़ हैं उनको काटा जाए और जो खाई हैं उनको पाटा जाए। हम जितने ज्यादा डाइरेक्ट टैक्सेज लगा सकते हैं लगाएं ताकि हमारे जीवन काल में नहीं तो हमारे बच्चों के जीवन काल में देश में समाजवाद आ सके। और जो इन-डाइरेक्ट टैक्सेज हैं जोकि देश की गरीब से गरीब जनता पर पड़ते हैं, जो जनता की हड्डी को चूर चूर करते हैं और जिनका दमन चक्र समाज के शोषित वर्ग पर ही चलता है, उसको कम से कम बढ़ावा दिया जाए। मेरी विनती है कि जो तरीका खर्च करने का है उसको भी बदलना चाहिए ताकि इस देश की जनता का एक-एक पैसा ठीक तरीके से खर्च हो।

[श्री मौर्य]

आज स्थिति यह है कि अगर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से कहा जाता है कि आप एक हजार रुपए तनखाह लो तो उनका कहना है कि एक हजार में गुजारा नहीं कर सकता। तब फिर मैं भी एक मजदूर का बालक होने के नाते कहता हूं कि जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री एक हजार रुपए में गुजारा नहीं कर सकते तब एक प्राइमरी स्कूल का टीचर, या कलों को चलाने वाला कारीगर या मजदूर और इस देश का शोषित किसान भी ४५ या ५० रुपए में गुजारा नहीं कर सकता। यह असमानता बरदाश्त नहीं की जा सकती। अगर इस दिशा में कुछ किया जाए तब तो हमको तवक्को हो सकती है कि हमारे लिए कुछ होगा नहीं तो हमको कोई उम्मीद नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमको लोकशाही के लिए खतरा नजर आता है।

मुझे एक बात डिफेंस के बारे में कहनी है लेकिन उसको कहना तो तभी ठीक होगा जबकि डिफेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हों। लेकिन मुझे लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। आज अवस्था यह है कि केवल पूंजीपति ही जीत कर इस सदन में आ सकते हैं, किसान और मजदूर जीत कर नहीं आ सकता। इस व्यवस्था को बदलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं प्राहिबिशन की नीति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि इस प्राहिबिशन को खत्म कर दिया जाए लेकिन शराब की कीमत बढ़ा दी जाए। इससे सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी। जो अभी नीति अपनायी जा रही है उससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। आज आप बम्बई में जाकर देखें कि वहां किस तरह से लोग नाली और गटर में शराब बनाते हैं और पीते हैं। लोग टिंक्चर जिंजर भी पी लेते हैं जिसके ज्यादा पीने से मौत हो सकती है और लोग मर भी जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्राहिबिशन को समाप्त कर दिया जाए और शराब का ज्यादा से ज्यादा दाम बढ़ा दिया जाए जिससे गरीब लोग उसको खरीद न सकें। ऐसा करने से लोगों को भी फायदा होगा और राज्य को भी फायदा होगा।

मेरा एक और सुझाव है कि एक्सपेंडीचर टैक्स जिसको कि वित्त मंत्री जी ने समाप्त किया है उसको समाप्त न किया जाए बल्कि उसको और बढ़ावा दिया जाए।

अन्त में मैं बाबा साहब अम्बेडकर की याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि इस देश की इकानमी सुधर सके। आज मेरी विनती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को सामने रखते हुए, कि देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि देश की आर्थिक अवस्था सुधर सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कुछ माननीय सदस्य आपके आसन पर बैठे रहने पर भी बोलने वाले के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। मैं समझता हूं कि सदन का इससे बड़ा अपमान होता है। आप चाहें तो कुछ कह सकते हैं लेकिन सदस्यों को [illegible] ले [illegible]को रोकने का प्रयत्न करना उचित नहीं हो सकता। और यदि ऐसा करना ठीक है तो इसकी छूट सबको होनी चाहिए।

†**श्री गजराज सिंह** (गुड़गांव) : तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा समाजवादी समाज की स्थापना का सिद्धान्त सभी ने स्वीकार किया है अब प्रश्न यह है कि इसकी पूर्ति के लिये धन कहां से

---

†मूल अंग्रेजी में

आये । मेरा विचार है कि विकास योजनाओं के लिये धन बड़े व्यापारियों और उच्च आय वाले व्यक्तियों से आना चाहिये । जन साधारण को उनमें स्वेच्छा से श्रमदान करना चाहिये । यह राष्ट्र का कार्यक्रम है ।

जितने भी ये बड़े व्यापारी तथा अन्य लोग हैं करापवंचन के मामले में बहुत तेज़ हैं । अतः आवश्यकता इस बात की है कि करापवंचन पर अधिक कड़ा नियंत्रण किया जाय और करापवंचन करने वालों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जायें और ऐसा करने से राजस्व बढ़ाया जा सकता है ।

हमारे देश में ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं अतः बजट में ग्रामीण जनता के सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिये । हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी योजनाओं के लाभ गांवों तक पहुंच सकें ताकि गांवों से नगरों को प्रव्रजन की प्रवृत्ति को रोका जा सके ।

गांवों में औषधालय तो हैं लेकिन वहां डाक्टर नहीं हैं और न वे वहां जाना चाहते हैं । हमें गांवों की स्थिति में सुधार करना चाहिये ताकि लोग गांवों में रहने के लिये आकर्षित हों ।

खंड विकास योजना का काम गांवों में अच्छी गति से नहीं हो रहा है । उनके सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां आती हैं जिन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के प्रयोजन के लिये बिजली की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय सदस्य कुछ अधिक समय लेंगे ?

†**श्री गजराज सिंह:** जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ९ मई १९६२/१९ वैशाख १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ८ मई, १९६२

१८ वैशाख, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४४५—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४९७	कोयले की बजाय मीथेन गैस का प्रयोग	१४४५-४६
४९८	डाक तथा तार विभाग में हिन्दी	१४४७-४८
४९९	सवारी डिब्बों का निर्यात	१४४८-४९
५००	केरल में तपेदिक के मरीज़	१४४९-५०
५०१	दिल्ली मास्टर प्लान	१४५०—५२
५०२	आस्ट्रेलिया के साथ किया गया गेहूं का सौदा	१४५२—५४
५०३	दक्षिण के राज्यों में सूखा	१४५४-५५
५०४	दक्षिण रेलवे पर विभागीय उपाहार-गृह	१४५५—५७
५०६	दिल्ली में पंचायतों के चुनाव	१४५८
५०७	रिहन्द बिजली परियोजना की फालतू बिजली	१४५८—६०
५०८	इम्फाल-कचार सड़क	१४६०-६१
५०९	अपरसिलेरू परियोजना का स्थान	१४६२
५१०	गन्ने की खेती का क्षेत्रफल	१४६२-६३
५११	दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा दो मंजिली बसों का आयात	१४६४-६५
५१२	त्रिपुरा में पशु महामारी	१४६५-६६
५१३	रासायनिक-उर्वरक	१४६६—६८
५१४	संयुक्त राष्ट्र का खाद्य तथा कृषि संगठन	१४६८-६९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
५	पठानकोट ऐक्सप्रस गाड़ी में एक स्त्री से बलात्कार	१४६९—७१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४७१—१५५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
५०५	अमरीका की चीनी का निर्यात	१४७१–७२
५१५	अजमेर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोके गये तार	१४७२
५१६	कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन	१४७२
५१७	दिल्ली में टेलीफोन	१४७३
५१८	जलढाका जल-विद्युत परियोजना	१४७३
५१९	आसाम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	१४७४
५२०	कृषि आयोग	१४७४
५२१	पशुधन	१४७४
५२२	श्रीसैलम और नागार्जुन सागर परियोजनायें	१४७५
५२३	भारत में मानसिक रोग	१४७५–७६
५२४	पेंसिल निर्माण के लिये लकड़ी का आयात	१४७६
५२५	जापान में प्रौद्योगिकीय सहायता	१४७६–७७
५२६	बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस में सोने के लिये डिब्बा	१४७७
५२७	हेलीकोप्टर डाक सेवा	१४७७
५२८	पानशेत और खड़कवासला बांध	१४७७–७८
५२९	राप्ती पुल	१४७७–७८
५३०	मालाबार तट पर मत्स्य पालन	१४७८–७९
५३१	जबलपुर इटारसी सेक्शन पर माल-डिब्बों की कमी	१४७९
५३२	चीनी का उत्पादन	१४७९
५३३	थाईलैण्ड को रेलूनों का सम्भरण	१४७९–८०
५३४	पोस्ट कार्ड बेचने की मशीन	१४८०
५३५	डीजल इंजनों का जल जाना	१४८०–८१
५३६	दिल्ली दूध योजना	१४८१
५३७	मलाया को चीनी के सम्भरण सम्बन्धी करार	१४८१
५३८	संयुक्त खेती सम्बन्धी अग्रिम योजनायें	१४८१–८२
५३९	रेलवे अस्पतालों में रोगियों से भोजन का पैसा लिया जाना	१४८२
५४०	नौवहन "टनभार"	१४८२–८३
५४१	उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी पर तटबन्ध	१४८३
५४२	चीनी का निर्यात	१४८३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी	
तारांकित प्रश्न संख्या	
५४३ खुम्भी की खेती	१४८४
५४४ अदन को चीनी का सम्भरण	१४८४-८५
५४५ प्रतिरक्षा विभाग को गेहूं की भूसी का सम्भरण	१४८५
५४६ स्वदेश लौटने वाले भारतीय मजदूर	१४८५
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७७३ जिला मदुरै में तीर्थयात्री कर	१४८६
७७४ बीना रेलवे प्रशिक्षण संस्था	१४८६
७७५ रूरकेला से भुवनेश्वर और पुरी से प्रयाग तक राजपथ	१४८६-८७
७७६ हावड़ा-बर्दवान विद्युतचालित रेलगाड़ी	१४८७
७७७ ललितपुर-बांदा बिजावर-करतल रेलवे	१४८७-८८
७७८ उद्यानकर्म के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को अनुदान	१४८८-८९
७७९ उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन रुजालय	१४८९
७८० पूर्व रेलवे के समुद्रगढ़ स्टेशन पर प्लेटफार्म	१४८९
७८१ मनमदुरै और विरुदुनगर के बीच छोटी लाइन	१४९०
७८२ राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४	१४९०
७८३ मोटर परिवहन के विकास के लिये राज्यों को रेलवेज से ऋण	१४९०-९१
७८४ कोर्टल्लम में पर्यटक सुविधायें	१४९१
७८५ तम्बाकू के मूल्य निर्धारित करना	१४९१-९२
७८६ पश्चिम बंगाल में बाढ़	१४९२
७८७ कूंच बिहार में नया मेडिकल कालिज	१४९२
७८८ भारतीय केन्द्रीय जूट समिति	१४९२-९३
७८९ डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१४९३
७९० टेलीग्राफिस्ट और टेलीग्राफमास्टर	१४९३
७९१ तार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता	१४९३-९४
७९२ डाक व तार निगम में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता	१४९४
७९३ तारों का भेजा जाना	१४९४
७९४ अपमिश्रण निरोधक उपाय	१४९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

७९५	भूमि का कृष्यकरण और वितरण .	१४९५
७९६	टेलीफोन डायरेक्टरी . . .	१४९५–९६
७९७	केरल के "कार्ड रेलवे लाइन" का निर्माण	१४९६
७९८	व्यास बांध परियोजना	१४९६
७९९	पठानकोट रेलवे स्टेशन .	१४९६
८००	यमुना पर पुल	१४९७
८०१	कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन पर गोदाम और यात्री शैड . .	१४९७
८०२	देश में प्राकृतिक-चिकित्सा केन्द्र .	१४९७–९८
८०३	केरल के समुद्र द्वारा भूमि का कटाव .	१४९८
८०४	समुद्र द्वारा भूमि का कटाव .	१४९८
८०५	फेफड़ों का केन्सर .	१४९९
८०६	भारतीय नाविक . . .	१४९९
८०७	कैन्सर के कारणों के बारे में रिपोर्ट .	१४९९–१५००
८०८	दिल्ली में चिड़ियाघर	१५००—०२
८०९	ग्राम सभायें .	१५०२–०३
८१०	दिल्ली में भूमि विकास	१५०३
८११	रेलवे कर्मचारियों की आम हड़ताल	१५०३
८१२	केरल में शोलयार परियोजना	१५०३–०४
८१३	भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	१५०४
८१४	केरल में पीने के पानी का सम्भरण	१५०४–०५
८१५	इन्द्रावती और गोदावरी नदियों के संगम पर बांध	१५०५
८१६	पेट के व्रण का इलाज	१५०५
८१७	तिपटूर रेलवे स्टेशन पर पुल .	१५०५–०६
८१८	डीज़ल इंजनों का दक्षिण और पश्चिम भारत में भेजा जाना . .	१५०६
८१९	मैसूर में बाढ़ नियन्त्रण . .	१५०६
८२०	त्रिपुरा के कृषकों के लिये काम . .	१५०७
८२१	आसाम में बाढ़ नियन्त्रण . . .	१५०७
८२२	पर्यटन के महानिदेशक द्वारा विदेश यात्रायें .	१५०७—०९
८२३	संयुक्त स्टीमर कम्पनियां	१५०९–१०

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखत उत्तर--जारी	
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
८२४	रेलवे कालोनियों में रेलवे संस्थान और वाचनालय	१५१०
८२५	बीकानेर नगर में दुग्धशाला .	१५१०-११
८२६	बेलघरिया और सोदपुर रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल .	१५११
८२७	पश्चिम-बंगाल में पीने के पानी का सम्भरण . .	१५११
८२८	बीकानेर डिवीजन में नये स्टेशनों के लिये इमारतें .	१५११-१२
८२९	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर	१५१२
८३०	मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म .	१५१२
८३१	रेलवे के लिये कोयला खरीदने की नीति	१५१२-१३
८३२	मनीपुर को दुग्ध चूर्ण का आवंटन	१५१३
८३३	मनीपुर राज्य परिवहन . .	१५१३-१४
८३४	विजयवाड़ा और मछेरला के बीच एक्सप्रेस गाड़ी .	१५१४
८३५	तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर . . .	१५१४-१५
८३६	तीसरी योजना में मध्य प्रदेश के लिये नई रेलवे लाइन . .	१५१५
८३७	त्रिपुरा में मोटर दुर्घटना . . .	१५१५
८३८	त्रिपुरा में धान के लिये भूमि	१५१६
८३९	त्रिपुरा-अगरतला मालवाही विमान सेवा . . .	१५१६
८४०	बालासौर से नीलगिरी तक रेलवे लाइन . . .	१५१६-१७
८४१	दिल्ली में तकावी	१५१७
८४२	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना	१५१७-१८
८४३	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना	१५१८
८४४	बिनौले बोना . . .	१५१८
८४५	पाल वाले जहाजों का विनाश . . .	१५१९
८४६	नागार्जुनसागर परियोजना	१५१९
८४७	चेचक और छोटी चेचक	१५२०
८४८	अंगोल से हैदराबाद तक नई रेलवे लाइन . .	१५२०-२१
८४९	गुण्टुर से नरसरावपेट तक (दक्षिण रेलवे) बड़ी लाइन . .	५१२१
८५०	ओलवक्कोट जंक्शन पर शयन कक्ष .	५१२१
८५१	पश्चिम रेलवे में रेलवे की भूमि पर मोदी मिल .	१५२१-२२
८५२	दक्षिण रेलवे पर चक्रधरपुर में ऊपरी पुल .	१५२२
८५३	चक्रधरपुर में काम करने वाले कुली व मजदूर .	१५२२-२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

८५४	रेलों में स्थान रक्षित कराने की प्रक्रिया .	१५२३
८५५	वन्य-पशुओं का परिरक्षण	१५२३–२४
८५६	रेलों में उच्च श्रेणी के पद	१५२४
८५७	मनीपुर में सन्तरे और अनानास	१५२४–२५
८५८	रेल कारों का निर्माण . .	१५२५
८५९	वेजथरा रोड रेलवे स्टेशन पर टिन शेड	१५२५
८६०	माल यातायात के लिये रेलवे में टेलीविज़न .	१५२६
८६२	हलवाड से मेहसाना तक सीधी गाड़ी	१५२६
८६३	बीकानेर में टेलीफोन के कनेक्शन . . .	१५२६–२७
८६४	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति .	१५२७
८६५	राष्ट्रीय राजपथ के लिये भूमि का अर्जन . .	१५२७
८६६	केरल मण्डल के डाक व तार कर्मचारियों के लिये निवास स्थान	१५२७–२८
८६७	कोजीरोड का बड़ा डाकघर . .	१५२८–२९
८६८	कासरगोड के समीप चन्द्रगिरि नदी के ऊपर रेल का पुल	१५२९
८६९	टेपिग्रोका की खेती और निर्यात . .	१५२९–३०
८७०	४३ अप/४४ डाउन नार्थ-बंगाल एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन . . .	१५३०
८७१	मद्रास राज्य के लिये उर्वरक .	१५३०
८७२	मद्रास (एगमोर) ताम्बरम-विल्लूपुरम् सैक्शन का विद्युतीकरण .	१५३०–३१
८७३	बंगलौर-सैलम मीटर लाइन .	१५३१
८७४	नित्रेली और सैलम के बीच रेलवे लाइन	१५३२
८७५	बिहार में तपेदिक और कुष्ठ के रोगी .	१५३२–३३
८७६	अलवर को कोसी/भरतपुर के साथ मिलाने वाली बड़ी लाइन	१५३३
८७७	बिहार-बख्तियारपुर लाइट रेलवे के अपदस्थ कर्मचारी .	१५३३
८७८	गुलमर्ग में रज्जुपथ . . .	१५३४
८८०	तुंगभद्रा जलाशय गांवों के पास नलकूप .	१५३४–३५
८८१	कृष्णा नदी घाटी परियोजना . .	१५३५
८८३	रेलवे वर्कशापों द्वारा रद्दी लोहे का उपयोग .	१५३६
८८४	गुन्टकल-हौजपेट बड़ी रेलवे लाइन	१५३६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८८६	आन्ध्र देश के गांवों में बिजली लगाना	१५३६–३७
८८७	जम्मू और कश्मीर राज्य में सामुदायिक विकास खण्ड	१५३७
८८८	अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा नेता	१५३७–३८
८८९	परिवार नियोजन रुजालय .	१५३८–३९
८९०	केन्द्रीय स्वास्थ्य पदाली . . .	१५४०
८९१	१८ वर्ष से कम आयु के रेलवे कर्मचारियों की भरती	१५४०
८९२	दिल्ली में परिवहन सहकारी समितियां .	१५४०
८९३	कोटा रेलवे स्टेशन यार्ड में मिशनरी स्कूल	१५४१
८९४	तम्बाकू पर लाइसेंस फीस	१५४१
८९५	मीटरगेज लाइन को बगहा तक बढ़ाना .	१५४१–४२
८९६	दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना	१५४२
८९७	दक्षिण पूर्व रेलवे पर राज खारसवान में ऊपरी पुल	१५४२
८९८	डाक व तार विभाग का मोटर सर्विस सेक्शन, दिल्ली	१५४२–४३
८९९	गोहाटी रेलवे स्टेशन	१५४३
९००	पानी भर जाना	१५४३
९०१	भोपाल में टेलीफोन के कनेक्शन	१५४४
९०२	कोयला परियोजना . .	१५४४
९०३	ट्रंक कालों के सम्बन्ध में शिकायत . . .	१५४४–४५
९०४	हरदोई स्टेशन के समीप सिपाही की मृत्यु . .	१५४५
९०५	तूना मछलियों सम्बन्धी अनुसन्धान . .	१५४५
९०६	कम्पाउण्डरों और ड्रेसरों के लिये सेलेक्शन ग्रेड .	१५४५–४६
९०७	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारी .	१५४६
९०८	कपास की कम उपज .	१५४७
९०९	मशीनी फार्मों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति . .	१५४७
९१०	दिल्ली दूध योजना . .	१५४७–४८
९१२	दिल्ली के गांवों में क्षयरोगियों के लिये चलते फिरते चिकित्सालय	१५४८
९१३	पंजाब में गांवों में पानी पहुंचाने की योजनायें	१५४८
९१४	रूपड़-नंगल बांध सेक्शन में सुविधाओं की व्यवस्था .	१५४८–४९
९१५	नगल बांध और भानुपली के बीच हाल्ट स्टेशन . .	१५४९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६१६ किराये की इमारतों में डाक-तार घर . १५४६
६१७ पंजाब में डाक-तार विभाग की इमारतें . १५४६–५०
६१८ कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र १५५०
६१६ बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन को फिर से बनाना . १५५१
६२० कानपुर-बालामऊ सेक्शन पर कालीमिट्टी स्टेशन का निर्माण . १५५१
६२१ तार की सुविधायें . १५५१
६२२ उत्तर प्रदेश में पलियाकलान में चीनी कारखाना १५५२
६२३ फरक्का बांध . . १५५२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १५५३–५४

श्री हेम बरुआ ने नागालैण्ड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान के गिरने की ओर प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५५४–५५

(१) इण्डियन टेलीग्राफ अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मार्च, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४६२ में प्रकाशित इण्डियन टेली-ग्राफ (दूसरा संशोधन) नियम, १६६१।

(दो) दिनांक ४ नवम्बर, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५१ में प्रकाशित इण्डियन टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम १६६१।

(तीन) दिनांक २३ दिसम्बर, १६६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०२० में प्रकाशित इण्डियन टेलीग्राफ (बारहवां संशोधन) नियम, १६६१।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १६५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २८ अप्रैल, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५६२।

विषय **पृष्ठ**

(दो) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३।

(३) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के लेखे का वार्षिक विवरण और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

सामान्य आयव्ययक-सामान्य चर्चा १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक, १९६२-६३ पर सामान्य चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, ९ मई, १९६२/१९ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि :

सामान्य आय व्ययक, १९६२-६३ पर सामान्य चर्चा।

GMGIPND—LSIII—664(Ai)LSD—10-7-62—150